लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खंड 39, 1965/1886 (शक)

Volume, XXXIX, 1965/1886 (Saka)

[3 से 16 मार्च, 1965/12 से 25 फाल्गुन, 1886 (शक)]

[March 3 to 16, 1965/Phalguna 12 to 25, 1886 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)

Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं]

[Vol. XXXIX contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची

अंक 17 गुरुवार, 11 मार्च, 1965 / 20 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
380	बिजली के मीटरों के लिये नक़द जमानत	1515--18
381	औद्योगिक मज़दूरों के लिये आवास	1518--21
382	शांतिवन दिल्ली	1521--22
383	यमुना के पानी को दूषित होने से रोकना .	1523--26
384	चौथी योजना में बेरोज़गारी . .	1526--29
385	विदेशी पूंजी .	1529--34
386	चतुर्थ योजना	1534--36

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या		
387	परिचर्या (नर्सिंग) के लिये केन्द्रीय पदावली . . .	1536–37
388	संयुक्त अरब गणराज्य तथा जोर्डन में सिचाई संबंधी भारतीय दल का प्रतिवेदन .	1537
389	कर से बचना	1537–38
390	चीन में बनी वस्तुओं का भारत में चोरी-छिपे लाया जाना	1538–39
391	कलकत्ता में एक व्यापारी के मकान की तलाशी	1539
392	ग्रामीण विकास के लिये श्री चेस्टर बाउल्स की योजना .	1539
393	भारत का विदेशी दायित्व	1540
394	योजना आयोग .	1540
395	विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम	1541
396	बर्ड एण्ड कम्पनी	1541–42
397	पूर्वी उत्तर प्रदेश की सिंचाई और विद्युत सम्बन्धी समस्याएं	1542–43
398	बम्बई तथा केरल में फर्मों पर छापे	1543
399	आयुर्वेदिक कालिज .	1543–44
400	गर्भपात को वैध बनाना . .	1544
401	सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज . .	1544

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 17 *Thursday, March* 11, 1965/*Phalguna* 20, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS —

Starred Q. Nos.	*Subject*	PAGES
380	Cash Security for Electric Meters	1515—18
381	Houses for Industrial Workers	1518—21
382	Shantivana, Delhi . . .	1521–22
383	Prevention of Pollution of Jamuna Water	1523—26
384	Unemployment during Fourth Plan .	1526—29
385	Foreign Capital . .	1529—34
386	Fourth Plan	1534—36

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Q. Nos.		
387	Central Cadre of Nursing	1536–37
388	Report of Indian Team Re : Irrigation in U.A.R. and Jordan	1537
389	Tax Evasion	1537–38
390	Smuggling of Chinese Goods to India . .	1538–39
391	Search of a Businessman's House in Calcutta . .	1539
392	Mr. Chester Bowles Scheme for Rural Development	1539
393	India's Foreign Liabilities . . .	1540
394	Planning Commission	1540
395	School Health Programme	1541
396	Bird & Co	1541–42
397	Irrigation and Power problems of Eastern U.P.	1542–43
398	Raids on Firms in Bombay and Kerala .	1543
399	Ayurvedic Colleges	1543–44
400	Legalisation of Aboration	1544
401	Interest on G.P.F. Accumulations	1544

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
969	विशेष ऋण-नियंत्रण	1545
970	सिंचाई तथा जल निकाय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग	1546
971	मलाबार में बिजली की दर	1546–47
972	भारत सेवक समाज	1547
973	बाढ़ संरक्षण	1547
974	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	1547–48
975	राष्ट्रीय परिषद् की समिति की बैठक	1548–50
976	स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन	1550
977	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गयी सहायता	1550
978	स्थानीय योजनाओं की क्रियान्विति सम्बन्धी प्रशिक्षण	1551
979	पालम, नई दिल्ली पर सोने का तस्कर व्यापार	1551
980	तस्करों की गिरफ्तारी	1551–52
981	बिजली की कीमत	1552
982	भारत-पाकिस्तान बाढ़ नियंत्रण योजना	1552–53
983	ग्रांड होटल, शिमला	1553
984	सोने का निजी व्यापार	1553–54
985	गांव का विद्युतीकरण	1554
986	नई दिल्ली में पुराने सरकारी क्वार्टर	1554–55
987	श्री बी० के० दत्त का इलाज	1555
988	सुनार	1555–56
989	अमरोहा में फिल्म निर्देशक के मकान की तलाशी	1556
990	उपभोक्ता वस्तुयें	1556–57
991	दिल्ली में चूहे तथा ऐसे जीव जन्तु	1557–58
992	कोटा में आय-कर कार्यालय	1558
993	दिल्ली में धोबियों के लिये आवास	1559
994	दिल्ली में गन्दी बस्ती हटाने की योजना	1559
995	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टर	1560
996	मध्य प्रदेश में आवास कार्यक्रम	1560
997	कलकत्ता बन्दरगाह पर छिद्रण उपकरण की निकासी	1560–61
998	दिल्ली में फिलोसोफिकल हाल के लिये भूमि	1561
999	गोल मार्केट इलाका, नई दिल्ली	1561–62
1000	घटिया थर्मामीटर	1562
1001	विश्व बैंक के कर्मचारियों की यात्रा	1562
1002	राजस्थान में परिवार नियोजन	1562–63
1003	पंजाब से दिल्ली के लिये पानी	1563
1004	चौथी योजना के लिये रूस से सहायता	1563–64
1005	कर-अपवंचक	1564
1006	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1564
1007	छोटे नगरों की समस्यायें	1564–65

Unstarred Q. Nos.	*Subject*	PAGES
969	Selective Credit Controls	1545
970	International Commission on Irrigation and Drainage	1546
971	Electricity rates in Malabar	1546-47
972	Bharat Sewak Samaj	1547
973	Flood Protection	1547
974	All India Institute of Medical Sciences	1547-48
975	N.D.C.'s Committee Meeting	1548--50
976	Post Graduate Medical studies	1550
977	Aid sought by U.P. Government	1550
978	Training in Execution of Local Schemes	1551
979	Gold Smuggling at Palam, New Delhi	1551
980	Arrest of Smugglers	1551-52
981	Price of Electricity	1552
982	Indo-Pakistan Flood Control Scheme	1552-53
983	Grand Hotel, Simla	1553
984	Private Trade in Gold	1553-54
985	Rural Electrification	1554
986	Old Government Quarters in New Delhi	1554-55
987	Treatment of Shri B. K. Dutt	1555
988	Goldsmiths	1555-56
989	Search of Film Director's House at Amroha	1556
990	Consumer Goods	1556-57
991	Rats and Mice in Delhi	1557-58
992	I.T. Office, Kotah	1558
993	Housing for Delhi Washermen	1559
994	Delhi Slum Clearance Scheme	1559
995	Quarters in Ramkrishnapuram, New Delhi	1560
996	Housing Programme in Madhya Pradesh	1560
997	Clearance of Drilling Equipment at Calcutta Port	1560-61
998	Land for Philosophical Hall in Delhi	1561
999	Gole Market Area, New Delhi	1561-62
1000	Sub-standard Thermometers	1562
1001	Visit by World Bank Officials	1562
1002	Family Planning in Rajasthan	1562-63
1003	Water Supply to Delhi from Punjab	1563
1004	Aid from Russia for Fourth Plan	1563-64
1005	Tax Evaders	1564
1006	Public Sector Undertaking	1564
1007	Problem of Small Towns	1564-65

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1008	अफीम का तस्कर व्यापार	1565
1009	चौथी योजना	1565–66
1010	उड़ीसा में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें	1566
1011	विदेशी व्यापार संस्थानों को दी गई रायल्टी	1566
1012	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1566–67
1013	प्रबन्ध अभिकरण	1567
1014	छात्रों को विदेशी मुद्रा	1567
1015	समवायों में कदाचार	1567–68
1016	औद्योगिक उत्पादों की बिक्री पर कमीशन	1568
1017	तुलनात्मक उत्पादन लागत का अध्ययन	1568–69
1018	"आस्टरमिल्क" में जीवित कीड़ों का पाया जाना	1569
1019	विदेशों में प्रदर्शनार्थ भेजे जाने वाले चलचित्रों की जांच के लिये बोर्ड	1569–70
1020	भूमि सुधार	1570
1021	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि	1570–71
1022	उद्योगों के लिये विद्युत की दर	1571
1023	मध्य प्रदेश की नई पूंजीगत परियोजना	1571
1024	मद्रास में आय-कर सम्बन्धी मुकदमे	1571
1026	गाजीपुर में अफीम का कारखाना	1571–72
1027	सिंचाई परियोजनायें	1572
1028	यूगोस्लाविया से सहायता	1572
1029	आसाम में ग्रामों के लिये पानी की व्यवस्था	1573
1030	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा आयोजित परिसंवाद	1574
1031	साइन्स फीस	1574
1032	चीनी का उत्पादन	1574–75
1033	गाजीपुर अफीम कारखाने के कर्मचारी	1575
1034	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पानी बांटना	1575–76
1035	केरल में सिंचाई	1576
1036	राजस्थान में सिंचाई संसाधन	1576–77
1037	भवन-फ्लाटों के पट्टे	1577
1038	जल-संसाधनों का उपयोग	1578
1039	केरल में वेतन आयोग	1578
1040	केरल में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	1578–79
1041	सामान्य बीमा के लिये आचरण संहिता	1579

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 1579–80

मनीपुर के एक सब-डिवीजन में की गई आपात की घोषणा और सेना बुलाये जाने की आवश्यकता--

श्री मधु लिमये 1579–80

श्री ल० ना० मिश्र 1580

Starred Question Nos,	SUBJECT	PAGES
1008	Opium Smuggling	1565
1009	Fourth Plan	1565–66
1010	Rural Industrial Projects in Orissa	1566
1011	Payment of Royalty of Foreign Concerns	1566
1012	Primary Health Centres	1566–67
1013	Managing Agencies	1567
1014	Foreign Exchange to Students	1567
1015	Malpractices in Companies	1567–68
1016	Commission on Sale of Industrial Producta	1568
1017	Study of Comparative Production Cost	1568–69
1018	Live Worms in Ostermilk	1569
1019	Boards for Screening Films for Export	1569–70
1020	Land Reforms	1570
1021	International Monetary Fund	1570–71
1022	Power rates for Industries	1571
1023	New Capital Project of Madhya Pradesh	1571
1024	I.T. Prosecutions in Madras	1571
1026	Opium Factory, Ghazipur	1571–72
1027	Irrigation projects	1572
1028	Aid from Yugoslavia	1572
1029	Rural Water Supply in Assam	1573
1030	Syposium Organised by National Buildings Organisation	1574
1031	Science Fee	1574
1032	Sugar Production	1574–75
1033	Employees of Ghazipur Opium Factory	1575
1034	Sharing of West Flowing Rivers	1575–76
1035	Irrigation in Kerala	1576
1036	Irrigation Potential in Rajasthan	1576–77
1037	Lease of Building Plots	1577
1038	Utilisation of Water Resources	1578
1039	Pay Commission in Kerala	1578
1040	D.A. To Employees of Local Bodies in Kerala	1578–79
1041	Code of Conduct for General Insurance	1579
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance		1579–80
Declaration of emergency in Manipur sub-division and necessity for calling of troops		
	Shri Madhu Limaye	1579–80
	Shri L.N. Mishra	1580

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	1580–81
राज्य सभा से सन्देश	1581
औचित्य -प्रश्न के बारे में	1582
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1965–66	1582––98
डा० मा० श्री अणे	1582–83
श्रीमती लक्ष्मी बाई	1583–84
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	1584–85
श्री अ० प्र० शर्मा	1585–86
श्री ओंकार लाल बेरवा	1586
श्री दी० चं० शर्मा	1587
श्रीमती सहोदराबाई राय	1587–88
श्री चं० का० भट्टाचार्य	1588–89
श्री अब्दुल गनी गोनी	1589–90
श्री बसुमतारी	1590–91
श्री दलजीत सिंह	1591–92
श्रीमती सावित्री निगम	1592–93
श्रीमती सुभद्रा जोशी	1593
श्री डाकलीवाल	1593
श्री दे० जो० नायक	1594
श्री वीरप्पा	1594
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	1594–95
डा० राम सुभग सिंह	1595––98
चीन समर्थक साम्यवादियों की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों पर गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	1598–1612
श्री प्र० के० देव	1600––02
श्री ही० ना० मुकर्जी	1602–03
श्री विद्याचरण शुक्ल	1603–04
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	1604–05
श्री मधु लिमये	1605–06
श्री पें० वेंकटासुब्बया	1606–07
श्री नि० चं० चटर्जी	1607–08
श्री केप्पन	1608–09
श्री हरिविष्णु कामत	1609
श्री दीनेन भट्टाचार्य	1609–10
श्री राम सहाय पाण्डेय	1610–11
श्री हुकम चन्द कछवाय	1611
श्री सरजू पाण्डेय	1611–12
श्री नन्दा	1621

Subject	*Pages*
Papers laid on the Table	1580–81
Messages from Rajya Sabha	1581
Re : Point of Property	1582
Demands for Grants (Railways), 1965-66	1582–98
Dr. M. S. Aney	1582–83
Shrimati Laxmi Bai	1583–84
Shri Harish Chandra Mathur	1584–85
Shri A. P. Sharma	1585–86
Shri Onkar Lal Berwa	1586
Shri D. C. Sharma	1587
Shrimati Sahodra Bai Rai	1587–88
Shri C. K. Bhattacharyya	1588–89
Shri Abdul Ghani Goni	1589–90
Shri Basumatari	1590–91
Shri Daljit Singh	1591–92
Shrimati Savitri Nigam	1592–93
Shrimati Subhadra Joshi	1593
Shri Bakliwal	1593
Shri D. J. Naik	1594
Shri Veerappa	1594–95
Shrimati Lakshmikanthamma	1595–98
Dr. Ram Subhag Singh	1598
Motion re : Home Minister's statement on anti-national activities of Pro-Peking Communists.	1598—1612
Shri P. K. Deo	1600–02
Shri H. N. Mukerjee	1602–03
Shri Vidhya Charan Shukla	1603–04
Shri Prakash Vir Shastri	1604–05
Shri Madhu Limaye	1605–06
Shri P. Venkatasubbiah	1606–07
Shri N. C. Chatterjee	1607–08
Shri Kappen	1608–09
Shri Hari Vishnu Kamath	1609
Shri Dinen Bhattacharya	1609–10
Shri R. S. Pandey	1610–11
Shri Hukam Chand Kachhavaiya	1611
Shri Sarjoo Pandey	1611–12
Shri Nanda	1612

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 11 मार्च, 1965/20 फाल्गुन, 1886 (शक)

Thursday, March 11, 1965/Phalguna 11, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Cash Security for Electric Meters

†

*380. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Omkar Singh :
Shri S. L. Verma :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Hem Raj :
Shri Ramanand Shastri :
Shri Mohammad Elias :
Shri Gauri Shankar Kakkar :
Shri Utiya :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. L. Barupal :
Shri Krishnapal Singh :
Shri J. B. Singh :
Shri Yashpal Singh :
Shri Daji :
Shri Sinhasan Singh :
Shri Jedhe :
Shri U. M. Trivedi :

Shri Bade :
Shri Mate :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :
Shri Sheo Narain :
Shri D. D. Mantri :
Shri D. S. Patil :
Shri P. H. Bheel :
Shri Sham Lal Sharaf. :
Shri Y. D. Singh
Shri Lahri Singh :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government employees have been served with notices to deposit cash security for thier electric meters and the Government security therefor has been cancelled;

(b) if so, the total number of Government employees affected;

(c) the reasons for issuing such notices; and

(d) whether it was stated in the notices that the meter connections would be cut off if cash security was not deposited by the 24th February, 1965.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Shyamdhar Mishra) : (a) to (d) A statement giving the required information is placed on the Table of the House.

Statement

(a) The Delhi Electric Supply Undertaking have asked the gazetted officers residing in government quarters in whose case deduction of the electricity charges can not be made at source, to deposit cash security for thier light and power connections which were given before 26th November, 1964. In respect of connections after 26th November, 1964, such connections are being given to gazetted officers in government quarters only after they deposit cash security in the prescribed scale. This does not apply to the gazetted officers residing in N.D.M.C. and cantonment areas.

(b) The total number of officers affected is about 4,500.

(c) In the absence of cash security, it had been noticed by D.E.S.U. that number of officers, on vacating the quarters either on transfer or shifting to another, did not ask the undertaking to disconnect the electric supply. Many of them left the quarters without finally clearing the dues with the result that the undertaking was put to great difficulty in recovering them. Moreover, when an officer occupied a quarter vacated by another officer, the former would keep on utilising the power from the connection registered in the name of the latter and disputes arose in regard to payment of the bills, which, sometimes, lingered on for a pretty long time.

(d) The power supply connections were liable to be disconnected 15 days after serving the notice. But no disconnection has been effected so far.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that electricity charges are charged at different rates in different areas of Delhi and there are different rules applying to different areas ?

Shri Shyam Dhar Mishra : In Delhi some area is of D.E.S.U. and some area of N.D.M.C. It is correct that charges are different in both the

areas. As D.E.S.U. are facing some difficulties, so they made such rules and as N.D.M.C. have no difficulties, their way of charging is different. If they had some difficulty, they would also make such rules.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Due to non-protection of meters installed in Delhi, most of them are stolen. Have you received any report about the number of meters stolen during a year.

Shri Shyamdhar Mishra : Theft is not a special matter for Delhi. Everywhere theft is there. About the number of thefts, I require notice.

Shri A. S. Saigal : How much time will be taken in implementing the new scheme so as to symmeterise in rates ?

Shri Shyamdhar Mishra : There is no question of rates here. This is about meters. Gazetted officers in the D.E.S.U. area were asked to deposit cash security for government security.

Ms. Speaker : This is stated in the statement.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : For what special reasons cash security is being demanded for government security ?

Mr. Speaker : This all is mentioned in the statement. Probably you have not seen the statement.

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the number of connections disconnected so far in cases where the cash security was demanded upto the 25th February, 1965 as the same was not deposited ?

Shri Shyamdhar Mishra : No connection has so far been disconnected. Only notice has been served.

Shri Onkar Lal Berwa : Will the last date for depositing cash security be extended ?

Shri Shyamdhar Mishra : There is no question of extending the last date. When again the advice is served, it will take effect.

Shri Y. S. Chaudhary : May I know the reason of not getting cash security from government employees before taking the decision ?

Mr. Speaker : This is given in the statement.

Shri Y. S. Chaudhary : Why it was not recovered before ?

Mr. Speaker : This is given in the statement as to why it is not recovered.

Shri Y. S. Chaudhary : We have not received the statement.

Mr. Speaker : I would enquire to why could not get. Those who asked for it, must have got.

Shri Yashpal Singh : Still there are lakhs of consumers who have not to give personal security. What was the loss to the government to exempt these government employees also from giving cash security.

Mr. Speaker : That is given in the statement.

Shri Yashpal Singh : Details are not there.

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम वाले क्षेत्र में 2,75,000 उपभोक्ता हैं और उनमें से राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों से, नकद जमानत मांगी जा रही है, जो सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 4500 है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार इस बारे में किसी मध्य-मार्ग के बारे में विचार कर रही हैं जिससे निम्नतम वेतन पाने वाला सरकारी कर्मचारी भी बाजदफा अधिक राशि का भुगतान कर सके ?

डा० कु० ल० राव : अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों से नकद जमानत नहीं ली जाती। उनकी गारंटी सरकारी विभाग द्वारा दी जाती है।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि उस श्रेणी के लोगों से नकद जमानत नहीं ली जाती है।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं यह जानना चाहती थी कि क्या बकाया राशि को, जोकि बड़ी रकम होती है, किस्तों में देने की अनुमति दी जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : बकाया को रहने दीजिए। वह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

औद्योगिक मजदूरों के लिए आवास

+

*381. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा विधान पेश करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिससे नियोजकों द्वारा औद्योगिक मजदूरों के लिये मकान बनाना अनिवार्य किया जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) औद्योगिक मज़दूरों के लिए मालिकों को मकान बनाना अनिवार्य करने के प्रश्न पर चंडीगढ़ में 29, 30 दिसम्बर 1964 को आवास मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन ने यह सिफारिशें की थीं कि फिलहाल सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने, आय-कर में छूट देने, लागत मूल्य पर भूमि आवंटित करने और मज़दूरों के मकानों के लिए नियंत्रित भवन सामग्री देने की तरह की अतिरिक्त सुविधायें, अधिक संख्या में मज़दूरों के लिए मकान बनाने को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से औद्योगिक मालिकों को दी जायें। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की थी कि यदि इन अतिरिक्त सुविधाओं के बावजूद मालिकों की प्रतिक्रिया असंतोषजनक बनी रही तो मालिकों को अपने मज़दूरों के कुछ प्रतिशत के लिए मकान की व्यवस्था अनिवार्य करने का समुचित विधान बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार करे। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार के विभिन्न विभागों ने इन सुझावों से लाभ उठाया है और सभी सरकारी कर्मचारियों को मकान देने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाई हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं इस प्रश्न को समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने मालिक की हैसियत से यह सुझाव क्रियान्वित किया है और अपने कर्मचारियों को मकान दिए हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह प्रश्न केवल गैर-सरकारी मालिकों के बारे में है । जहां तक सरकारी क्षेत्र में सरकारी निर्माण का सम्बन्ध है, इस योजना में एक निश्चित सीमा तक मकानों का निर्माण किए जाने की व्यवस्था है । जहां तक गैर-सरकारी मालिकों का सम्बन्ध है, उनसे हमें अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के बारे में उत्साहजनक उत्तर नहीं मिल रहा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया गया है । सरकारी क्षेत्र में कई उद्योग हैं । क्या मंत्री महोदय ने इस ओर ध्यान दिया है कि इन सरकारी उपक्रमों में नियोजित कर्मचारियों को मकान की और अन्य सुविधायें दी जाएं जो कि उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए सिफारिश की है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां तक मेरे मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है, मैंने इस पर ध्यान दिया है कि हमें उनके लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए ।

श्री ओझा : क्या सरकार के पास जानकारी है कि कितने प्रतिशत कर्मचारियों को मकान मिले हुए हैं ? निर्माण और आवास मंत्रालय और कितने प्रतिशत कर्मचारियों को मकान दे सकेगा ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह प्रतिशतता बहुत अधिक नहीं है, कुछ कम ही है । इसी कारण हमने इस प्रश्न को लिया है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए अधिक मकान बनाए जाएं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : मंत्री महोदय ने बताया कि यदि उन्हें प्रगति संतोषजनक नहीं लगी तो वह यह देखेंगे कि इसको संतोषजनक बनाने के लिए कदम उठाए जाएं । अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं इस बारे में की गई प्रगति के बारे में गैर-सरकारी मालिकों से किस प्रकार रिपोर्ट प्राप्त की जाती है ? उनकी आखिरी रिपोर्ट क्या है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : नवीनतम स्थिति वैसी ही है । पहले हम 50 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत सहायता दे रहे थे, अब हमारा इरादा 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत सहायता देने का है ताकि उद्योगपति और उद्योग पर कम से कम भार पड़े । यदि इस प्रोत्साहन के बावजूद भी उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा तो फिर इस मामले पर विचार किया जाएगा । इसमें वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और मेरा मंत्रालय सम्बंधित हैं । यह एक बड़ा प्रश्न है जिस पर विचार करना होगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मंत्री महोदय के इस स्पष्ट वक्तव्य को देखते हुए कि दो-तिहाई से अधिक लोग कुटियाओं और छप्परों में रहते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गैर-सरकारी उद्योगपतियों ने उन कठिनाइयों के बारे में बताया है जो, यदि उन्हें कुछ सुविधाएं न दी जाएं, उनको होती हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं समझता हूं कि मेरा वक्तव्य बड़ा स्पष्ट था । यह अस्पष्ट नहीं है । गैर-सरकारी मालिकों की स्थिति का हम सबको पता है । यदि वे कुछ रुपया बचाते हैं, तो वह उद्योग का विकास करने में लगा देते हैं, वे इस धन को मकान बनाने पर नहीं लगाना चाहते ।

Shri Bibhuti Mishra : The Sugar Mill owners who have been given loan and subsidy by the government to construction of houses for their workers, have not so far constructed any house. Would the government enquire into that ?

Shri Mehr Chand Khanna : I am not aware of the second thing but so far as the first is concerned, I have already said it is true that their response has not so far been satisfactory.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether there were some representatives of employers also in this conference and if so, the suggestions given by them and whether the government are of the view that workers, who have got cretain amount in thier project fund, should be given loans to construct houses ?

Shri Mehr Chand Khanna : So far as this conference is concerned, we invited the representatives of industrialists and two of them attended the conference. They put their difficulties before us, as far as the State and Central Governments are concerned, we want that maximum number of houses should be constructed for them.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अक्सर गैर-सरकारी क्षेत्र के मालिक यह तर्क देते हैं कि यदि वे मकान बनाना चाहते हैं तो उनको, विशेषत: उन क्षेत्रों में जहां मकान बनाये गये हों, भूमि नहीं मिलती । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आवास मंत्रियों के सम्मेलन में इस बारे में कोई निर्णय किया गया कि जो मालिक मकान बनाना चाहते हैं, उन्हें केन्द्र अथवा राज्य सरकारें अर्जन आदि करके आवश्यक भूमि दें ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : हमने इस प्रश्न पर विचार किया है और इस प्रयोजन के लिए हमने योजना आयोग के श्री ठक्कर की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है । हम इस समस्या को दो ढंग से सुलझाना चाहते हैं । यदि भूमि प्राप्त करने में कठिनाई हो तो हम प्रक्रिया को सरल बनाएंगे ताकि औद्योगिक क्षेत्र में मकान निर्माण के लिए भूमि मिल सके, दूसरे यह समिति इस बात पर भी विचार करेगी कि जहां कुछ परिस्थितियों में हमें यह बताया गया है कि उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में भूमि अर्जित की गयी जिसका बड़ा भाग अब भी बिना इस्तेमाल का पड़ा हो, क्या उस भूमि पर औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान नहीं बनाए जा सकते ।

Shri Bhagwat Jha Azad : The Hon. Minister just now said that housing facilities are not adequate. May I know whether the amount of loan and subsidy, though limited, advanced by the government were utilised properly ?

Shri Mehr Chand Khanna : That I also said that they have not constructed the required number of houses. At some place they say land is not available and at some place, they say that water is not available.

Mr. Speaker : Has the amount advanced been utilised fully ?

Shri Mehr Chand Khanna : We advance this loan through the State Governments. If information is required about a particular industry, I require notice for that.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों को मकान देने में बड़ी असंतोषजनक प्रगति हुई है , क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार

इसको एक नीति का विषय बनाएगी कि गैर-सरकारी उद्योग को लाइसेंस देने के बारे में उनके लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए मकान बनाना आवश्यक कर दिया जाए ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इस प्रश्न पर विचार किया गया है, इसमें बड़ी कठिनाई है ।

श्री दी. चं. शर्मा : उन उद्योगपतियों के विरुद्ध, जिन्होंने किन्हीं वैध कारणों से मकान नहीं बनाए हैं, क्या कोई दण्ड सम्बन्धी वित्तीय अथवा सामाजिक कार्यवाई करने का फैसला किया गया है ?

श्री शिंकरे : 'सामाजिक' से उनका क्या तात्पर्य है ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि जिन्होंने धन खर्च नहीं किया क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : इस बारे में अनिवार्यता कोई नहीं है ।

Shantivana, Delhi

\+

*382. **Shri Naval Prabhakar:**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri R. Barua :
Shri Ram Sewak :
Shri P. G. Sen :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether any plan has been drawn up for the development of Shantivana in Delhi;

(b) if so, the *broad outlines* thereof; and

(c) when it would be implemented ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c) Shanti Vana is proposed to be developed into a *wooded area and deer park.* As short-term arrangements, the *area has been filled up to avoid flooding, footpaths to the Smadhi have been provided* and a *railing round it instal- led.* Plans for long-tetm development are under preparation.

Shri Naval Prabhakar : May I know the total area of land fixed for it ?

Shri Mehr Chand Khanna : Much land is there. We want to clear the whole area of land from Rajghat to the other corner of old fort and no houses should be constructed on that land. That land may be from 70 to 100 or 150 acres.

Shri Naval Prabhakar : Is it a fact that that area is much dirty ? This is an international place where persons from abroad come to pay their homage. Are attempts being made to clear this ?

Shri Mehr Chand Khanna : Yes, Sir the place was very dirty. We are clearing the area of Shantivana and all Jhuggi-Jhopris opposite to Shantivana have also been cleared. We want to develop this place into a very fine place appropriate for the dignity of India.

श्री वसुमतारी : क्या यह योजना निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन है या इसके लिए कोई समिति बनाई गई है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इसका प्रभारी मंत्रालय निर्माण और आवास मंत्रालय है। लेकिन, जैसा मैंने अभी कहा, एक समिति बनाई गई है जो शांति वन के विकास के बारे में मेरे मंत्रालय की सहायता करेगा ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know where fruit trees would be planted in Shantivana and if so, the acreage thereunder and whether these fruits would be utilised for the public?

Mr. Speaker : The trees have not so far been planted and you are anxious for the fruits.

Shri Yashpal Singh : The Jhuggi-Jhopris which are being demolished, Shri Nehru dedicated his life for the welfare of those persons. May I know why they are being made homeless from there ?

Shri Mehr Chand Khanna : The Hon. Member once praised me that I did good work in rehabilitation. I think, he would again praise me as I would soon rehabilitate them.

Mr. Speaker : That certificate was for that time only.

Shri Yashpal Singh : No, my view are some even now.

श्री दे. जी. नायक : शांतिवन के विकास पर कितनी लागत आएगी ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इस समय मेरे लिए यह बताना मुश्किल है। लेकिन योजना तैयार हो रही है और अगले दो या तीन महीनों में इस बारे में हम फैसला कर लेंगे। उसके बाद मैं खर्च के बारे में कुछ बता सकूंगा ।

Shri Sarjoo Pandey : I want to know the cost for developing Shantivana.

Shri Mehr Chand Khanna : After the plan is ready, I shall be able to indicate.

Shri Audul Ghani Goni : In this project of combining Rajghat and Shantivana, whether Government are thinking for instaling a big nursery at Shantivana ?

Mr. Speaker : It is a Suggestion.

Shri Ratan Lal : By when the development of Shantivana would be completed ?

Shri Mehr Chand Khanna : About this something can be told after the plan is ready and long terms project is sanctioned. I think it would take time.

Shri Gulshan : The Hon. Minister said that an area of 100 acres has been acquired for the development of Rajghat and Shantivana. I want to know the area of land required for the construction of Shantighats if ten prime ministers die, the whole of Delhi or land from outside would be acquired?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

यमुना के पानी को दूषित होने से रोकना

-।-

*383. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रा. गि. दुबे :
श्रीमती सावत्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क. ना. तिवारी :
श्री हेडा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में पीने के पानी के संभरण को दूषित होने से रोकने के लिए वज़ीरावाद के निकट यमुना नदी में बाढ़ का पानी को मिलने से रोकने के लिए अब दो परियोजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और उन पर कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री यू. शे. नास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यमुना के पानी को दूषित होने से रोकने के लिए निम्नलिखित दो परियोजनाओं पर अमल किया जाने वाला है :—

(1)(क) टेल रेगुलेटर से शाह आलम पुल तक बांध का निर्माण

यह कार्य दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में आरम्भ किया है और इस पर 31,000.00 रुपये खर्च आने का अनुमान है । फरवरी, 1965 तक लगभग $2\frac{1}{2}$ लाख घनफुट मिट्टी खोदने का कार्य पूरा हो चुका था ।

(ख) वज़ीराबाद से 1400 फीट नीचे की ओर यमूना से मिलने वाले दहाने की चट्टान की खुदाई

यह कार्य पंजाब सरकार के कर्नाल ड्रेनेज सर्कल द्वारा किया जाना है । इस कार्य को समाप्त करने के लिए लक्ष्य तिथि जून, 1965 रखी गई है । इस कार्य पर 1,90,500.00 रूपये व्यय आने का अनुमान है ।

(2)(क) बुरारी नाले के बांये किनारे के साथ साथ 7,100 फीट लम्बा बांध

यह कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा इस वर्ष किया जाना है । इस पर 6,17,700.00 रुपये व्यय आने का अनुमान है । इस काम के टैन्डर पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और उसे अब दिया जा रहा है ।

(ख) बुरारी नाले के अन्तिम छोर पर रेगुलेटर

यह कार्य भी दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाना है। केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग डिजाइन तैयार कर रहा है। इसके प्राक्कलन अभी तैयार नहीं हुए हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : विवरण से पता चलता है कि पहली परियोजना में टेल रेगुलेटर से शाह आलम पुल तक बांध बनाने का कार्य दिल्ली प्रशासन को सौंपा गया है और वज़ीराबाद से 1400 फुट नीचे की ओर यमुना से मिलने वाले दहाने की चट्टान को तोड़ने का कार्य पंजाब सरकार करेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि एक ही परियोजना के यह दोनों कार्य दो भिन्न भिन्न एजेंसियों को क्यों सौंपे गये हैं और इन दो परियोजनाओं के कार्य में समन्वय के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं जिससे दोनों स्थानों पर कार्य अनुसूची के अनुसार पूरा हो सके ?

श्री यू. शे. नास्कर : बाढ़ रोकने का कार्य दिल्ली प्रशासन को इसलिये सौंपा गया है क्योंकि मद संख्या 1 दिल्ली प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आती है और दूसरा कार्य पंजाब सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है इस लिए उनको दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण और समवाय सम्बन्धी कार्य के लिए सिंचाई मंत्रालय उत्तरदायी है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पानी के दूषित होने के मामले पर सलाह लेने के लिए कुछ विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया है; यदि हां, तो क्या हम यह समझें कि हमारे लोक-स्वास्थ्य इंजीनियर और विशेषज्ञ इस समस्या को सुलझाने के लिए सक्षम नहीं हैं और हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा. सुशीला नायर) : जी, नहीं। हमने किसी विदेशी विशेषज्ञ को नहीं बुलाया है। परन्तु संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रशासन का एक लोक स्वास्थ्य इंजीनियर यहां पर है, जिनसे हमारे इंजीनियर परामर्श ले सकते हैं। इनसे भले ही कुछ परामर्श लिया गया हो, परन्तु हमने कोई विदेशी सहायता नहीं मांगी है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : ब्रिटेन से जो श्री टेलर इस प्रयोजन के लिए 26 मार्च, को आ रहे हैं उन के बारे में क्या है ?

डा. सुशीला नायर : दिल्ली नगर निगम ने ब्रिटेन की प्रयोगशाला के नमूने की एक प्रयोगशाला बनाने के लिए कहा है। मेरे विचार में यह सुझाव माननीय मंत्री डा. कु. ल. राव द्वारा दिया गया है। जिन्होंने ब्रिटेन की प्रयोगशाला देखी है और क्योंकि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत उपकरण आदि की सहायता मांगी गई थी, इसलिये श्री टेलर इस का मूल्यांकन करने जा रहे हैं।

श्री रा. गि. दुबे : क्या ढासा बांध का इन परियोजनाओं से कोई सम्बन्ध है और यदि हां, तो क्या वह वैसा ही रहेगा जैसा पहले है अथवा उसमें कोई परिवर्तन किये जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा. कु. ल. राव) : ढासा बांध का इन परियोजनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में यह बताया गया है कि बुरारी नाले के अंतिम छोर पर रेगुलेटर सम्बन्धी कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जायेगा और केन्द्रीय जल तथा

विद्युत आयोग द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन अभी तैयार नहीं है। क्या यह रेगुलेटर जून के अन्त तक अथवा जुलाई के आरम्भ तक तैयार हो जायेगा क्योंकि इन महीनों में पानी अधिक दूषित होता है ?

डा. कु. ल. राव : कार्यों में अच्छी प्रगति हो रही है और आशा है कि बरसात में पानी के आने से पहले यह सभी कार्य समय पर पूरे हो जायेंगे।

Shri Vishwa Nath Pandey : When will these two projects be completed.

डा. कुल. ल. राव : जून के अन्त तक कार्य समाप्त होने की सम्भावना है।

Shri Bibhuti Mishra : It has been mentioned in para 2(a) of the statement laid on the Table that the estimated cost is Rs. 6 crores and 17 lakhs and that "tenders for the work have already been received and the work is being awarded". The hon. Minister just said that the works would be completed by June-July, may I know as to when the works would be completed precisely.

Mr. Speaker : He said that the work would be completed either by the end of June or in the begining of July.

Shri K. N. Tiwary : It has been mentioned in the statement that the expenditure would be borne by both Punjab and Central Governments. May I know how much expenditure would be borne by each of them separately ?

डा. कु. ल. राव : कार्य भिन्न भिन्न एजेंसियां करेंगी परन्तु खर्चा सारा दिल्ली प्रशासन बर्दाश्त करेगा।

श्री हेडा : क्या माननीय मंत्री इस सभा को तथा दिल्ली के लोगों को यह आश्वासन दे सकते हैं कि इस वर्ष हमें जो पानी मिलेगा वह दूषित नहीं होगा और मिलेगा भी पर्याप्त मात्रा में ?

डा. सुशीला नायर : जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय का सम्बन्ध है हम यह आश्वासन दे सकते हैं कि हम पानी को अच्छी तरह साफ करेंगे जैसाकि पिछले साल भी किया था जिससे लोगों को हानि न हो। जहाँ तक बाढ़ नियंत्रण का सम्बन्ध है, इसके लिये मेरे मित्र उत्तरदायी हैं और वह इस दिशा में हर सम्भव उपाय कर रहे हैं।

Shri Rameshwaranand : Is there any place in Delhi from where good water could be extracted and supplied to the people by means of tube-wells so that it has no bad effect on thier health ?

Mr. Speaker : The suggestion made by the hon. Member might be looked into.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, the answer should came from the Minister.

Mr. Speaker : He said that the water of Jamuna was becoming polluted and instead of treating it, tube-wells should be set up at suitable places to have good water, thereupon I asked the hon. Minister that he should look into that matter. What more you require ?

Shri Rameshwaranand : Has he any such scheme ?

Mr. Speaker : It is what I have told the hon. Minister that he should think over a scheme so that Swamiji is satisfied.

चौथी योजना में बेरोजगारी

+

*384. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स. मो. बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र. रं. चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क. ना. तिवारी :
श्री हेम बरुआ
श्री मोहन स्वरूप :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र. चं. बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री 1 अक्तूबर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी विकास योजनाओं तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया है जो चौथी योजना की अवधि में बेरोजगारी दूर करने के लिए अन्ततः जिम्मेदार होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब. रा. भगत) : (क) चौथी योजना के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का काम अभी प्रगति पर है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या आयोग में यह निर्णय ले लिया है कि रोज़गार की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कुटीर उद्योगों, भारी उद्योगों तथा लघु उद्योगों में कितना विनियोजन किया जायेगा ?

श्री ब. रा. भगत : जी, हां । प्रारम्भिक ज्ञापन में यह सब जानकारी दी गई है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सभी योजनाओं की, जैसे जन शक्तिउपयोग योजना तथा अन्य योजनायें जिनका अभिप्राय बेरोज़गारी को दूर करना है, चौथी योजना में, ले ली जायेंगी ।

श्री ब. रा. भगत : उनका केवल चौथी योजना में ही नहीं लिया जायेगा अपितु उनका चौथी योजना में पुनरीक्षण तथा विस्तार भी किया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh : May I know the number of unemployed persons who would not be able to get employment by the end of Third Five Year Plan? How many such persons would be in the cities and how many in the villages ?

Shri B. R. Bhagat : Roughly speaking 13 million persons would be given employment by the end of the Third Five Year Plan and the number of unemployed persons then would be 23 millions.

श्री रंगा : शहरों में कितने और देहातों में कितने ?

अध्यक्ष महोदय : देहातों के बारे में उसके पास आंकड़े नहीं हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : क्योंकि तीसरी योजना के समाप्त होने के पश्चात् बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो जायेगी, क्या सरकार का विचार लोगों को सामान्य आश्वासन देने के अतिरिक्त चौथी योजना में उन बे रोज़गारों के लिए बेरोज़गारी बीमा योजना शामिल करने का भी है जो बेरोज़गारों के रूप में रजिस्टर्ड हैं ?

श्री ब० रा० भगत : हम बेरोजगारी भत्ता देने के हक में नहीं हैं। जहां तक बेरोज़गारी बीमा का प्रश्न है, इस पर विचार किया जा रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : It is clear from the results achieved in the 2nd and 3rd Five Year Plans that the Government have not been able to provide employment to those who were ausured employment. The hon. Minister has just given some approximate figures. May I know whether any programme would be chalked out in the Fourth Year Plan so that all those people could be absorbed to whom employment is assured.

Shri B. R. Bhagat : 14 million persons were to be given employment during the third Five Year Plan. Out of which 13 million persons were absorbed. It is correct that the target was not fulfilled either due to none-implementation of the Plan fully and or due to the fact that while financial targets were completed, the fiscal targets would not be reached because of rise in prices. On the basis of the last experience we are examining it as to how operational efficiency in the Fourth Five Year Plan could be increased, fiscal prgorammes could be finished through phased programmes and on that basis the target could be reached.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तीसरी योजना के अन्त तक 300 लाख से भी अधिक बेरोज़गार होंगे, क्या सरकार का विचार उनको कोई सहायता देने का है ?

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना में उनको रोज़गार देने के अतिरिक्त हम बेरोज़गारी बीमा योजना के वित्तीय तथा अन्य पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Would this be taken into consideration that equal and justifiable employment opportunities are provided to the people of each regioning the country ?

Shri B.R. Bhagat : It is always taken into consideration.

Shri K.N. Tiwary : As there was shortfall in the third Five Year year Plan there might be shortfall in Fourth Five Year Plan also. Have any figures been worked out as to how many persons would not be given employment and what arrangement have been made to provide them employment?

Shri B.R. Bhagat: Mr. Speaker, there was some mistake in my answer given before, I may be allowed to correct that. I stated that there would be 23 million unemployed persons in the beginning of the Fourth Five Year Plan. These 23 million persons would be new entrants for employment. There would be a backlog of 12 million unemployed. In order to complete the programme in the Fourth Year Plan, we are formulating intensive labour schemes and rural works schemes and we expect that this programme of fiscal targets is completed.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि चौथी योजना बनाते समय आयोजकों के ध्यान में यह बात थी कि योजना में रोजगार की बजाये उत्पादन पर अधिक बल दिया जाये और यदि हां तो बेरोजगारों तथा कम काम वालों को रोज़गार दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : योजना में उत्पादन तथा रोजगार दोनों पर बल दिया जायेगा।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : सरकार पूर्व-निर्मित मकानों सम्बन्धी योजना को चालू क्यों कर रही है जिस से बेरोजगारी बढ़ती है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं नहीं जानता कि पूर्व-निर्मित मकानों से बेरोजगारी में वृद्धि होती है। यदि ऐसा है, तो उन को रोजगार दिलाने के लिये अन्य उपाय ढूंढने पड़ेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना काल में शिक्षित बेरोजगार कितने होंगे ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether agricultural labourers are also included in the figures which the hon. Minister has just given, and if not, what do the Government propose to do for them ?

Shri B. R. Bhagat : They are also included in them.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has this come to the notice of the Government that workers have been retrenched from a number of factories as a result of which they have become unemployed. Are the Government proposing to take any steps to prevent the employers from taking such action in the private sector during the Fourth and Fifth Year Plans ?

Shri B. R. Bhagat : The Ministry of Labour attends to it off and on.

Shri Sheo Narain : The Government said that they have not been able to provide employment to 13 million persons. May I know whether any money would be paid as subsidy to the unemployed persons to enable them to run small scale industries or whether the Government would give any allowance to them as it is given in the foreign countries ?

Mr. Speaker : It has already been answered.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : चौथी योजना के ज्ञापन में यह बताया गया है कि तीसरी योजना के अन्त तक 35 लाख लोगों को कृषि क्षेत्र में रोज़गार दिया जायेगा ; और यदि ऐसा है, तो क्या उस लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा और यदि नहीं, तो चौथी योजना के लिये उन में से कितने शेष रह जायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत वास्तव में तीसरी योजना में कृषि क्षेत्र में 15 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा ।

Shri Daljit Singh : May I know whether the cojpletion of dams and other projects has resulted in more unemployment, whether this matter was considered ?

Shri B. R. Bhagat : Efforts are made to give them employment in other new projects which are undertaken or any other employment is given to them.

श्री रंगा : क्या यह सच है कि सरकार ने कृषि श्रमिकों को रोज़गार दिलाने की किन्ही विशेष योजनाओं का उद्घाटन अथवा स्थापना नहीं की है और कि कम काम वालों को काम दिलाने सम्बन्धी समस्या को अभी सुलझाना है ?

श्री ब० रा० भगत : यह बहुत बड़ी समस्यायें हैं और माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि इनको एक योजना काल में नहीं सुलझाया जा सकता । इस के लिये तो लम्बी अवधि का प्रोग्राम है । हम इस समस्या को तीसरी योजना में सुलझाने का प्रयत्न करते रहे हैं और चौथी योजना में हम ने विभिन्न योजनायें चलाई हैं जिस से घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी का अधिक बोलबाला है, अधिक रोजगार दिया जा सके । हम ग्रामीण कृत्यों तथा अन्य उद्योगों का भी विकास कर रहे हैं जिस से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार दिया जा सके ।

Shri Bhagwat Jha Azad : It is clear in the last year of the Third Five Year Plan that the number of unemployed persons is increasing continuously. Would employment be provided to 230 lakh new entrants or the backlog of 130 lakh unemployed would also be absorbed, if so, which matters in regard to development schemes and the directive principles would be considered ?

Shri B. R. Bhagat : Efforts are being made that employment is provided to 230 lakh new entrants at least and thereafter the remaining people are also given employment as far as possible.

विदेशी पूंजी

\+

*385. श्री दी० चं० शर्मा :
प्र० चं० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री द० ब० राजू :
श्री कोल्ला बैंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती रेणुका राय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० च० सामन्त :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी के और अधिक समन्याय भाग लेने को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). पूंजी लगाने के लिए इन वर्षों में कुछ प्रोत्साहन दिये जा रहे थे जो देशी और विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में लागू होते थे । इन प्रोत्साहनों और वित्त विधेयक, 1965 में प्रस्तावित कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहनों का ब्यौरा सभा की मेज पर रखे गये विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—39 66/65]**

श्री दी० चं० शर्मा : हमारी सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने के बावजूद, वित्तीय पत्रों अथवा अन्य दैनिक और साप्ताहिक पत्रों के अनुसार पूंजी क्यों नहीं आ रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस के कुछ गहरे कारण हैं । लोगों के पास विनियोजन के लिये जो राशि है उस में निस्संदेह ही परिवर्तन आया है । यह भी सच है कि जो वर्ग छोटी राशियां विनियोजित करते थे उन के पास विनियोजन के लिये शायद पैसा नहीं है । यह भी कि जिन श्रेणियों के पास अधिक धन है वे इसलिये विनियोजन नहीं कर रहे हैं कि उन के पास कोई जाता नहीं है । इसके लिये किसी एक कारण को बताना कठिन है ।

एक और कारण भी है, अर्थात्, लोग अपने विनियोजन द्वारा होने वाली आय की अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते ।

इन सब बातों पर विचार कर के सरकार ने कुछ प्रोत्साहन दिये हैं। अभी कुछ समय बाद मालूम होगा कि क्या होगा । परन्तु मेरी अपनी राय यह है कि—और यह बिल्कुल व्यक्तिगत राय है—उन क्षेत्रों में जाया नहीं जाता है जहां पर विनियोजन के लिये पूंजी है, और जिन व्यक्तियों को पूंजी चाहिये वे अथवा दलाल शहरों से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते हैं ।

श्री रंगा : ग्रामीण क्षेत्रों में धन कहां है ?

श्री दी० चं० शर्मा : किसी भी देश में विदेशी पूंजी को रखना आग से खेलने के बराबर है जैसा कि अफ्रीकी, लेटिन अमरीका और विश्व के अन्य देशों का अनुभव है । और वे देश स्वामित्व हरण तथा अन्य उपायों द्वारा विदेशी पूंजी से पीछा छुटाने का प्रयत्न कर रहे हैं । सरकार के पास इस बात की क्या गारंटी है कि विदेशी पूंजी का हमारे देश के लोकतन्त्रात्मक ढांचे में कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं होगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वही शर्तें हैं जो स्वदेशी पूंजी के राजनैतिक प्रभाव को रोकने के संबंध में हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या विदेशी विनियोजकों को कुछ विशेष रियायतें दी जाती हैं जो कि भारतीय विनियोजकों को नहीं दी जाती हैं और यदि हां, तो वे रियायतें क्या हैं और विनियोजन करने वाले किन किन लोगों को ये रियायतें दी जायेंगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : विनियोजकों को सामान्यत: एक जैसी ही रियायतें दी जाती हैं सिवाय इस के कि विदेशी विनियोजकों को अपनी पूंजी वापस ले जाने की अनुमति होती है और वे लाभांश को भी अपने देश वापस ले जा सकते हैं। कुछ और रियायतें उन देशों —विशेषत: उन में से दो अमरीकी की सरकार और पश्चिम जर्मनी की सरकार — के सहयोग से, जिन से पूंजी मंगाई जाती है, विनियोजनकर्त्ताओं को दी जाती है । वे रियायतें यह हैं कि उन देशों की सरकारों ने संभाव्य हानि के विरुद्ध उन कम्पनियों का बीमा किया होता है जो भारत में पूंजी लगाती है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या उन को कर से छुट्टी दे दी जाती है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वह तो हर एक को होती है ।

Shri Siddheshwar Prasad : Just now the hon. Finance Minister said that the areas from which there is the possibility of raising capital could not have been approached. May I know the steps Government propose to take to establish contacts with those areas ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : भारत सरकार का मंत्री ऐसे विशेष लोगों का एजेंट नहीं होता है जो पूंजी लगाना चाहते हैं। गैर सरकारी पूंजी, गैर सरकारी लोगों द्वारा ही इकट्ठा की जा सकती है और इस के लिये उनको लोगों को मनाना होगा ; यह संभव नहीं है कि उन के लिये मंत्री या अन्य कोई व्यक्ति विनियोजनकर्त्ताओं को मनाये।

Shri Yashpal Singh : Are Government in a position to give assurance that most of the shares will be of Indians ?

Shri B. R. Bhagat : So far the practice has been that mostly shares will be given to Indians ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस मूल प्रश्न की जांच की है कि क्या विदेशी पूंजी लगाने को बढ़ावा देना अधिक वांछनीय है अथवा विदेशों से ऋण लेना ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ऋण और पूंजी विनियोजन में अन्तर होता है। ऋण ऐसी चीज है जिसे शीघ्र लौटाना पड़ता है और जो लोग इसमें पैसा लगाते हैं उनकी किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं होती है। पूंजी ऐसी चीज है जो अधिक समय ठहरती है, और यद्यपि हम इसको वापस ले जाने की अनुमति देते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि पूंजी को वापस ले जाया जाये और प्राय: वे अपना मुनाफा भी यहां पर ही लगा देते हैं जैसा कि विदेशी कम्पनियों ने भारत में किया है। दीर्घकालीन बातों को सामने रख कर ऋण और पूंजी में से पूंजी अधिक अच्छी है, परन्तु यह एक व्यक्तिगत निर्णय की बात है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय वित्त मंत्री को कितनी पूंजी का विनियोजन हो जाने की आशा है ? हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था में उनके विचार में कितनी पूंजी काफी होगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा होता है । हमारी चतुर्थ योजना के अनुमानों के अनुसार हमें कुछ और विदेशी सहायता की आवश्यकता है न केवल नये उद्योग स्थापित करने के लिये ही नहीं अपितु पहले लिया हुआ पैसा वापस करने के लिये भी । प्रश्न यह है कि क्या यह उसी रूप में उपलब्ध होना चाहिये जिस रूप में कि यह आता रहा है, क्या इसमें कुछ विदेशी गैर सरकारी पूंजी विनियोजन के तरीके से नहीं जोड़ दिया जाना चाहिये । परन्तु माननीय मंत्री को इस बात का भी पता होना चाहिये कि केवल हमारा ही देश नहीं है जिसको विदेशी गैर सरकारी पूंजी चाहिये । योरोपीय साझा बाजार के देशों और अफ्रीकी देशों का तो कहना ही क्या केनेडा, आस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे अनेक देश हैं । इसलिये यह बताना बड़ा कठिन है कि कितनी पूंजी उपलब्ध होगी ।

इसके बारे में वास्तव में बात यह है । यदि पूंजी हमारी शर्तों पर आती है---और वे शर्तें बहुत साफ हैं---तो हम इसका स्वागत करते हैं ; यदि पूंजी केवल उनकी शर्तों पर आती हैं, तो हम यह ही कहेंगे कि हमें नहीं चाहिये । मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यह ठीक है कि भारत को विदेशी सहायता और विदेशी पूंजी चाहिये, वह दूसरे लोगों द्वारा बताई गई शर्तों पर लेने के लिये तैयार नहीं है ।

श्री रंगा : हमें बहादुर बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हो सकता है । मुझे खेद है । हम दोनों एक ही युग के हैं ; परन्तु हम अलग अलग पैदा हुए हैं । मेरे माननीय मित्र बहादुर नहीं बनाना चाहते । मैं बहादुर बनना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे सभी मित्र यहां पर बहादुर हैं ।

श्री रंगा : आप वास्तव में बहुत बहादुर हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इसलिये अपने आत्म-सम्मान को ध्यान में रख कर जब कि हम विदेशी पूंजी को प्रत्येक संभव रियायत देते हैं, हम इसको उन शर्तों पर नहीं लेते हैं जो हमें मंजूर न हो ।

माननीय मंत्री कहेंगे आपका क्या अनुमान है ? मैं यह नहीं बता सकता । यह धीरे धीरे आ रही है । हमें एक और बात पर विचार करना है कि हमारे सामने केवल विदेशी मुद्रा की ही कठिनाई है ; अनेक देशों के सामने भुगतान और संतुलन की कठिनाइयां हैं । उदाहरणार्थ ब्रिटेन: अमरीका भी । वे विदेशी ऋणों और विदेशी विनियोजनों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं । हो सकता है इस समय वातावरण बहुत अच्छा न हो परन्तु परिवर्तन होता ही है । इसलिये हम दूरदर्शिता से काम लेते हैं और अपने सिद्धांतों और अपने सम्मान को ध्यान में रख कर अपनी तैयारियां करते हैं ।

श्री रंगा : वित्त मंत्री को भी बदलना चाहिये ।

श्रीमती रेणुका राय : क्या सरकार इससे अवगत है कि इन में से कुछ रियायतों से, जो कि भारतीय कम्पनियों की अंश पूंजी में विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिये हैं, कुछ कदाचार बढ़ा है जिनके द्वारा प्रतीत होता है कि इन में से कुछ कम्पनियों के बड़े व्यक्तियों ने विदेशों में बैंकों में काफी धन जमा कर लिया है और यदि हां, तो क्या सरकार इन खराबियों को दूर करने के लिये कोई कदम उठा रही है जिनके द्वारा कि छिपे हुए धन को विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जा रहा है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इन रियायतों का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या विदेशी विनियोजकों को विनियोजन करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि वर्तमान छूट केवल प्राथमिकता वाले उद्योगों तक ही सीमित है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सामान्यतः ऐसा है। प्राथमिकता वाले उद्योग, जिनको हम स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे उद्योग हैं जिनको हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, और यदि इसके लिये विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है तो विदेशी पूंजी को देश में आने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है।

श्री हो० ना० मुकर्जी: आजकल अधिकांश अल्पविकसित देशों की यह नीति है कि वे समाजवाद की नीति पर चलते हैं और विदेशी पूंजी को अपने देश से निकाल रहे हैं। इस देश की यह नीति रही है कि विदेशी गैर सरकारी पूंजी की बजाय विदेशी ऋण लेने में क्या बुराई है। तो क्या इस का अर्थ मैं यह समझूं कि वित्त मंत्री ने अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार जिसका कि उन्होंने अपने उत्तर में कई बार उल्लेख किया है, सरकार की नीति में परिवर्तन कर दिया है ? अथवा सरकार ने ही विदेशी पूंजी के स्वागत करने का निर्णय कर लिया है जब कि हमारा अनुभव यह कहता है कि यह एक खतरनाक चीज़ है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वास्तव में स्थिति इस प्रकार है। हम विदेशों से ऋण मांगते रहे हैं। हम समझते हैं कि विदेशी ऋणों की मात्रा पर्याप्त नहीं होगी, हो सकता है इन ऋणों की शर्तें हमें विशेष रूप से स्वीकार्य न हों। विदेशी पूंजी के कुछ अपने फायदे हैं। हमें विदेशी पूंजीपति का यहां की किसी संस्था से गठजोड़ करना होगा और उसके द्वारा उस संस्था को बढ़ाना होगा। विभिन्न अन्य कारण भी हैं जैसे कि पूंजी को वापस विदेशों में भेजने को स्थगित करने का प्रश्न। परन्तु एक बात जो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं वह यह है कि जो भी विदेशी पूंजी आती है, वह बाढ़ के रूप में आती है अपितु आहिस्ता आहिस्ता आती है। इसलिये विदेशी पूंजीपतियों की मांगों के सामने सरकार के झुकने की बात पैदा नहीं होती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि अंश पूंजी में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी भागिता केवल हमारी शर्तों और निबन्धनों पर ही स्वीकार्य होगी न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बताई गई शर्तों पर। यह आश्वासन पश्चिम जर्मनी की गैर-सरकारी पूंजी भागिता पर किस प्रकार लागू होगा, जो कि और देशों को पूंजी देते समय अपनी शर्तें रखता है तथा पश्चिम जर्मनी और पूर्व जर्मनी की सरकार के सम्बन्धों पर इसका क्या असर होगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र दो बातों को मिला रहे हैं। एक बात तो पश्चिम जर्मनी से पूंजी के आने की है। दूसरी बात उनके पड़ौसी देशों के साथ, जो उनके अपने देश का भाग था, सम्बन्धों के बारे में उनकी अपनी प्रवृत्ति के मिलाने की है। ये अलग अलग प्रश्न हैं। यदि पश्चिम जर्मनी की पूंजी यहां आती है तो वह उन शर्तों पर आती है जो हमें स्वीकार्य होती हैं, परन्तु यदि शर्तें कुछ और हो जाती हैं तो इसका कारण पूंजी के आने का नहीं है परन्तु अन्य परिस्थितियां होती हैं।

श्री विश्वनाथ राय : सरकार की औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने का जो विचार है क्या उसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थ व्यवस्था पर समय बीतने पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि विदेशी पूंजी को यहां आने देकर अथवा भारतीय पूंजी को विनियोजन करने में प्रोत्साहन देकर ऐसी कोई बात नहीं की जायेगी जिसका कि अन्त में हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पर या हमारे देश में राजनैतिक शक्ति के संतुलन पर बुरा असर पड़ता हो।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या यह सच नहीं है कि बहुत से विदेशी विनियोजन समान अंशों की भागिता की शर्त पर भारत में धन लगाने के लिए तैयार हैं; परन्तु इसके साथ साथ उनको यह शिकायत है कि यहां देर होती है और इस देश में अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं ? सरकार की नीति क्या है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यहां लोग देर की शिकायत करते हैं इसको सब जानते हैं, मुझे भी पता है। हम स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु अनुकूल परिस्थितियों का प्रश्न एक ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं सकता क्योंकि परिस्थितियां एक सार्थ से दूसरी सार्थ में भिन्न प्रकार की होती हैं। हम तो केवल इतना ही कर सकते हैं कि गाजर को पकड़ लें, परन्तु गधे को बांध नहीं सकते कि वह उसे खाये।

चतुर्थ योजना

+

श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
*386. श्री हेम राज :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री मानसिंह पु० पटेल :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा हाल में की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए योजना आवंटनों पर पुनर्विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विकास परिषद् ने चौथी योजना के आकार और उद्देश्यों के बारे में सामान्यतया योजना आयोग के प्रस्तावों का अनुमोदन किया और चौथी योजना के क्षेत्रीय कार्यक्रम बनाने तथा साधनों से सम्बन्धित नीति विषयक मामलों पर सलाह देने के लिए पांच समितियों का गठन किया। समितियों ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्योंकि योजना आयोग ने यह निश्चय किया है कि इसके मूल प्रस्ताव के अनुसार योजना व्यय 22,500 करोड़ रु० ही रखा जाये, लोगों के मन से, जिन में कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज भी शामिल हैं, यह आशंका दूर करने के लिए कि योजना से मुद्रा स्फीति को बढ़ावा मिलेगा, क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इन मामलों की अब जांच की जा रही है; और मुझे आशा है कि मैं बजट पर बहस का उत्तर देते हुए स्थिति को स्पष्ट कर दूंगा।

श्री प्र. चं. बरुआ : क्या योजना आयोग यह समझता है कि सिक्के के फैलाव को कम करने के लिए कुछ अतिरिक्त कर लगाये जाये जाने चाहियें, और यदि हां, तो इसके बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : संसाधनों सम्बन्धी समिति इन सब बातों पर विचार करेगी। इस समिति की एक बैठक हो चुकी है और अभी और भी बैठकें होंगी।

Shri Yashpal Singh : May I know the time by which the decisions taken will be placed on the Table for consideration ?

Shri B.R. Bhagat : Memorandum has already been placed and afterwards whatever decisions are taken or draft plan received will be placed on the Table of the House.

Shri Bhagwat Jha Azad : Are different groups of people in the country pressing for reducing the estimated amount given in the statement for spending on the Plan? Have Government considered it and should it be taken that that amount will not be altered, or do Government propose to reconsider it by being under the pressure ?

Shri B.R. Bhagat : No, Sir. That amount has been accepted. The amount mentioned in the Memorandum has been accepted by National Development Council, Planning Commission and Government.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What items have been given priority in this plan ; whether priority has been given to national defence, food problem or industries ?

Shri B.R. Bhagat : All these details have been given in the memorandum.

श्री स० चं० सामन्त : जो पांच समितियां बनाई गई हैं उनमें किन किन संगठनों अथवा अभिकरणों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

श्री ब. रा. भगत : वे ऐसी समितियां हैं जिनमें राज्यों और योजना आयोग के प्रतिनिधि हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय का ध्यान कृषि मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कृषि के लिये एक पृथक् योजना होगी, और यदि हां, तो क्या उस योजना को इस योजना में रख लिया गया है ? कृषि योजना की मुख्य बातें क्या हैं जिस पर कि कृषि मंत्रालय विचार कर रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं नहीं जनता कि कृषि मंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया हो, परन्तु कल ही मैं ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि किसी पृथक् योजना का प्रश्न नहीं है, परन्तु चतुर्थ योजना के भीतर ही कृषि के लिए एक स्वयंपूर्ण योजना तैयार की जा रही है जिसमें लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी बातों की व्यवस्था की गई है ।

Shri R.S. Tewari : May I know the amount allocated for Madhya Pradesh in the 4th Five Year Plan ?

Shri B.R. Bhagat : That shall be determined while finalising the Madhya Pradesh Plan.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

परिचर्या (नर्सिंग) के लिए केन्द्रीय पदाली

*387. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परिचर्या सेवा की केन्द्रीय पदाली बनाने का प्रस्ताव तैयार करने तथा उसकी कार्यान्विति में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). इस प्रस्तावित केन्द्रीय उपचर्या सेवा के गठन के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

संयुक्त अरब गणराज्य तथा जोर्डन में सिंचाई सम्बन्धी भारतीय दल का प्रतिवेदन

*388. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दे० जी० नायक :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सेवक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई, कृषि तथा आयोजन के वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के पांच-सदस्यीय दल ने, जो संयुक्त अरब गणराज्य तथा जोर्डन गया था, उन दोनों देशों में सिंचाई विकास तथा कृषि विस्तार कार्यों के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या मुख्य सुझाव दिये हैं; और

(ग) भारत में कार्यान्विति के लिए उनके सुझाव कहां तक व्यवहार्य हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

कर से बचना

*389. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरन्तर कर से बचने वाले व्यक्तियों को काली-सूची (ब्लैक लिस्ट) में रखने की और जनता या आय कर विभाग के कर्मचारियों के लाभ के लिये समय समय पर उनकी सूचियां प्रकाशित करने की कोई व्यवस्था है ;

(ख) क्या यह सच है कि कर-संग्रह प्रशासन के कुछ विशेषज्ञों ने ऐसे उपायों के सुझाव दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे अपराधियों के नामों के अधिक विस्तृत प्रचार करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) हालांकि कर से बचने वाले व्यक्तियों को काली-सूची (ब्लैक लिस्ट) में रखने की इस प्रकार की कोई प्रणाली नहीं है,

सरकार ऐसे व्यक्तियों के नाम जिन पर कर के अभिप्रायों के लिये आमदनी को छिपाने के कारण 5,000/- रु० या अधिक का दण्ड लगाया गया हो और उनके नाम जिन्हें आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये अभियोजनों के परिणाम स्वरूप दोषी ठहराया गया हो, सरकारी गजट में प्रकाशित करती आ रही है ।

(ख) यह कदम प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति ने सुझाया था ।

(ग) वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है ।

Smuggling of Chinese Goods to India

*390 **Shri Madhu Limaye :**
Shri M.L. Dwivedi :
Shri R.S. Tiwary :
Shri S.C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :
Shri Basappa :
Maharajkumar Vijaya Ananda :
Shrimati Renuka Barkataki :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shei Rameshwar Tantia :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri R. Barua :
Shri Ravindra Varma :
Shri P.C. Borooah :
Shri D.C. Sharma:
Shrimati Johraben Chavda :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports of smuggling of Chinese goods into India through Nepal ;

(b) whether it is a fact that individual articles the value of which does not exceed Rs. 75 can be brought into India without payment of duty ;

(c) whether it is also a fact that the Nepalese currency is in Circulation in the Indian border areas near Nepal ; and

(d) if so, the steps Government propose to take in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) The Government are aware of such reports.

(b) People coming from Nepal are given the same baggage concessions as are given to persons coming from other countries, including duty free import of articles upto the value of Rs. 500/- to Rs. 1,000/-, depending upon the period of their stay in Nepal subject to the conditions that the value of any individual article does not exceed Rs. 75/- and the Customs officer is satisfied that a particular passenger is not visiting India frequently and bringing foreign articles for sale in India.

(c) As far as Government are aware Nepalese currency is not in circulation in Indian areas bordering on Nepal.

(d) At present there is no large scale smuggling of Chinese goods into India. However, the matter is under close watch and appropriate action will be taken whenever necessary.

कलकत्ता में एक व्यापारी के मकान की तलाशी

*391. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री कलकत्ता की हैरिंगटन और केनिंग स्ट्रीट के कुछ मकानों, आदि की तलाशी के बारे में 10 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सीमा-शुल्क और आयकर प्राधिकारियों ने जांच-पड़ताल पूरी कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख). सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा मामले के कुछ पहलुओं की जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है । और कुछ शो-काज नोटिस जारी किये गये हैं । सीमा-शुल्क तथा आय-कर प्राधिकारियों द्वारा आगे जांच-पड़ताल अभी प्रगति पर है और जितनी जल्दी हो सकेगा, पूर्ण कर दी जायगी ।

ग्रामीण विकास के लिए श्री चेस्टर बाउल्स की योजना

*392. **श्री हेमराज :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री 17 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 554 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ग्रामीण विकास के लिये श्री चेस्टर बाउल्स द्वारा तैयार की गई योजना को अन्तिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) योजना को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). प्रत्येक राज्य के एक जिले में समेकित तथा व्यापक विकास का आदर्शरूप तैयार करना, जो कि एक योजना आगे हो, की योजना के ब्यौरे पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों की टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए ध्यान-पूर्वक विचार किया गया है । इसके बाद यह निश्चय किया गया है कि राज्यों की चौथी योजनाओं के निरूपण के अभिन्न अंग के रूप में कृषि, सहकार, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, प्रारंभिक और सामाजिक शिक्षा, ग्रामीण जल-सम्भरण और सफाई, इत्यादि क्षेत्रों में तुरन्त जिला विकास योजनायें तैयार करने का काम शुरू किया जाय ।

भारत का विदेशी दायित्व

*393. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हिम्मतसिंह हका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1955 और 1961 के बीच भारत के विदेशी दायित्व में 1,736 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है ;

(ख) विदेशी लेखे के इतने बड़े और बढ़ते हुए राष्ट्रीय ऋण की किस प्रकार ऋण-व्यवस्था (सर्विस) करने का विचार है ; और

(ग) अमरीका, ब्रिटेन और रूस को कितनी-कितनी राशियां देनी है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। यह सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की कुल देनदारी में हुई वृद्धि है ।

(ख) विदेशों से ऋण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए लिया गया और ऋण चुकाने के लिए उत्पादन और निर्यात बढ़ाकर साधन ढूंढ़ने होंगे । जिन शर्तों पर सहायता मिलती है, सरकार उन्हें उदार कराने के लिए भी कोशिश कर रही है ।

(ग) 31 दिसम्बर, 1961 को भारत के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की कुल देनदारी संयुक्त राज्य अमरीका के प्रति 916.9 करोड़ रुपये, ब्रिटेन के प्रति 664.7 करोड़ रुपये और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के प्रति 68.5 करोड़ रुपये थी ।

योजना आयोग

*394. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **योजना** मंत्री 10 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में अनावश्यक कर्मचारियों की छटनी करने तथा कर्मचारियों का पुनर्गठन करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर योजना आयोग ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). यह प्रस्ताव अभी योजना आयोग के विचाराधीन है ।

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

*395. **श्री मती रेणुका बड़कटकी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एक व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या होंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की एक योजना सम्मिलित करने का प्रस्ताव है । योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) स्कूलों के लिये समुचित सफाई तथा सुरक्षित जल प्रदाय की व्यवस्था ।

(2) मध्यान्ह का भोजन ।

(3) (क) स्वास्थ्य की जांच, (ख) शारीरिक त्रुटियों का पता लगाना (ग) यथासम्भव इन कमियों का उपचार तथा सुधार करना, (घ) निरापद-करण सहित निरोधी चिकित्सा (ङ) स्वास्थ्य शिक्षा ।

पहली दो बातों के लिये शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है तथा अन्तिम के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय ।

बर्ड एण्ड कम्पनी

*396. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के विरुद्ध न्याय-निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(ख) इस मामले पर अन्तिम फैसला देने में देरी होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या न्याय-निर्णय के सम्बन्ध में कोई व्यादेश (इंजेकशन) जारी किया गया था; और न्यायालय ने उन्हें कब रद्द किया या पक्षों ने कब वापस लिया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) सीमा शुल्क सम्बन्धी न्याय-निर्णय कार्यवाईयां चल रही हैं ।

(ख) लेने देनों की संख्या, उन में लगी अवधि और मामलों की जटिलताओं, पार्टी को जारी किये गये शो काज ज्ञापनों के उत्तर में पार्टी द्वारा दिये गये लम्बे स्पष्टीकरणों

को देखते हुए न्याय-निर्णय सम्बन्धी कार्यवाईयों के पूरा होने में समय की आवश्यकता है । कोई वर्जनीय विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ग) व्यादेश (इंजेक्शन) कलकत्ता के उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये थे । उनको रद्द नहीं किया गया था । तथापि, मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी तथा अन्य सम्बन्धित पार्टियों ने कलकत्ता चे उच्च न्यायालय की इजाजत से अपने अभिवेदन वापस ले लिये ।

Irrigation and Power Problems of Eas tern U.P.

*397. **Shri Bal Krishana Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he toured some of the districts o astern U. P. recently, where the people apprised him of their difficulties arding iiation, power and floods ; and

(b) if so, the major difficulties put before him and whether any scheme to remove the same is under the consideration of Government ?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The people of the area brought the following difficulties to the notice of the Union Minister :

(i) Need for irrigation facilities ;

(ii) Need for remedial measures to counteract ravine formations along the Ganga, encroaching on fertile land ;

(iii) Erosion at Mirzapur and Vindhyachal Ghats ; and

(iv) Shortage of power in rural areas and in Varanasi town.

The Union Minister examined the following measures contemplated in regard to the above :

(i) The U.P. Engineers had framed preliminary proposals for pumping water from the Ganga at Shringmerpurghat, about 20 miles up stream of Allahabad, to a lift canal to irrigate areas in Allahabad, Jaunpur and Varanasi districts, which are at present not irrigated. This scheme was examined and the State Government have been requested to finalise proposals for pumping about 1,000 cusecs to enable annual irrigation of about 200,000 acres. This scheme would roughly cost about Rs. 5 crores.

The Minister also inspected tubewells in the area and examined their performance.

(ii) Terracing work being done in certain areas by the U.P. Government to arrest ravine formations along the course of the Ganga were inspected and the State Government were also advised to take up supplementary works like check dams on large number of nullahs joining Ganga at an early date.

(iii) Some of the Mirzapur and Vindhyachal Ghats are fallen and attacked by the Ganga certain at places. All these are in a bad condition. The others were also inspected. The State Government are already investigating the problem with a view to drawing up a phased programme of anti-erosion works.

(iv) The shortage of power in Varanasi town was reported to be mainly due to short-comings in the distribution system of the private licence at Varanasi. The State Electricity Board was requested to examine measures to improve the position, keeping in view the contract period of the licencee.

The State Electricity Board have also been requested to examine measures to relieve, to the extent possible, the general shortage of power in rural parts of these districts.

बम्बई तथा केरल में फर्मों पर छापे

*398. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री बम्बई तथा केरल की कुछ फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के मामलों सम्बन्धी 10 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पकड़े गये दस्तावेजों की विस्तृत जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख). प्रवर्तन निदेशालय में पकड़े गये कागजातों की अभी विस्तार पूर्वक जांच-पड़ताल हो रही है ।

आयुर्वेदिक कालेज

*399. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सझियान :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री ह० स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में अनेक आयुर्वेदिक कालेजों का दर्जा ऊंचा कर के स्नातकोत्तर तथा गवेषणा संस्थाओं के बराबर लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक केन्द्र को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सह-अनुसंधान संस्थान बनाने के प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली में भी इसी प्रकार की एक संस्था की स्थापना करने की संभावना है। विवरण तैयार किये जा रहे हैं। इसी प्रकार के कार्य के लिए भारत सरकार ने तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पूना में एक स्नातकोत्तर केन्द्र चलाने के लिये भी 130,000 रुपये का एक अनुदान दिया है ।

गर्भ पात को वैध बनाना

*400. **श्री हेम राज :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गर्भपात को वैध बनाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये स्थापित की गई समिति ने क्या प्रगति की है ; और

(ख) क्या समिति देश के जनमत का भी पता लगायेगी और यदि हां, तो ऐसा करने के लिये इसने क्या तरीका अपनाया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). भारतीय दण्ड संहिता तथा कुछ विदेशों के गर्भपात संबंधी कानूनों में गर्भपात के बारे में जो उपबन्ध हैं, समिति ने उनकी जांच कर ली है। समिति का विचार है कि यह समस्या जटिल है क्योंकि इसमें ऐसे चिकित्सीय सामाजिक तथा नैतिक प्रश्न हैं जिन पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है।

समिति ने चिकित्सा, सामाजिक, वैधानिक, धार्मिक संस्थाओं, राज्य सरकारों, संसद सदस्यों तथा प्रेस के विचारों का अध्ययन करने के लिये एक प्रश्नावलि तैयार की है।

सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज

*401. **श्री दी० चं० शर्मा :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बैंक-दर में हुई वृद्धि को ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि में जमा राशियों पर ब्याज की दर बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) . सामान्य भविष्य निधि और अन्य ऐसी निधियों की रकमों के ब्याज की दर हर साल, केन्द्रीय सरकार के उन रुपया-ऋणों की उससे ठीक पहले के पांच वर्षों की औसत परिशोधन प्राप्ति (रिडेम्पशन यील्ड) के आधार पर निर्धारित की जाती है जिनके पकने में पांच वर्ष से अधिक समय बाकी हो । चूंकि इस संदर्भ में बैंक दर की वृद्धि की बात, सिवाय इसके कि परिशोधन-प्राप्ति पर इसका प्रभाव बाद में पड़ सकता है, संगत नहीं है, इसलिए भविष्य निधि की रकमों की पहले से ही निर्धारित की गयी ब्याज की दर में वृद्धि करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

विशेष-ऋण नियंत्रण

969. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि सामग्री सम्बन्धी विशेष ऋण-नियंत्रण से क्या लाभ है ;

(ख) यह नियंत्रण किस प्रकार रखा जाता है ;

(ग) क्या इस प्रकार नियंत्रण करने से कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) गुप्त संचय और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए और इस बात को सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि अनाज और अन्य कृषि पदार्थों का वितरण या विपणन शीघ्र और सुव्यवस्थित रूप से हो, अनाज तथा अन्य कृषि जन्य पदार्थों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर नियंत्रण रखना जरूरी है ।

(ख) बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे इन अग्रिमों के सम्बन्ध में न्यूनतम 'मार्जिन' रखें, और इन अग्रिमों के स्तर को, कुछ पिछले वर्षों की उन्हीं अवधियों में दिये गये अग्रिमों के स्तर को देखते हुए, समय समय पर निर्धारित उच्चतम सीमाओं के अन्दर रखें । आवश्यकता पड़ने पर, 'मार्जिन' और उच्चतम सीमा (सीलिंग) सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण, राज्य सरकारों के लिए अथवा उनकी ओर से स्टाक रखने वालों को या निर्यातकों को, या मालगोदामों (वेयर हाउस) की रसीद के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों या आवश्यकता से अधिक अनाज वाले राज्यों (सरप्लस स्टेट) में दिये जाने वाले अग्रिमों के बारे में अलग अलग किया जाता है । कृषि-पदार्थों के यातायात सम्बन्धी प्रलेखी हुंडियों (डाक्युमेंटरी बिल्स) के आधार पर दिये गये अग्रिमों और माल तैयार करने और विपणन करने वाली सहकारी समितियों (कोआपरेटिव प्रोसेसिंग ऐण्ड मार्केटिंग सोसाइटीज़) को दिये जाने वाले अग्रिमों को प्रायः छूट दी जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सिंचाई तथा जल निकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग

970. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई तथा जल निकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने 1966 में भारत में अपना छटा पूर्ण-अधिवेशन करने का भारत सरकार का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सम्मेलन में कितने विदेशी प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है।

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) केन्द्रीय सिंचाई तथा बिजली बोर्ड, जो कि सिंचाई तथा जल निस्सार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की भारत राष्ट्र समिति के रूप में कार्य करता है, ने सिंचाई तथा जल निस्सार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को अपना छटा पूर्णाधिवेशन भारत में करने के लिये निमंत्रण दिया था। आयोग ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

(ख) यह अधिवेशन नई दिल्ली में 4 जनवरी से 15 जनवरी, 1966 तक होगा। इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सिंचाई तथा बिजली बोर्ड प्रबन्ध कर रहा है।

सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों पर विचार किया जाना है, उनमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं :—

(1) सिंचाई के अन्तर्गत जारी जमीन का कृष्यकरण।

(2) सिंचाई तथा जल निस्सार नालियों में गाद।

(3) डेल्टा क्षेत्रों का विकास।

(4) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और अन्य उद्देश्यों के लिये जलाशयों का अनुकलित चालन।

इसके अतिरिक्त, सिंचाई, जल निस्सार और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में हुए अद्यतन विकास पर विशेष भाषण और वार्तालाप होंगे। शिष्टमण्डलों को इन क्षेत्रों में भारत में हुई प्रगति से अवगत कराने के लिये चार्ट, प्रारूप और नक्शे भी प्रदर्शित किये जाएंगे। तत्पश्चात वे अध्ययन दौरे करेंगे।

(ग) लगभग 400।

मलाबार में बिजली की दर

971. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विद्युत बोर्ड ने केरल के मलाबार प्रदेश में बिजली की दर बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस लिए ; और

(ग) ट्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में यह वृद्धि लागू न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अकेले मालाबार क्षेत्र में बिजली की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु गर्मियों में राज्य के सारे उद्योगों पर, चाहे वे मालाबार क्षेत्र में हों अथवा ट्रावन्कोर-कोचीन क्षेत्र में, 30 प्रतिशत अधिक कर लगाने का एक प्रस्ताव केरल राज्य बिजली बोर्ड के विचाराधीन है ।

(ख) केरल राज्य बिजली बोर्ड मद्रास ग्रिड से लगभग 25 मैगावाट बिजली प्राप्त कर रहा है, ताकि उन्हें गर्मियों में बिजली की कटौती न करनी पड़े । मद्रास राज्य बिजली बोर्ड ने इस सप्लाई के लिए 9.5 पैसे प्रति यूनिट मांगा है । केरल राज्य बिजली बोर्ड अतिरिक्त कर इसलिए लगाना चाहते हैं, ताकि गर्मियों में मद्रास से प्राप्त की गई बिजली की अधिक लागत को पूरा कर सके ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सेवक समाज

972. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **योजना** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 में सरकार ने भारत सेवक समाज को कोई अनुदान मंजूर किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) इस अवधि में भारत सेवक समाज की उड़ीसा शाखा को कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना आयोग अब तक 1964-65 के दौरान, केन्द्रीय भारत सेवक समाज को 11,29,844 रु0 की राशि मंजूर कर चुका है ।

(ग) अनुदान भारत सेवक समाज के केन्द्रीय कार्यालय को मंजूर किया जाता है । केन्द्रीय भारत सेवक समाज 18,000 रुपये उड़ीसा शाखा को भेज चुका है ।

बाढ़ संरक्षण

973 श्री राम हरख यादव : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के हेमवर्ग विश्वविद्यालय ने भारत में बाढ़ संरक्षण सम्बन्धी अपनी जानकारी तथा अनुभव भारत को उपलब्ध करने के लिये भारत से विशेष प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान

974. श्रीमती अकम्मा देवी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 24 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1830 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आल इण्डिया इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साईन्सेस, नई दिल्ली के प्रशासन सम्बन्धी अधिकारियों के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही को पूरा करने में आगे क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के प्रशासन सम्बन्धी अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्रवाई में हुई प्रगति इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम तथा पद	हुई प्रगति
1.	श्री के० सी० ढींगरा, भूतपूर्व प्रशासन अधिकारी	श्री के० सी० ढींगरा के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के अध्यक्ष ने उन्हें सेंसर का दण्ड दिया है ।
2.	श्री टी० एस० सोढी, अधीक्षक	श्री सोढी के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच पूरी हो चुकी है तथा जांच अधिकारी की रिपोर्ट विचाराधीन है । शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जायेगा ।
3.	श्री जी० एल० चोपड़ा, एल०डी०सी०	विशेष पुलिस ने इस मामले में छान-बीन शुरू कर दी है । उसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति की बैठक

975. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की 'उद्योग, बिजली तथा परिवहन' सम्बन्धी समिति की बैठक हाल में नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की 'उद्योग, बिजली तथा परिवहन' सम्बन्धी समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं । पहली प्रारंभिक

बैठक 2 जनवरी, 1965 को हुई । दूसरी बैठक उद्योग और परिवहन पर विचार-विमर्श करने के लिए 23 फरवरी, 1965 को हुई । समिति की आगामी बैठक 15 और 16 मार्च, 1965 को होने वाली है ।

(ख) निम्नलिखित मुख्य विषयों पर विचार किया गया :

(1) उद्योग :

1. पिछड़े क्षेत्रों के विकास सहित उद्योगों की स्थिति तथा छितराव सम्बन्धी नीति,
2. निजी क्षेत्र परियोजनाओं में राज्य का भाग,
3. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं में उद्योगों की व्यवस्था करना,
4. चौथी पंचवर्षीय योजना की राज्य योजनाओं में उद्योगों की व्यवस्था करना,
5. सहकारी औद्योगिक उद्यमों का विकास, और
6. राज्य और निजी क्षेत्र परियोजनाओं की संस्थागत वित्तीय व्यवस्था ।

(2) बिजली :

1. टैक्नोलोजी के क्षेत्र में नवीनतम विकासों का उपयोग ।
2. निर्माण, कार्य संचालन और रखरखाव के लिए राज्यों से केन्द्र द्वारा बड़ी बिजली परियोजनाओं को लेना ।
3. राज्य बिजली बोर्डों के कामों से सम्बन्धित समिति (वैंकटारमण समिति प्रतिवेदन) की सिफारिशों पर विचार ।
4. चौथी योजना में बिजली निर्माण क्षमता का परिमाण ।
5. क्षेत्रों के औद्योगिक और कृषि विकास की क्षमता के अनुसार, ग्रामीण बिजलीकरण ।
6. बिजली बोर्ड द्वारा बंद खानों से कोयला निकालना ।

(3) परिवहन :

1. समेकित परिवहन का जाल बिछाने के लिए (1966–76) दीर्घकालीन योजना की तैयारी ।
2. सीमा क्षेत्रों की आवश्यकताओं सहित राज्य परिवहन योजनाओं की गुंजाइश ।
3. देश भर में समस्त सड़क विस्तार पर समेकित दृष्टिकोण अपनाना ।
4. ग्रामीण सड़कों के कार्यक्रम को कृषि उत्पादन कार्यक्रमों तथा हाट-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम और सम्बद्ध क्षेत्रों से संयोजित करना ।
5. सड़क परिवहन के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र कार्यक्रमों की गुंजाइश ।
6. निजी परिवहन उद्योग के लिए संस्थागत और अन्य वित्तीय व्यवस्था ।
7. प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य तथा छोटी पत्तनों के विकास की योजनाओं का समन्वय ।

(ग) समिति ने अभी अपने विचार-विमर्श समाप्त नहीं किये हैं। इस समिति के सुझावों और सिफारिशों पर, राष्ट्रीय विकास परिषद् की अन्य समितियों के सुझावों और सिफारिशों के साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद् की विशेष बैठक में विचार किया जायेगा ।

स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन

976. **श्री सुरेंद्रपाल सिंह :**
श्री र० गि० दुबे :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, हां ।

(ख) यह विषय अभी विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गयी सहायता

977. **श्री सुरेंद्रपाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 1000 नलकूप लगाने के लिये विश्व बैंक के सम्बद्ध निकाय अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में केन्द्र की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के लिये अपेक्षित सहायता प्राप्त करने के लिये केन्द्र ने प्रयास किया है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ; लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के नलकूप लगाने के कार्यक्रम के दूसरे दौर के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की आयोजनाओं की कुछ जानकारी विश्व बैंक के उस दल को दी गयी थी, जो हाल में भारत आया था। बैंक की प्रतिक्रिया की प्रतीथा की जा रही है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जायगी ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

स्थानीय योजनाओं की क्रियान्विति सम्बन्धी प्रशिक्षण

978. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **योजना** मंत्री 1 अक्तूबर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्थानीय योजनाओं के आयोजन तथा कार्यान्विति के सम्बन्ध में शिक्षा-शास्त्रियों तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यह योजना अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पालम, नई दिल्ली पर सोने का तस्कर व्यापार

979. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सेवक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने 20 दिसम्बर, 1964 को पालम, नई दिल्ली पर 4 लाख रुपये का सोना पकड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई जांच-पड़ताल का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० ति० कृष्णमाचारी) : (क) 20 दिसम्बर, 1964 को पालम हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों ने एक व्यक्ति से जो विदेश से आया था 47.675 किलोग्राम वजन की कुछ धातु सम्बन्धी वस्तु, जिस पर सोना होने का संदेह था, 19 ग्राम बजनी पासा सोना और 3 ग्राम बजन का प्लेटिनम तार पकड़ा था। मुल्य सोने की वास्तविक मात्रा पर आधारित होगा परन्तु मोटे तौर पर इसका अनुमान 1.6 लाख रुपये लगाया जाता है ।

ख) मामले की जांच अभी चल रही है

तस्करों की गिरफ्तारी

980. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री दिगे :
श्री चांडक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1964 से 31 जनवरी, 1965 की अवधि में सीमा शुल्क अधिकारियों ने भारत में कुल कितने तस्करों को गिरफ्तार किया ;

(ख) उनमें से कितनों के विरुद्ध दोष सिद्ध हुए ;

(ग) उनके कब्जे से कितने मूल्य का सामान प्राप्त हुआ ; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिजली की कीमत.

981. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 26 दिसम्बर, 1964 को भारत में बिजली उपक्रमों की फीड्रेशन में दिये गये अपने भाषण में यह सलाह दी थी कि वे कार्य-संचालन संबंधी कुशलता द्वारा तथा अधिक तकनीकी दक्षता से विद्युत् पारेषण में होने वाले अपव्यय को कम कर के बिजली की कीमत कम करें।

(ख) यदि हां, तो इससे कीमत कितनी कम की जा सकती है, और

(ग) फीड्रेशन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क). मैंने भारतीय बिजली उपक्रम संघ को उनकी बम्बई में 26-12-64 को हुई 20वीं वार्षिक साधारण बैठक में सलाह दी थी कि उत्तम परिणामों के लिये अर्वाचीन तकनीकी विकास को प्रयोग में लाकर इष्टतम दक्षता लाने के वास्ते गैर सरकारी सेक्टर के उपक्रमों को आधुनिक समय के अनुसार ढालना आवश्यक है । मैं ने यह भी सुझाव दिया था कि संघ को चाहिये कि वे इस मामले पर विचार करने के लिये एक समिति स्थापित कर लें ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस सुझाव पर संघ की प्रतिक्रिया अनुकूल ही थी ।

भारत-पाकिस्तान बाढ़ नियंत्रण योजना

982. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी भारत में बाढ़ की रोक-थाम करने के लिए संयुक्त भारत-पाक योजना बनाई जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस का ब्यौरा जानने का कोई प्रयत्न किया गया है, और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) भारत और पाकिस्तान के बीच अगस्त, 1956 में हुए समझौते के परिपालन में हम पूर्वी पाकिस्तान को वहां की बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को तैयार करने के लिये मानसून ऋतु में निम्नलिखित सूचनाएं पहले से ही दे रहे हैं :—

(1) बिहार, असम, और त्रिपुरा के केन्द्रों से बाढ़ चेतावनियां,

(2) शिलांग से असम तक भारी वर्षापात आंकड़े,

(3) ब्रह्मपुत्र घाटी के सम्बन्ध में मांगी गई कोई अन्य सूचना अथवा यथा आवश्यक दूसरी सहायता ।

ग्रांड होटल, शिमला

983 **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रांड होटल, शिमला की कार्यप्रणाली का पुनर्गठन हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) पुनर्गठन की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) अपने ग्राहकों को ठहराने और खाने की ओर अधिक अच्छी सुविधायें देने के लिये तथा उसे और अधिक अच्छी आर्थिक स्थिति पर लाने के लिए ।

(ग) होटल को दो भागों में विभाजित कर दिया जायेगा । उनमें से एक का नाम होगा "होली डे होम" । यह शिमला घूमने जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए रिजर्व रहेगा । इस भाग के कमरों के साथ एक छोटी रसोई और गर्म पानी की व्यवस्था होगी । दूसरा भाग किसी होटल वाले को पट्टे पर दे दिया जायेगा जो कि इसे होटल के रूप में चलायेगा ।

सोने का निजी व्यापार

श्री स० मो० बनर्जी :
984. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री चुनी लाल :
श्री हेडा:
श्री राम पुरे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने सोने के निजी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने तथा सुनारगिरी को कुटीर उद्योग के रूप में मान्यता देने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने मांग की है कि सरकार को सोने का आयात करना चाहिये और सरकारी एजेंशियों के द्वारा कारीगरों तथा जनता को सोना बांटना, सुनारगिरी को कुटीर उद्योग के रूप में मान्यता देना और उसके विकास इत्यादि के लिए समस्त जिम्मेदारियां उठानी चाहिये।

(ख) इन मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है क्योंकि वे सोने के आयात का पूर्वानुमान करती है जिसके लिए देश क्षमता नहीं रखता।

गांव का विद्युतीकरण

985. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांव का तेजी से विद्युतीकरण करने की योजना कार्यान्विति के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जायेगी ;

(ख) इस योजना का ठीक-ठीक ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय होगा;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस बारे में प्रस्ताव भेज दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो आसाम सरकार से प्राप्त हुए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) यथार्थ ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। फिर भी, भारत सरकार की यह नीति होगी कि कृषि उपज में वृद्धि लाने के निमित्त उत्थान सिंचाई के लिए पम्पों को बिजली देने के वास्ते बनाई गई स्कीमों को प्राथमिकता दी जाये।

(ग) छः राज्यों से, जिनमें असम भी सम्मिलित है, स्कीम रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं।

(घ) असम राज्य बिजली बोर्ड ने 1965-66 वर्ष के दौरान 96 लाख रुपये की अनुमति लागत पर 260 ग्रामों में बिजली लगाने की एक स्कीम प्रस्तुत की है। आगामी वर्षों के लिए स्कीम रिपोर्टें उचित समय में ही प्राप्त हो जाएंगी, ऐसी सम्भावना है।

नई दिल्ली में पुराने सरकारी क्वार्टर

986. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पहले उच्च स्तर पर यह निर्णय किया था कि नई दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र में उन पुराने सरकारी क्वार्टरों और बंगलों के स्थान पर जिनकी मियाद पूरी हो गई है, नये भवनों का निर्माण किया जाये और पुराने भवनों की मरम्मत और नवीकरण पर व्यर्थ व्यय नहीं किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के अनुसरण में इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस नीति सम्बन्धी निर्णय के होते हुए भी अनेक पुराने भवनों की मरम्मत और नवीकरण किया गया है और किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन नवीकरणों पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है और आगे के लिए मरम्मत के कितने काम की मंजूरी दे दी गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ). डी० आई० जेड० एरिया के पुनर्विकास के किसी भी प्रस्ताव के विचार से पहले सरकार इस एरिया के पुराने मकानों की भारी मरम्मत करने और उनका नवीकरण करने का अनुमोदन कर चुकी थी। जब कभी इस प्रयोजन के लिए मकान खाली हो सके, इस प्रकार का कार्य किया गया। लगभग 1962 के अन्त तक इस एरिया के पुनर्विकास की प्रथम प्रावस्था स्वीकृत हुई थी। पंचकुईयां रोड पर 611 क्वार्टर तोड़े गये थे और उस स्थान पर टाईप 1 के 720 क्वार्टरों को बनाना शुरू किया गया था। इनमें से अधिकांश क्वार्टर तैयार हो चुके हैं और आवंटित किये जा चुके हैं। इसके बाद के पुनर्विकास की प्रावस्था की योजनायें बनायी जा रही हैं ।

पुनर्विकास के कार्यक्रम के प्रसंग में भारी मरम्मतों औरन वीकरण को ोक दिया गया है सामान्य रूप से अब डी० आई० जेड० एरिया में और किन्हीं मकानों का नवीकरण न ीं किया ज रहा है ।

Treatment of Shri B. K. Dutt

987. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri B. K. Dutt, an associat of great martyr, Sardar Bhagat Singh, is at present undergoing treatment in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi ;

(b) if so, whether Government have issued any instructions to authorities of the Institute for his proper care ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) & (b). Yes.

(c) Does not arise.

Goldsmiths

988. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Miniser of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 63,000 goldsmiths became jobless after the enrforcement of the Gold Control Order ;

(b) if so, whether the Government contemplate to provide them with alternate employment ; and

(c) the number of goldsmiths provided with alternate employment so far ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) About 2,70,000 goldsmiths were affected as a result of the Gold Control Order.

(b) & (c). By virtue of the Defence of India (Ninth Amendment)mi Rules, 1963, 2,28,000 persons have resumed their professions ascertified goldsmiths. 46,000 have been sanctioned loans to take up alternative occupations, 11,000 given employment through Employment Exchanges and 8,000 provided with other employment assistance. The numbers thus settled in other occupations include those who had applied for certificates.

Search of Film Director's House at Amroha

989. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at Amroha Government officials searched the house of a film director of Bombay named Shri Kamal Amrohi ; and

(b) if so, the result thereof ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir.

(b) Some papers were seized, and are being examined.

उपभोक्ता वस्तुएं

990. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की अपेक्षा 1965 में फुटकर व्यापार के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के संभरण में कितनी वृद्धि होने की आशा है ; और

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं और वृद्धि का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) इस के साथ एक विवरण संलग्न है जिसमें कुछ ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि में 1965 में होने वाली अनुमित वृद्धियों का ब्योरा दिया है, जिनके सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं। ये अनुमान अस्थायी हैं और वर्तमान जानकारी पर आधारित हैं। आशा है कि अनाज की उपलब्धि की स्थिति में काफी सुधार हो जायगा, लेकिन 1964-65 के मौसम के कुल उत्पादन के अनुमित आंकड़े कुछ समय बाद ही प्राप्त होंगे।

विवरण

	इकाई	1964 (अनुमान)	1965 (सम्भावनाएं)	1964 की तुलना में 1965 में होने वाली लगभग प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
चीनी	लाख पेट्रिक टन	23	27	16
सूती कपड़ा	लाख मीटर	71320	75000	+ 5

1	2	3	4	5
बनास्पती	हजार मेट्रिक टन	360	400	+11
साइकिलें	हजार	1384	1600	+15
बिजली के पंखे	हजार	1112	1300	+17
रेडियो संग्राहक	हजार	466	550	+18
बिजली के लैम्प	लाख	700	740	+ 6
कागज और गत्ता	हजार मैट्रिक टन	490	525	+ 7

दिल्ली में चूहे तथा ऐसे जीव-जन्तु

991. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में चूहे तथा ऐसे ही अन्य जीव-जन्तु बहुत अधिक मात्रा में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस खतरे को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और नागरिकों को इस खतरे का प्रभावी ढंग से सामना करने में क्या सहायता दी जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) घरेलू चूहों के विरुद्ध स्थानीय निकायों तथा खेतों के चूहों के विरुद्ध खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एण्ड स्टोरेज निदेशालय के द्वारा उपाय किये जा रहे हैं । विभिन्न प्राधिकारों द्वारा बरते गये उपाय इस प्रकार हैं :--

(1) दिल्ली नगर निगम--

चूहों के उत्पात के नियंत्रण में लगा स्टाफ टोलियों में काम करता है । हर टोली में एक चूहा टोली-जमादार तथा तीन चूहा टोली कुली होते हैं । निगम क्षेत्रों में इस समय ऐसी 23 चूहा टोलियां काम कर रही हैं । चूहों को चूहे दानियों में पकड़ा जाता है । यह स्टाफ चूहों को मारने के लिए सायन गैस तथा विषाक्त गोलियों (बैट्स) का प्रयोग भी करता है । 1964 में 481656 चूहे पकड़े गये ।

2) नई दिल्ली नगरपालिका--

इस कार्य के लिए नियुक्त 21 चूहे पकड़ने वालों के जरिये नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों को निःशुल्क चूहेदानियां तथा विषाक्त गोलियां (बैट्स) दी जाती हैं ।

(3) **दिल्ली छावनी बोर्ड**—

इस क्षेत्र में मकानों के अन्दर चूहेदानियों तथा गोलियां देने और बाहर चूहों के बिलों में सायनों गैस देने के उपाय काम में लाये जा रहे हैं।

डाइरक्टोरेट आफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एण्ड स्टोरेज—

बोये हुये खेतों में चूहों के विनाश का काम दिल्ली प्रशासन का कृषि विभाग करता है। डाइरेक्टोरेट प्लांट प्रोटेक्शन क्वारण्टाइन चूहे मारने के विष तथा उपकरण देकर इस काम में दिल्ली प्रशासन की सहायता करता है। यह निदेशालय बाटिकाओं में चूहों के नियंत्रण का कार्य भी करता है।

I. T. Office, Kotah

992. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that an Income-tax office is functioning at Kotah in Rajasthan ;

(b) if so, the break-up of the tax collected during the period from 1960 to 1964 ;

(c) whether it is also a fact that this office is situated in a rented building and the accommodation there is not sufficient ;

(d) whether it is also a fact that land has already been purchased for the building of this office ; and

(e) if so, the reasons for delay in the construction of the building ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir.

(b)

Assessment year	Tax (Figures in thousands)
	Rs.
1960-61	2,026
1961-62	2,028
1962-63	1,967
1963-64	3,840

(c) Yes, Sir, but the accommodation in the rented building is sufficient according to the austerity standards laid down by the Government of India.

(d) Yes, Sir.

(e) In view of the present emergency and need for economy in civil expenditure it has been decided to postpone for the present the construction of Income-tax Office building at Kotah.

Housing for Delhi Washermen

993. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri S. M. Banerjee
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have constituted a special committee for the solution of the housing problem of the washermen in the Capital ; and

(b) if so, when the Committee will submit its report ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) The Committee is likely to submit its report within 2-3 months.

दिल्ली में गन्दी बस्ती हटाने की योजना

994. **श्री हेडा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामा मस्जिद, दिल्ली के पास मटिया महल की गन्दी बस्ती को साफ करने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उस पर कितना धन व्यय होगा ;

(ग) क्या वहां के रहने वालों के पुनर्वास के लिये कोई लक्ष्य नियत किया गया है ; और

(घ) इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (घ). मटिया महल क्षेत्र के लिए गन्दी बस्ती हटाने की कोई विशेष योजना नहीं है। फिर भी मटिया महल रोड के साथ लगी हुई निम्नांकित दो सम्पत्तियों के पुनर्विकास का कार्यक्रम है :—

(1) दुजाना हाउस ; और

(2) हवेली सदर-ए-सदूर ।

उपर्युक्त (1) प्रायोजना में 12.45 लाख रुपयों की अनुमानित लागत के 116 छोटे दो कमरे वाले टैनेमैन्ट्स, 12 दो कमरे वाले बड़े मकान, 24 दूकानें, 6 स्टाल और 18 कार्यालयों के निर्माण का कार्य शामिल है। दो कमरे वाले 40 छोटे टैनेमैन्ट्स तैयार हो चुके हैं और उन टैनेमैन्ट्स में उस क्षेत्र के 40 परिवार फिर बसा दिये गये हैं। प्रायोजना के शेष भाग का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है ।

उपर्युक्त (2) प्रायोजना में 8.48 लाख रुपयों की अनुमानित लागत में 72 टैनेमैन्ट्स और एक फायर स्टेशन का निर्माण कार्य शामिल है। इस प्रायोजना का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ ।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टर

995. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री राम हरख यादव :
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 17 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1488 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम कालोनी, नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्मित सरकारी क्वार्टरों में जल तथा विद्युत् जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस समय कितने क्वार्टर और दुकानें बन रही हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) रामकृष्णपुरम में 4,836 मकान तैयार हो चके हैं और उनमें बिजली, पानी आदि सुविधाओं की व्यवस्था की जा चकी है ।

(ख) 1 मार्च, 1965 को 4,129 क्वार्टर और 74 दुकानें निर्माणाधीन थीं ।

मध्य प्रदेश में आवास कार्यक्रम

996. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री उइके :
श्री राघेलाल व्यास :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है ; और

(ख) यदि हां, तो आवास कार्यक्रमों में कमी को पूरा करने के लिये विशेष सहायता देने के बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना : (क) और (ख) आवास योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था करने और साथ ही साथ उनका उपयोग करने में मध्य प्रदेश का स्थान आठवां है । राज्य ने अपनी तीसरी योजना में 500 लाख रुपयों की व्यवस्था की थी, जिसमें से प्रथम तीन वर्षों में 191,83 लाख रुपयों का उपयोग किया जा चुका है ।

कलकत्ता बन्दरगाह पर छिद्रण उपकरण की निकासी

7. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया था कि जनवरी, 1965 में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा निकासी दिये जाने में देर होने के कारण बहुमूल्य सामान, पुर्जे और अन्य सामग्री जिसकी कैनिंग बन्दरगाह और रुद्रसागर (आसाम) में तेल का पता लगाने और इसके लिये खुदाई करने के लिये अविलम्ब आवश्यकता थी, कलकत्ता बन्दरगाह में रुकी पड़ी रही ;

(ख) क्या उन्होंने इसके कारणों की जांच करके यह निश्चय किया है कि इसके लिये कौन उत्तरदायी है ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की देरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). जी, हां । पूछताछ करने से पता चला कि कथित वस्तुओं की निकासी में देरी के लिये कलकत्ता के सीमा-शुल्क प्राधिकारी उत्तरदायी नहीं थे । उत्तरदायित्व उन एजेंसियों का है जिनको तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने निकासी का कार्य सौंपा है । आयोग इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार कर रहा है ।

दिल्ली में फिलोसोफीकल हाल के लिए भूमि

998. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दिल्ली में एक फिलोसौफीकल हाल बनाने के लिये भूमि के आवंटन के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख). शिवानुभव समिति नई दिल्ली से, शिवानुभव मंडप, एक पुस्तकालय और एक गेस्ट हाउस को बनाने के लिए भूमि के आवंटन का अनुरोध प्राप्त हुआ है । 30 जनवरी 1965 को समिति से इस प्रस्ताव का विस्तृत विवरण निर्धारित प्रोफार्मा पर मांगा गया था । उसका अभी तक इन्तजार है ।

गोल मार्केट इलाका, नई दिल्ली

99. **श्री वाजी :**
श्रीमती विमला देवी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के गोल मार्केट के इलाके के विभिन्न स्वदायरों के रिहायशी भू-खंडों में रामलीला करने के लिए भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा भूमि किराया वसूल किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्षों में दशहरे के त्यौहार के अवसर पर रामलीला करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि का कोई किराया वसूल नहीं किया जाता था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले दो या तीन वर्षों में अपनी नीति बदल दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों से धार्मिक कार्यों के लिये अपने भू-खण्डों का प्रयोग करने के लिये भूमि विकास कार्यालय द्वारा भूमि का किराया क्यों वसूल किया जा रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) सरकारी भूमि का उपयोग करने के लिए, किराया / हानि सामान्य नीति के अनुसार वसूल किये जाते हैं । यह मामला भी उसी नीति के अधीन है । फिर भी ऐसे मामलों में मामूली खर्चे वसूल किये जाते हैं ।

घटिया थर्मामीटर

1000. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में घटिया थर्मामीटरों की बिक्री रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है और उस का क्या परिणाम हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). भारतीय मानक संस्था इस समय क्लीनिकी थर्मामीटरों के मानक तैयार करने में लगी हुई है । जब ऐसे मानक तैयार हो जायेंगे तो ऐसे थर्मामीटरों पर गुण नियंत्रण लागू करना सम्भव हो जायगा ।

विश्वबैंक के कर्मचारियों की यात्रा

1001. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के कर्मचारी भारतीय अर्थ व्यवस्था की समस्याओं का मूल अध्ययन करने के लिये जनवरी, 1965 में भारत आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) माननीय सदस्य का संकेत स्पष्टतः विश्व बैंक के उप-प्रधान, श्री ज्योफ्रे विल्सन तथा बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी, डाक्टर एल्डरवेरल्ड की यात्राओं से है । उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत की अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं का विशेष रूप से अध्ययन करना नहीं था, बल्कि वे यात्राएं बैंक द्वारा भारत को उल्लेखनीय मात्रा में ऋण दिये जाने के कारण, विश्व बैंक के कार्यों के सम्पादन के अन्तर्गत की गयी थीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

राजस्थान में परिवार नियोजन

1002. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से परिवार नियोजन की कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बारे में कोई निर्णय हो गया है और वह क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां। परिवार नियोजन कार्यक्रम के पुनर्गठन के लिये राजस्थान सरकार ने नवम्बर 1964 में 1.09 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत की निम्नलिखित योजना प्रस्तुत की है :—

1. 45 नगर परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना ।
2. 175 ग्राम परिवार नियोजन संस्थाओं की स्थापना ।
3. जिला परिवार नियोजन कार्यालयों की स्थापना ।

(ख) भारत सरकार ने इस योजना को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया था और राजस्थान सरकार को जनवरी, 1965 में सूचित किया था कि उन्हें इस योजना को शुरू कर देना चाहिये तथा उन्हें इस कार्य के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जायेगी ।

पंजाब से दिल्ली के लिये पानी

1003. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब से दिल्ली के लिये पानी देने के बारे में की जा रही बातचीत असफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस विवाद को निपटाने के लिये कुछ विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

चौथी योजना के लिये रूस से सहायता

1004. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कोला वैकैया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये सोवियत सहायता की भारत की आवश्यकताओं के बारे में रूस सरकार को अवगत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो रूस सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए सहायता देने के बारे में रूस सरकार के अधिकारियों के साथ सामान्य बातचीत हुई है और यह मामला अब भी प्रारम्भिक अवस्था में है ।

Tax Evaders

1005 Shri D.N. Tiwary : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that fifty to sixty thousand tax evaders have been detected during the recent income tax drive ;

(b) if so, the number of persons out of them who had been served notices to submit returns ; and

(c) the income likely to be accrued thereby ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) 1 जनवरी, 1964 से लेकर 31 दिसम्बर 1964 तक की अवधि में 6,11,794 नये कर निर्धारितियों का पता लगा है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितना जल्दी हो सकेगा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) जब तक कि कर निर्धारण का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक इस सूचना का पता नहीं चल सकता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1006. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963-64 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुनाफों में कोई उल्लेखनीय बढ़ोत्री हुई है ; और

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के समवायों के औसत मुनाफे की तुलना में ये मुनाफे कैसे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां ।

(ख) इस तरह की तुलना सम्भव नहीं है ।

छोटे नगरों की समस्यायें

1007. श्री हेमराज :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में छोटे नगरों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये स्थापित की गई समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें/सुझाव दिये गये हैं तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी, हां । रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जा रही हैं ।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी०–3967/65]।**

रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों को उन सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिये भेज दी गई है जिनसे उनका सम्बन्ध है ।

अफीम का तस्कर व्यापार

1008. **श्री उ० मु० त्रिवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उज्जैन के तस्कर-व्यापार करने वाले एक गिरोह को, जो जिला मंडसौर में नीमच के समीप एक गांव से चोरी-छिपे अफीम ले गया था, हाल ही में जबलपुर के निकट गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 30 दिसम्बर, 1964 को जबलपुर में तीन तस्करों का एक गिरोह पकड़ा गया था जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता था कि वह गिरोह उज्जैन से आया था, लेकिन जिस स्थान से अफीम चोरी-छिपे लायी गयी थी उसका निश्चय नहीं हो पाया है ।

(ख) इस मामले में सभी अभियुक्तों को और पकड़े गये सामान को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

चौथी योजना

1009. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** :
श्री वाजी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना का कुछ पश्चिमी और पूर्वी देशों की विकास योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है और इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या किसी देश ने सरकारी या गैर-सरकारी स्तर पर स्वयं अपनी समस्याओं को हल करने के लिये ऐसा सामंजस्य स्थापित करने का सुझाव दिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग). उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की सोलहवीं बैठक 28 फरवरी, 1965 को नई दिल्ली में हुई । इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि पश्चिमी तथा पूर्वी देशों के योजना प्राधिकारियों ने सुझाव दिये थे कि पारस्परिक हित में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से उनमें तथा योजना आयोग में भावी

विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अधिक विचार-विमर्श होना चाहिये । इससे यह लाभ होता कि हमें पहले ही मालूम हो जाता कि कौनसा देश क्या करने जा रहा था तथा हमारी योजनाएं क्या थीं । उनकी परिकल्पना के अनुसार आगामी वर्ष या इससे आगे अनुभव प्राप्त करने के लिए चार या पांच देशों के साथ इस प्रकार का काम करने में प्रगति करनी संभव होगी ।

उड़ीसा में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें

1010. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितनी ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं चालू हैं ; और

(ख) 1964–65 में इस प्रयोजन के लिए केन्द्र ने उस राज्य को कितनी राशि दी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) दो ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं यानी बारपली और जजपुर, इस समय उड़ीसा राज्य में काम कर रही हैं ।

(ख) दो ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा उड़ीसा राज्य को 1964–65 के दौरान दस लाख रुपये आवंटित किये गये हैं ।

विदेशी व्यापार संस्थानों को दी गई रायल्टी

1011. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964–65 में अब तक सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा विदेशी व्यापार संस्थानों को कुल कितनी रायल्टी दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): विदेशी व्यापार संस्थानों को रायल्टी के रूप में भेजी गई राशि के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु वे व्यापार चिन्ह के प्रयोग, प्रतिलिप्यधिकार, मशीनों के लिये किरायों आदि के लिये भुगतान सम्बन्धी आंकड़ों में सम्मिलित हैं । विदेशी व्यापार संस्थानों को अप्रैल-सितम्बर, 1964 की अवधि में, जिसके बारे में जानकारी उपलब्ध हैं, इन भुगतानों के लिये लगभग 1.8 करोड़ रुपये भेजे गये जिसमें रायल्टी भी सम्मिलित है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1012. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें 1964–65 में तीन महीने से भी अधिक समय तक डाक्टर नहीं थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जानकारी दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० -3968/65]

प्रबन्ध अभिकरण

1013. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964-65 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामलों में प्रबन्ध अभिकरणों की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी गई तथा कितनों में नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : 1-4-1964 से 28-2-1965 तक की अवधि के दौरान 33 मामलों में विद्यमान प्रबन्ध अधिकर्ताओं की अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई जब कि 40 मामले अस्वीकृत कर दिए गए ।

छात्रों को विदेशी मुद्रा

1014. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में विदेशों में अध्ययन करने के लिये कुल कितने छात्रों को विदेशी मुद्रा दी गई ;

(ख) उक्त अवधि में उन्ह कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ; और

(ग) क्या उक्त अवधि में किन्हीं छात्रों को विदेशी मुद्रा नहीं दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) 1964 में 6628 छात्रों को विदेशी मुद्रा दी गयी । इसमें उन 3338 छात्रों को दी गयी आवर्तक अनुमतियां (रिपीट पर्मिट) भी शामिल हैं, जो पहले ही विदेश जा चुके थे ।

(ख) जारी की गयी विदेशी मुद्रा की रकम 452 लाख रुपया थी ।

(ग) जी हां ।

Malpractice in Companies

1015 **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that inexperienced sons and other relatives of Industrialists coming out of schools and colleges, are appointed in some of Companies on very high salaries and their salaries exceed the salaries of even sufficiently experienced and old Directors ; and

(b) if so, the action being taken by the Company Law Department to check and regulate the appointment of relatives of Industrialists in Companies?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) and (b). In certain types of cases, *e.g.*, in regard to associates of Managing Agents, or for the initial appointment of a Managing or a whole-time Director prior approval of Government is necessary under the Companies Act. In such cases, Government see to it that appoinstmetn of the type referred to are not allowed. The Companies Act also provides that the previous consent of the company to be accorded by a special resolution should be obtained for a partner or a relative of a Director to hold an office of profit. In such cases, the shareholders, presumably exercise the required check. In other cases, where neither the prior approval of Government nor the approval of the shareholders is necessary, the possibility of such undesirable appointments does exist. Government have no general information as to the prevalence of such undesirable practices, but Government do enquire into specific instances when such cases come to their notice.

Commission on Sale of Industrial Products

1016. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have made a study of the commission or share accruing to the middlemen such as agents, sub-agents or sale agencies in the sale of industrial products/agricultural products ;

(b] if so, whether this study has revealed that prices of these goods are shooting up on account of large share of profit accruing to the selling agents ; and

(c) if not, whether Government have any proposal under consideration to undertake such a study in the context of the present rise in prices ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

Study of Comparative Production Cost

1017 { Shri Madhu Limaye : / Shri Kishen Pattnayak : / Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted a comparative study of the costs and prices of goods produced by large industrial units of India and of such goods produced by industrial units of Japan, Italy, West Germany and other developed countries ; and

(b) if so, the mesaures that Government propose to adopt to reduce the gap between our economy of higher cost-higher price and the economy of lower cost-lower price of developed countries ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) No single study of the kind indicated has been prepared. The Tariff Commission examines, from time to time, costs of representative units in industries which have applied for or have been granted tariff protection, or prices of whose products are to be fixed by Government. In this connection, the commission compares, wherever necessary, the costs and prices of goods manufactured in India with the landed costs of goods imported from other countries.

(b) The measures so far taken to reduce costs include assistance to the old established industries for modernisation, helping new industries to attain optimum scales of production and encouraging productivity consciousness, among other things, through the agency of the National Productivity Council. Government is also regulating the prices of some manufactured products. These efforts will continue.

"आस्टरमिल्क" में जीवित कीडों का पाया जाना

1018. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक समाचारपत्र की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि बम्बई में ग्लैक्सो के 'आस्टरमिल्क' में जीवित कीड़े पाये गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में बम्बई नगर निगम से रिपोर्ट मांगी । निगम से प्राप्त सूचना से मालूम हुआ कि राज्य सरकार द्वारा 1 दिसम्बर, 1964 को की गई छान-बीन से पहले ओस्टरमिल्क में जीवित कीड़े पाये जाने की कोई सूचना अथवा शिकायत उन्हें नहीं मिली थी । बम्बई नगर निगम के खाद्य निरीक्षक ने 2 दिसम्बर 1964 को बाजार का निरीक्षण किया । किन्तु उसे उस दुकान में जहां से ओस्टर मिल्क का वह डिब्बा खरीदा गया बताया गया था अथवा किसी दूसरी दूकान में बैच (सं० 731) जिसके बारे में शिकायत की गई थी, अथवा किसी दूसरे बैच का कोई स्टाक नहीं मिला । ग्लैक्सो लेबोरेटरीज़ में भी उसे इस बैच का कोई स्टाक नहीं मिला । पूछताछ के बाद खाद्य निरीक्षक को मालूम हुआ कि बेबी फूड की बढ़ती हुई मांग तथा निर्माताओं द्वारा उसकी कम पूर्ति के कारण जो माल आया था वह सब समाप्त हो गया था । अतः बैच सं० 731 के ओस्टरमिल्क के किसी नमूने की जांच करना सम्भव नहीं हुआ । किन्तु वह ग्लैक्सो लेबोरेटरीज़ बैच सं० 805 का एक नमूना ले सका जो कि विश्लेषण के बाद खाने योग्य पाया गया । ग्लैक्सो लेबोरेटरीज़ ने यह भी बताया कि उन्हें बैच सं० 731 के अनेक खरीदारों में से जिन्हें इस बैच के सैकड़ों डिब्बे बाजार में बेचे गये थे किसी भी दूसरे खरीदार से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली ।

विदेशों में प्रदर्शनार्थ भेजे जने वाली चल चित्रों की जांच के लिए बोर्ड

1019. **श्री रा० बरुआ** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में प्रदर्शनार्थ भेजे जाने वाले चलचित्रों की जांच करने के लिये

बोर्ड बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये अब तक कितने बोर्ड बनाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में एक एक ।

भूमि सुधार

1020. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में भूमि प्रणाली सम्बन्धी अमरीकी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) .श्री लेडजिस्की की रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। उसमें से जो सुझाव दिये हैं उन पर स्थानीय हालतों और आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकारें उचित विचार कर रही हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि

1021. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से अधिक ऋण मिलने का कोई संकेत मिला है ; और

(ख) क्या हमारी विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण रिजर्व की कमी को देखते हुए ऋण-व्यवस्था (सर्विसिंग) करने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से कोई रियायत मिलने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). मैंने पिछले महीने की 17 तारीख को इस सभा में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति के बारे में जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने सभा को यह सूचित कर दिया था कि मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के बोर्ड के अपने कार्यकारी निदेशक को उस संस्था से यथासंभव अधिक से अधिक आपाती ऋण (स्टैण्ड बाई क्रेडिट) देने का अनुरोध करने का अधिकार दिया है । इस अनुरोध के फलस्वरूप अब निधि से बातचीत चल रही है । जब तक बातचीत पूरी न हो जाय, यह बताना संभव नहीं है कि उसका क्या परिणाम होगा ।

उद्योगों के लिए विद्युत् की दर

1022. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे भारत में उद्योगों के लिये एक जैसे विद्युत दर लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश की नई राजधानी परियोजना

1023. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई राजधानी परियोजना के लिये अतिरिक्त अनुदान के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार की प्रार्थना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निणय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) मध्य प्रदेश की नयी राजधानी प्रायोजना के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदान देने के लिए भारत सरकार से कोई विशेष प्रार्थना नहीं की गयी है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

मद्रास में आय-कर सम्बन्धी मुकदमें

1024. { श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक अपराध डिवीजन ने मद्रास राज्य में आठ वस्त्र मिल मालिकों पर मुकदमे चलाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गाजीपुर में अफीम का कारखाना

1026. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के अफीम कारखाने को किसी अन्य राज्य में भेजने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई परियोजनायें

1027. श्री मेहश्वर नायक : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की योजना को परियोजनाओं सम्बन्धी समिति की जल उपयोग सम्बन्धी पैनेल द्वारा पांच सिंचाई परियोजनाओं पर किये गये अध्ययन से पता चलता है कि न केवल "उपलब्ध जल का अपर्याप्त उपयोग हो रहा है" बल्कि कृषि उत्पादन सम्बन्धी प्रयत्नों में भी ढील हो रही है ;

(ख) क्या अन्य परियोजनाओं पर भी यही बात लागू है ; और

(ग) इन मामलों में सुधार करने के क्या उपाय किये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) पैनेल ने पांच परियोजनाओं पर अपनी रिपोर्टें अभी तैयार नहीं की हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

यूगोस्लाविया से सहायता

1028. **श्री कोया** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यु० द० सिंह:
श्री प० ह० भील :
श्री रामपुरे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया के विदेशी व्यापार बैंक के प्रबन्ध निदेशक ने चतुर्थ योजना के लिए तृतीय योजना के मुकाबले में अधिक उधार देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

आसाम में ग्रामों के लिए पानी की व्यवस्था

1029. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में ग्रामों के लिए पानी सप्लाई करने की कितनी परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में (अब तक) सहायता दी है ; और

(ख) सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) 10 योजनायें।

(ख) वर्तमान पद्धति के अनुसार धनराशि का आवण्टन योजनावार नहीं होता अपितु योजनाओं के व्यापक समूहों अथवा वर्गों के लिये प्रत्येक वर्ष के अन्त में सहाय्यानुदान स्वीकृत किया जाता है तथापि एक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कुल केन्द्रीय सहायता का तीन चौथाई भाग प्रत्येक राज्य को उस वर्ष के भीतर एक मुष्टि आर्थोपाय अग्रिमों के रूप में नौ समान मासिक किस्तों में मासिक आधार पर दिया जाता है।

राज्य की समस्त केन्द्र साहाय्यित "स्वास्थ्य" योजनाओं के लिये, जिनमें ग्राम जल प्रदाय योजनायें भी सम्मिलित हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में असम सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

	स्वीकृत अनुदान (रुपये लाखों में)
1961–62	66.74
1962–63	64.76
1963–64	64.43
1964–65	69.16 (अन्य रूप में दी गई सहायता सहित)
1965–66	केन्द्रीय सहायता के आवन्टन का निर्णय अभी किया जाना है । बतलाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों के हिसाब किताब को 1964-65 के लिये अन्तिम भुगतान के आदेश तब जारी किये जायेंगे जब राज्य सरकारों से खर्च के पूरे पूरे आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा आयोजित परिसंवाद :

1030. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने हाल में एक परिसम्वाद आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य विचार प्रकट किये गये; और

(ग) उन्हें ध्यान में रख कर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) जी हां। "हाउसिंग फाइनेन्स," पर 1, 2, और 3 फरवरी, 1965 को एक परिसंवाद आयोजित किया गया था।

(ख) और (ग). इस परिसंवाद के द्वारा की गई सिफारिशें इस मन्त्रालय में 4 मार्च, 1965 को प्राप्त हुई थीं। उन पर विचार किया जा रहा है।

साइन्स फीस

1031. **श्री जेधे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता देने के सम्बन्ध में 'ट्यूशन फी' में 'साइन्स फी' को शामिल करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस तारीख से क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कन्या-विद्यार्थियों के लिए फीस वापिस देने के सम्बन्ध में 'साइन्स फी' में घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइन्स) और शारीरिक एवं स्वास्थ्य विज्ञान फीस भी शामिल है ; और

(घ) फीस वापिस देने के मामले में "साइन्स फी' के अन्तर्गत और कौनसी फीस फण्ड आते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (घ). जी हां। खर्च की वापसी के उद्देश्य से 'ट्यूशन फी' में विज्ञान और अन्य ऐसे विषयों के लिये लीए जाने वाली फीस शामिल है, जो नियमित स्कूली पाठ्यक्रम के विषयों के रूप में पढ़ाये जाते हैं। यह निर्णय 1 मई, 1964 से, जब से यह योजना खर्च की वापसी के लिए जारी की गयी थी, लागू है।

चीनी का उत्पादन

1032. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1965 के "इकानमिक टाइम्स" में "कर असमानताओं से चीनी के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि गन्ने के तीन मुख्य प्रयोग करने वालों अर्थात् चीनी, गुड़ तथा खांड़सारी उद्योग में करों में असमानता से किस प्रकार देश में चीनी उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर असमानताओं को दूर करने ने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां ।

(ख) जब भी आवश्यक समझा जाता है उपचारी उपाय किये जाते हैं । चीनी के कारखानों को, और और बातों के साथ, स्पर्धा में गन्ना खरीदने के लिए उत्पादन शुल्क की कटौती के रूप में, जहां भी आवश्यक हो, अतिरिक्त उत्पादन प्रोत्साहन दिया जाता है ।

एक आधुनिक कारखाने में चीनी के निर्माता की अर्थ-व्यवस्था और खांडसारी व "गुड़", बनाने वाले की अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक तुलना नहीं है । उन उद्योगों के अधिक निर्बल वर्गों को, जिनके उत्पादकों पर कर लगाया जाता है, संरक्षण देने की, यदि आवश्यक हो तो वित्तीय उपायों द्वारा भी संरक्षण देने की सरकार की नीति है ।

Employees of Ghazipur Opium Factory

1033. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Laboratory Attendants of Ghazipur Opium Factory have been recongised as Class III employees, while their pay-scale is not similar to that of Class III employees in the Central Government ;

(b) If so, the reasons therefor ;

(c) Whether any representation in this behalf has been received by Government ; and

(d) If so, the action taken thereon ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) : (a) and (b). No, Sir, not generally. The scale of pay for the posts of Laboratory Attendants in the Ghazipur Opium Factory is Rs. 80—1—85—2—95—EB—3—110. According to this scale of pay, these officers should normally be classifical as Class IV. But in conideration of the fact that some of these po st are held by Matriculates and that they are required to performed ties of 'technical' nature e.g. assisting the chemists in routine 6 perations under the direction of the chemists, it has been decided that Laboratory Attendants, who are Matriculates, should enjoy Class III status and that non-Matriculates should be treated as Class IV.

(c) & (d). Yes, the matter is under consideration.

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पानी बांटना

1034. **श्री रबीन्द्र बर्मा :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने राज्य में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पानी बांटने की योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु ल० राव): (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी को बांटने के बारे में केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध राज्यों के बीच समझौता कराने का प्रयत्न कर रही है।

केरल में सिंचाई

1035. श्री अ० क० गोपालन : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिंचाई योजनाओं के लिये एक करोड़ रुपये मांग हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1965–66 में सिंचाई के लिए कितनी धनराशि रखी गई है और इसमें ऋण तथा अनुदान का क्या अनुपात है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख). केरल सरकार ने अपने राज्य की निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं के लिये 1965–66 के दौरान 181 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता के लिये कहा है :

1. नेय्यार––1 और 2 चरण
2. पोयुंड़ी
3 चितुरपुजाह
4 पेरियार घाटी
5 गायत्री
6 कल्लादा
7 पम्बा
8 कुट्टियाडी

(ग) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। वृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिये अनुदान नहीं दिया जाता।

राजस्थान में सिंचाई संसाधन

1036. श्री तन सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसे सिंचाई संसाधन कितने हैं जिनका अभी प्रयोग किया जाना है ;

(ख) क्या भूमि जल सर्वेक्षण किये गये हैं ; और

(ग) सिंचाई-संसाधनों का पूर्ण रूप से विकास तथा उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):(क) लगभग 30 लाख एकड़ ।

(ख) जी, हां; गहरे नलकूपों के लिये।

(ग) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के लिये उपलब्ध वित्तीय साधनों में से राज्य योजना में पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। तकनीकी आर्थिक सुगमता और संगठन तथा सामग्री सम्बन्धी साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए छोटे सिंचाई कार्यक्रम में यथा सम्भव तेजी लाई जा रही है। सिंचाई-संसाधनों के उपयोग के बारे में राज्य सरकार खेतों के लिये आवश्यक जलमार्गों के निर्माण के बारे में विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई-संसाधनों को जल्दी प्रयोग में लाने के लिये क्षेत्रीय कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने तथा उनका विकास करने के लिये भी उन्हें कहा गया है ? राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने चम्बल क्षेत्र के बारे में कृषि विकास का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक संयुक्त अध्ययन दल स्थापित किया है।

भवन-प्लाटों के पट्टे

1037. **श्री हेम राज :**
श्री प० ला० बारुपाल :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1949 से 1963 तक प्रति वर्ष सुन्दरनगर, गोल्फ लिंक, जोरबाग नर्सरी, डिप्लोमैटिक एनक्लेव तथा मथुरा रोड, नई दिल्ली में दुकानों, रहने के मकानों तथा प्रेस के लिए पट्टे पर दिये गये, अथवा बेचे गये प्लाटों की संख्या क्या थी ;

(ख) प्रत्येक इलाके में, प्रत्येक श्रेणी में ऐसे प्लाटों की संख्या क्या है जिन पर पट्टा करार के दो वर्ष की समय-सीमा सम्बन्धी खण्ड के उल्लंघन में 31 मार्च 1963 तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया था ;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में ऐसे प्लाटों की संख्या क्या थी जिनके बारे में दिल्ली के मुख्यायुक्त ने पुनः प्रवेश के अपने अधिकार का प्रयोग किया परन्तु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जुर्माना कर के समझौता हो गया था तथा कुल कितनी धनराशि जुर्माने के तौर पर वसूल की गई ;

(घ) प्रत्येक इलाके में तथा उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में उपरोक्त प्लाटों में से न बनाये गये उन प्लाटों की संख्या क्या है जिनके बारे में पुनः प्रवेश के अधिकार का प्रयोग किया गया था तथा प्रीमियम धनराशि जब्त की गई थी तथा कितना भूमि किराया प्राप्त हुआ तथा कुल कितनी धनराशि इस प्रकार जब्त की गई और समझौते नहीं हुए; और

(ङ) यदि उपरोक्त प्लाटों में से कुछ प्लाट अभी तक नहीं बने हैं तो उनकी संख्या क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (ङ) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

जल-संसाधनों का उपयोग

1038. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में नई दिल्ली में हुई सिंचाई और विद्युत के केन्द्रीय बोर्ड की 37वीं सालाना बैठक में देश के जल-संसाधनों के उपयोग के बारे में क्या सुझाव दिये गये थे, और

(ख) इनके अनुसरण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल टी–3969/69] ।

केरल में वेतन आयोग

1039 **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोट्टकाट्ट :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग नियुक्त करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के कौन कौन सदस्य हैं और उसके निर्देश-पद क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां ।

(ख) आयोग का गठन इस प्रकार है :—

(1) श्री के० एम० उन्नीथन (अध्यक्ष)

(2) श्री पी० एस० नटराज पिल्ले, संसद् सदस्य (सदस्य)

(3) डा० ई० के० माधवन (सदस्य) और

(4) श्री सी० थामस, वित्त सचिव केरल सरकार (सदस्य) आयोग के निर्देश-पद यह हैं :—

(1) सरकारी कर्मचारियों के वेतन के ढांचे की जांच करना तथा उसमें परिवर्तन करने की सिफारिश करना ;

(2) महंगाई भत्ते की वर्तमान दरों का पुनर्विलोकन करना तथा उसमें परिवर्तन करने के लिये सुझाव देना । आयोग प्रशासन में कार्यकुशलता तथा किफायत बढ़ाने के लिये अन्य सिफारिशें भी कर सकता है ।

केरल में स्थानीय नियकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

1040. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० ब० राघवन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सरकार का स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अन्तरिम वृद्धि करने का विचार है ;

(ख) केरल सरकार का स्थायी निकायों को सहायता के रूप में कितनी राशि मंजूर करने का विचार है ; और

(ग) उसे कब लागू किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) से (ग) .केरल सरकार ने राज्य में पंचायतों, नगर निगमों, नगर परिषदों तथा गुरूवापूर्व मण्डलों के पूर्णकालिक तथा आकस्मिक कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के रूप में पहली अक्तूबर, 1964 से महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की मंजूरी दे दी है । इस बारे में व्यय स्थानीय निकाये स्वयं जुटायेंगे । राज्य सरकार उन स्थानीय निकायों को सहायता देना चाहती है जो अपनी निधि से यह व्यय नहीं जुटा सकते हैं । केरल सरकार ने इस प्रयोजन के लिये किसी स्थानीय निकाय को अब तक कोई विशेष सहायता की मंजूरी नहीं दी है ।

Code of Conduct for General Insurance

1041. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri U.M. Trivedi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 359 on the 25th February, 1965. and state :

(a) whether it is a fact that the Life Insurance Corporation, which has recently been authorised to deal with general insurance business also, is not required to follow the Code of Conduct which was voluntarily framed by the Executive Committee of the General Insurance Council ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to close the Department opened by them to investigate into the working of General Insurance Companies ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari): (a) Yes, Sir.

(b) The Life Insurance Corporation is a statutory body established under the Life Insurance Corporation Act, 1956. The Accounts and Reports of the Corporation are submitted to Parliament and the Corporation is, therefore, accountable to Parliament for its activities. Part II A of the Insurance Act, 1938 relating to Insurance Association of India, Councils of the Assocatin and Committees thereof, does ot apply to the Life Insurance Corporation. Nor is any advantage to be gained by subjecting the Corporation to the control of the Executive Committee of the General Insurance Council which consists mainly of the representatives of the general Insurance industry.

(c) Government has opened no such Department. The question of closing it, therefore, does not arise.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मनीपुर के एक (सब-डिवीजन) में की गई आपात की घोषणा और सेना के बुलाये जाने की आवश्यकता

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent Public importance and request that he may make a statement thereon:

"Emergency declared by the Chief Commissioner of Manipur in one of its sub-divisions and necessity for calling of troops."

"मनीपुर के उच्चायुक्त द्वारा वहां के एक सब-डिवीजन में की गई आपात की घोषणा और सेना के बुलाये जाने की आवश्यकता।"

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : श्रीमन्, मुख्य आयक्त ने यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर कि नागाओं के गिरोह पाकिस्तान से हथियार और गोली बारूद ले कर लौट रहे थे और नागालैंड लौटते हुए वापसी में मनीपुर के उस क्षेत्र से हो कर उनके गुज़रने की सम्भावना थी, सशस्त्र सेनाएं (आसाम और मनीपुर) विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अधीन 1 मार्च, 1965 से एक महीने की अवधि के लिये चूरा चांदपुर और तेंगनोपाल उप-मंडलों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। आसाम के राज्यपाल और मुख्य आयुक्त, उपर्युक्त अधिनियम के अधीन, अपने अधिकारों का समय-समय पर, जब कभी भी उनके विचार में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता पड़ी, प्रयोग करते रहे हैं। मैं इस बारे में यह भी बता देना चाहता हूं कि ऊपर कहे गए दो उपमंडलों के अलावा जीरीबाम उपमंडल, इन्हीं कारणों से पिछले कुछ अर्से से ऐसी घोषणा के अधीन चला आ रहा है।

Shri Madhu Limaye : Sir, the eastern part of Manipur territory is near Pakistan but not contiguous with Pakistan; and the Western part is adjacent to Burma. Emergency has been declared in the eastern sector of the territory. At the same time the area contiguous with Burma falls under the Arms Treaty. In view of this fact, May I know whether the Government of India propose to take steps to evoke this Arms Treaty with Burma, a friendly country of ours, and request the Burmese Government to collaborate with our troops in stopping those Nagas returning with arms and ammunition ?

Shri L.N. Mishra : The information given by the hon. member regarding the return of Nagas is correct, but nothing can be said about the route they may definitely pass through. So far as their coming from Burma side is concerned, I have no information in this regard.

Shri J. B. Kripalani (Amroha) : May I know about our friends and enemies ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सवायें, 1965

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्रीमान्, मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवायें, 1965 **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल टी 3961/65]**

(2) 1963–64 के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे तथा उनके वाणिज्यिक परिशिष्ट। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी–3962/65]**

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिदवेन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन (भाग 1) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल.टी–3963/65]**

स्वर्ण बांड और केरल सामान्य बिक्री-कर अधिनियम के बारे में अधिसूचना

श्री ब० रा० भगत : मैं श्री रामेश्वर साह की ओर से निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) 7 प्रतिवर्ष स्वर्ण बांड, 1980 जारी करने के बारे में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (2)-डब्ल्यू एंड एम/65, दिनांक 27 फरवरी, 1965 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3964/65]।**

(2) केरल राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 10 सितम्बर 1964 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित, केरल सामान्य बिक्री-कर अधिनियम, 1963 की धारा 57 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल सामान्य बिक्री-कर नियम, 1963 में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक 7 जुलाई, 1964 का एस० आर० ओ० 205/64।

(दो) दिनांक 13 अगस्त, 1964 का एस० आर० ओ० 242/64।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल.टी—3965/65]

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 3 मार्च, 1965 को पास किये गये आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1965 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 4 मार्च, 1965 को पास किये गये विनियोग विधेयक, 1965 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

———

औचित्य प्रश्न क बारे में

RE : POINT OF PROPRIETY

श्री दाजी (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, हमें विदित हुआ है कि राज्य-सभा में आय-व्ययक के बारे में चर्चा पहिले आरम्भ हो गई है । वास्तव में यह उपहासजनक बात है कि इस सदन में जहां अनुदानों की मांगों पर मतदान दिया जाता है, चर्चा पहले आरम्भ न हो । इस विषय को गत वर्ष के पहले भी इस सदन में औचित्य प्रश्न के रूप में उठाया गया था । संसदीय-कार्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा निगमों तथा उपक्रमों सम्बन्धी कई प्रतिवेदन हैं जिनके बारे में दूसरे सदन में इस दौरान चर्चा हो सकती है, इस सदन में आयव्ययक संबन्धी चर्चा बाद में होने पर उसका महत्व कम हो जाता है । यह अधिकार का नहीं अपितु औचित्य का प्रश्न है । अतः इस सदन में उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि मैं माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह सहमत हूं तथापि जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, उन्हे उसे इस प्रकार नहीं उठाना चाहिए था । (**अन्त-र्बाधायें**) ।

श्री दाजी : यह एक गम्भीर प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कल विचार करेंगे।

अनुदानों की मांगें रेलवेज़—1965-66—जारी

DEMAND FOR GRANTS—RAILWAYS—1965-66 *contd.*

अध्यक्ष महोदय : डा० मा० श्री० अणे अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, वर्धा और बलहारशा के बीच एक माजरी जकशन है। इस जंकशन से राजपुर कोयला खानों को एक लाइन जाती है । इस लाइन पर वानी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इस लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में केवल तीसरे दर्जे के ही डिब्बे होते हैं। इसके अतिरिक्त माजरी की ओर जाने वाली गाड़ियों के साथ दूसरी ओर से अन्य कोई गाड़ी भी उत्तर अथवा दक्षिण की ओर नहीं जाती है । अतः यात्रियों का समय व्यर्थ नष्ट होता है। अतः मैं रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस लाइन पर रेलों को चलाने की उचित एवं सुविधाजनक व्यवस्था करें। जनता एक्सप्रेस के अतिरिक्त सीधे जाने वाली अन्य कोई गाड़ी इस स्टेशन पर नहीं रुकती है।

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि अब रेलें समय पर छूटती हैं और ठीक समय पर गतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। अधिकांशतः सदस्यों ने यात्रियों को और अधिक सुख-सुविधायें देने पर जोर दिया है। किन्तु मेरा विचार यह है कि रेलों के ठीक समय पर छूटने तथा गन्तव्य स्थान पर पहुंचने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये क्योंकि इस कारण रेलवे यात्रियों को सबसे अधिक कठिनाई और परेशानी होती है। देश में जनता को समय की पाबन्दी के महत्व को समझाने में रेलें सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुई हैं; अतः समय की पाबन्दी के प्रश्न को अधिक महत्व देना चाहिए। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह

कह सकता हूं कि जी०टी० एक्सप्रेस, जो अधिकाधिक संख्या में यात्रियों को मद्रास से दिल्ली लाती हैं, अधिकाशत: निश्चित समय पर नहीं चलती है। रेलवे ने विशेषत: 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान देश के लिए प्रशंसनीय सेवायें की हैं।

रेलों में प्राय: यात्रियों द्वारा खतरे की जंजीर खीचने की घटनायें होती रहती हैं जिससे अन्य सह-यात्रियों को असुविधा होती हैं। इस कारण भी रेलें ठीक समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। रेलों में जंजीर का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जा रही है। अत: रेलवे बोर्ड को इस दुरुपयोग की प्रवृत्ति रोकने और इसका दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को कड़ी सजा देने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

रेलवे की लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है कि रेलवे में अनियमिततायें और अति के कारण 1,58,65,319 रुपये की हानि हुई है। इस प्रतिवेदन से यह भी पता चलता है कि अधिकांश मामलों में हानि का कारण रेलवे अधिकारियों की लापरवाही है। अत: रेलवे प्रशासन तथा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। प्रशासनिक-व्यय तथा अन्य राजस्व परिव्यय में यथासम्भव मितव्ययता करने की आवश्यकता है। यह हर्ष एवं प्रशंसा की बात है कि रेलवे विभाग में कामकाज सहयोग और समन्वय की भावना से किया जाता है।

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad) : Mr. Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on the Railway Budget. Some hon. Members have expressed adverse views regarding creation of the South-Central Zone in Secunderabad.

(श्री खाडिलकर पीठासीन हुए
Shri Khadilkar in the Chair)

Those Members are perhaps not aware of the fact that eighty years back, there were Railway lines in the State covering a distance of 1400 miles. The State Railways used to cater to passenger and goods traffic there. Unfortunately Hyderabad fell a victim to the Police Action on account of its politics. This incident helped eradicate the then existing evils there and at the same time it gave a severe blow to the State depriving it of its happiness and prosperity. All the State Railway property worth Rs. 200 crores was taken over by the Centre. There are various big buildings lying vacant and useless in Hyderabad which can be utilised for housing offices etc.

I am sure that the Railway Board will take suitable measures to develop the Railways in Andhra Pradesh. Hyderabad and Secunderabad Railway stations require their renovation as they are very small and old stations. I will request the hon. Minister to pay his attention to the problems relating to the passenger and goods traffic of the State. Hyderabad is not connected or linked directly with Delhi, Bombay and Calcutta. We have, therefore, to suffer much inconvenience and difficulties while performing railway journey. The Railway Authorities should give full consideration to this matter and take suitable measures to connect Hyderabad directly with these big and important cities with a view to meet the requirement of the State and cater to increased bulk of passenger traffic. There are very poor people in my constituency and adequate railway facilities should be extended to this area. There is a need to connect Lingampelli with Nader *via* Sangareddi, Jogipeth and Narayankhet ; and also to create a new section linking Hyderabad with Machlora *via* Ibrahim Patan, Nalgunda and Nagarjunsagar.

[Shrimati Laxmi Bai]

Now I come to the Welfare Fund which has increased to Rs. 20 crores. To ensure better and proper utilisation of the Fund, the Railway Authorities may formulate schemes and implement them in the interest of the staff. I may also suggest that steps should be taken to start industries and open Production Centres even at Small Railway stations which may provide jobs to suitable female candidates belonging to the families of the staff.

I will request the hon. Minister to extend some more facilities to the Lady compartments. It is after observed that the fellow male passengers put their luggage in the Lady compartment causing much inconvenience to the ladies sitting in the compartment. So the Railways should find some ways of checking this tendency. The Railway Administration also requires improvements as the Railways authorities do not pay due attention to the complaints made by the public.

Coming to the catering in the Railways, I am happy to say that it is being run on satisfactory lines and the system introduced is very good one. At the same time complaints are often received from the passengers that some discrimination is meted out to them as they are not served as good meals as Members of Parliament are. The matter may, therefore, be looked into and necessary steps taken to eliminate this discrimination.

Efforts should also be made to see that the running and other staff detailed for duty is functioning properly, for even a bit negligence on their part may cause much inconvenience and difficulties to the passengers.

There is a large scope to effect economy in the various wings of the Railways, and the hon. Minister and the authorities concerned may look into this matter properly so that they may find suitable measures to materialise it.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : मेरा निवेदन है कि सामान्यत: रेलवे का कार्य अच्छा ही रहा है। इस दिशा में भी कार्य सन्तोषजनक रहा है कि गाड़ियों की कमी नहीं हो पाई। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि इस दिशा में हमें अब उदासीन हो जाना चाहिये। वैसे उत्पादन तथा औद्योगिक विकास आशातीत नहीं हुआ है। इसके कारण भी रेलवे राजस्व कम प्राप्त हुआ है। माल डिब्बों की हमने काफी व्यवस्था कर ली थी। रेलवे मंत्री का यह गर्व ठीक ही है कि काम काफी ठोस आधार पर हुआ है और वित्तीय स्थिति काफी मजबूत हो गयी है। उन्होंने यह भी कहा है कि रेलवे की स्थिति को मजबूत करने के विचार से ही वह भाड़ा बढ़ा रहे हैं। यह ठीक तर्क नहीं है कि भाड़ा और वस्तु भाड़ा बढ़ा कर राजस्व बढ़ाने से हम रेलवे की साख भी बढ़ा २ हैं। भाडे तथा वस्तु भाड़े में वृद्धि के बिना भी रेलवे की साख ठीक रहती ।

रेलवे के वाणिज्यिक पहलू पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया है। निश्चय ही वह हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक उपक्रमों में से एक है परन्तु उसमें वाणिज्यिक प्रवृत्ति और बिक्री के ढंग की कमी है जो किसी वाणिज्यिक संस्था के लिए अत्यावश्यक है। लाभ के अतिरिक्त अन्य व्यापारी प्रवृत्तियां भी उदाहरणतया ग्राहकों की सन्तुष्टि होनी चाहिये।

रेलवे जो सड़क परिवहन के बड़े भाई के समान है, उसके प्रति उचित व्यवहार नहीं कर रही है। इसलिए खंड बनाने में आर्थिक विचारों के अतिरिक्त अन्य कोई आधार नहीं होना चाहिये। हमें विभिन्न स्टेशनों पर काम में वृद्धि की ओर ध्यान देना चाहिये।

खंड बनाने के आधार को निश्चित करने के कुछ सिद्धान्त होने चाहियें। इस समय यह आधार त्रुटिपूर्ण है। पृथक मीटर गेज खंड तुरन्त बनाने की आवश्यकता है ताकि उनकी अवहेलना न हो। कुछ डिवीजन बहुत ही असंतुलित हैं। उदाहरणार्थ दिल्ली डिवीजन बहुत बड़ा है जिसमें 30,000 कर्मचारी हैं।

गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये। जहां तक समय-पालन का सम्बन्ध है कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो महीने के अधिक भाग में देर से आती हैं। जोधपुर से जयपुर जाने वाली गाड़ी इनमें से एक है। इस ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। यह बहुत ही अनुचित है कि कुछ विभागीय लाइनों अर्थात् रानवेड़ा-भिलड़ी-कोटेवल और खण्डवा-हिंगोली लाइनों पर अधिक किराया और वस्तु-भाड़ा लिया जा रहा है। इसके लिये तनिक भी औचित्य नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

बार बार मांग किये जाने पर भी कि सिरोही और जालोर जिलों में रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेलवे में एक अच्छे कर्मचारी सम्बन्धी आयोजन की आवश्यकता है। एक ओर तो रेलवे प्रशासन से अधिकारी बाहर चले जाते हैं और दूसरी ओर वे अच्छे अधिकारियों को रेलवे सेवा में लाने में असफल हो रहे हैं। उनकी पदोन्नति आदि के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये। मुझे रेलवे को इस बात के लिए भी मुबारकबाद देनी है कि गत तीन मास में जो तूफान दक्षिण में आया था और जिसके फलस्वरूप पुल उड़ा दिया गया था, उस पुल को पुनः बना लिया गया है। इस मामले में जनरल मैनेजर श्री गांगुली ने बहुत ही अच्छा कार्य करके दिखाया है। यद्यपि इस कार्य को कर लेने के लिए तीन मास का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु उन्होंने इसे दो मास में ही पूरा कर लिया। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि मैं देश के चुने स्टेशनों को 'माडल स्टेशन' बनाना चाहिए। समें स्टेशन लेने चाहिए जहां पर क विदेशी यात्री प्रायः जाते हैं। इन स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर ायः माल त्यादि बिखरा रहता है और भिखारियों की भी भीड़भाड रहती है।

Shri A. P. Sharma (Buxar) : We hope that as under the demand No. 2, the survey of Arah-Sasram Line has been including, the work will be completed very shortly. I have this fear because many-a-time it is noticed that the work is started but later on unnecessary delays are done.

It is very good that the Railways have done very satisfactory progress. But I feel the Railway Minister has hinted nothing regarding those who are responsible for the progress. We must not forget 12 lakhs of railway employees who have put in their hard toil to achieve this progress. I don't agree with the Railway Minister that railway employees are satisfied with their lot. I think there is a general dissatisfaction from top to bottom. The appointment of wage board is their old demand which I think should be accepted. This demand has been put forward and supported by all the organizations of railway employees.

Then the problem of casual labour is very important. These people are still in these days getting a rupee, 12 annas, or one ruppee, 50 paise per day. I hope the Revenue Miniser will look into their miserable plight. I also like to state in this connection the plight of railway labour machinery. There is a

[Shri A. P. Sharma]

need of effecting revolutionary changes in it. Because of that there is a great dissatisfaction amongst the people. I may stress that there should be provision of arbitration on the level of railway board. The Honourable Minister should look into this demand of mine.

I also stress the need of a separate Railways Public Service Commission. There should be provision of examination in either Hindi or in the regional language for the recruitment of the class three employees. Shri Patil gave such an assurance in the Consultative Committee. I hope this will solve many problems. Some town in Bihar may be headquarter of this new Public Service Commission. This is all I wanted to state.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I have stated beforehand certain things regarding Rajasthan. Now I shall say a few words regarding the labour. I want to submit that after sometimes, say six months, a year or two, the casual labour should be made permanent. As they are temporary people, therefore they get no hospital facilities. Even if somebody gets the medicine, that is not up to the mark. Good medicines in the hospitals are purchased for the big people and nothing has been done for the labour. They are asked to purchase medicines. They are poor people and cannot purchase medicine. Even, it is difficult for them to keep body and soul together. He gets only 110 rupees per month for his and his family's maintenance. I urge that the casual labour must be fixed up.

Railway has got 44000 commercial employees, they are neither given any grade nor are supplied with the uniforms. I am also told that some money out of their wages is also deducted for the losses for which they are held responsible. This commercial clerk gives to the Railway sufficient income, still he has to face all these hardships. I would request the honourable Minister to look into their case and give them some facilities.

Together with that I may also state that at Kotah railway station, there are 20,000 Railway employees. There must be some arrangement for Police Station. Recently one or two murders have taken place. For such big area there are only four constables. How can 20,000 men with their families feel secure with 4 policemen.

The 90 Down Dehradun train is always overcrowded as majority of the passengers travel upto Jaipur. Only two third class boggies are attached with it. All the passengers cannot be accommodated in them. My suggestion is that there should be railway train between Nagda to Mathura, this is very important. There should be partition in the overbridge at Kotah for the facility of the passengers. At the canteen in Loco Workshop, scheduled caste people are not given proper treatments. After Shri Jagjiwan Ram, we find that backward classes are not treated well. Scheduled caste people have to sit separately in these canteens. This must go.

Railway employees should be given quarters. Moreover there is no arrangement for the education of the children of the Railway employees. It has also been brought to my notice that some railway employees are misusing the free Railway passes. It should be checked.

I want to state one thing more. The sleeper coach must have a separate room for the Conductor. He has to sit near the latrine. I hope the honourable Minister will look into the suggestion I have put forward.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : सामान्यत: लोग यह महसूस नहीं करते कि रेलवे का कार्य कितना व्यापक है। रेलवे के विरुद्ध शिकायतें बहुतों को है, परन्तु हमें कुछ कहने से पूर्व सब स्थिति को अच्छी प्रकार देख लेना चाहिये। रेलवे एक आदर्श सरकारी उपक्रम है तथा हमारे अन्य सरकारी उपक्रमों को उससे शिक्षा लेनी चाहिये। समूचे रूप से रेलवे बोर्ड ने अच्छा कार्य कर दिखाया है। ऊपर से नीचे तक सभी रेलव कर्मचारी अच्छा काम करने के लिए बधाई के पात्र हैं। रेलवे ने राष्ट्रीय एकता तथा देश की प्रतिरक्षा के विषय में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। यदि किसी मजूरी बोर्ड की स्थापना सम्भव नहीं है तो विभिन्न रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनके कार्य-स्थान और काम में खतरे के प्रकार को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन-क्रम नियत किए जाएं। हमारी रेलवे को विश्व के दूसरे भागों के समान शो-पास रखने चाहियें।

पठानकोट में कथुआ तक और बाद में जम्मू से रियासी तक रेलवे लाइन के बनाने का प्रस्ताव था परन्तु हम नहीं जानते कि इसकी कार्यान्विति में इतना समय क्यों लिया गया है। हमारे देश की सामरिक आवश्यकता को महसूस किया जाना चाहिये तथा इस लाइन को शीघ्रता से बनाया जाए। यात्रियों की आदतों में सुधार करने के लिए रेलवे को उपाय करने चाहिये। गाड़ियों के आने-जाने की घोषणाओं के साथ-साथ सफाई, सामान आदि सम्बधी मंत्रणा भी दी जानी चाहिये। जमालपुर की रेलवे कर्मशाला में बहुत अच्छे तकनीकी कर्मचारी काम कर रहे हैं। उहें उचित प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये। वे और अधिक प्रतिष्ठा तथा वेतन-क्रयों के पात्र हैं। अब तो रेलवे का बजट बचत वाला है। अत: इसे कर्मचारियों को दिया ही जाना चाहिये। 500 से 1200 वाले कर्मचारियों को आप भत्ता क्यों नहीं देते। आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा है। रेलवे में बड़े और छोटे में भेद भाव नहीं किया जाना चाहिए।

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh) : I request the Railway Minister to pay some attention to Madhya Pradesh and its needs. I understand that from the point of view of defence some priorities have to be given. But after this item the backward areas must be looked into. I agree that more provision of railway must be done in Kashmir and at other places. But the backward area of Madhya Pradesh should not be ignored in the laying of new railway lines.

I would also like to stress that the amenities for trains should be improved. The timings of the trains should be so arranged that a connecting train is available at the changing station. On stations Katni, Bina, Saugar, and Damoh etc., the people pull the chain at the outer signals and hundreds of them get down without tickets. This has also been seen sometimes that they take away the belongings of other passengers also. Stern steps should be taken to stop such things.

I would like to draw the attention of the honourable Minister the necessity of connecting Saugar with Hirapur, Chartrapur Barhanpur and Narsmhapur by railway lines. It is also felt that the bridge is also necesary at Saugar. Bridges should also be constructed at Katni, Jabalpur and Damoh.

[Shrtimati Sahodra Bai Rai]

Together with that we should be very vigilant regarding monetary consideration. No appointment should be made on such matters. I also feel the great necessity of an underground railway between Delhi and Calcutta. There should be a separate train for women only from Delhi to Madras. I have complaints regarding the Cattle transport. That is not looked after properly . Proper attention should be given to this matter. Cattle should not die for want of water.

On big railway stations the railway employees indulge in anti-social practices. That should be checked and we should see that employees on bigger stations must be transferred after three years. I hope due attention will be given to the points which I have placed here for consideration.

श्री चं० का० भट्टाचार्य (रायगंज): श्रीमन, माननीय मंत्री जी ने रेलवे बोर्ड तथा तथा रेलवे प्रशासन की जो सराहना की है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं परन्तु मैं उनका ध्यान उन आश्वासनों की ओर दिलाना चाहता हूं जो रेलवे मंत्री समय समय पर देते रहे हैं परन्तु प्रशासन ने उनको अभी तक पूरा नहीं किया। मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधान करता हूं जो बंगाल प्रांत की राजनीति, संस्कृति और इतिहास में प्रमुख पार्ट अदा करता रहा है। परन्तु खेद से कहना पड़ता है कि वहां संचार सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं। वहां के लोग इस असुविधा से दुखी होकर सरकार से बार-बार अपील करते रहे हैं कि रायगंज और बलूरघाट का कलकत्ता से बड़ी लाइन द्वारा सम्पर्क होना चाहिये। कितनी दुख की बात है कि कलकत्ता से बलूरघाट अथवा रायगंज पहुंचने में 26 से 28 घंटे लगते हैं जबकि कलकत्ता से दिल्ली तक केवल 24 घंटे लगते हैं। हमारे प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री, जब रेलवे मंत्री थे, लोगों द्वारा बार-बार की गई अपीलों के फलस्वरूप बलूरघाट गये और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिलाया कि उस जिले को मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ दिया जायेगा। एक ऐसा प्रस्ताव भी था कि खजुरियाघाट से सिलीगुड़ी तक एक बड़ी लाइन के निर्माण करने की योजना बनाई जायेगी। इससे वहां के लोगों को ऐसा आभास हुआ कि अब उनकी असुविधा दूर हो जायेगी। हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री जगजीवन राम ने भी एक बार आयव्ययक प्रस्तुत करते समय कहा था कि पश्चिमी दीनाजपुर जिले को एक लाइन द्वारा यातायात के लिये खोला जायेगा। यद्यपि एक लाइन बनाई गई परन्तु वह लाइन पश्चिमी दीनाजपुर जिले के अन्दर न होकर बाहर से ही आगे चली गई। इस प्रकार रेलवे बोर्ड ने रेलवे मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में कही गई बात को पूरा नहीं किया। जिसके फलस्वरूप लोगों को आज भी बहुत असुविधा हो रही है। प्रशासन पर न ही मेरी प्रार्थना का कोई प्रभाव पड़ा है और न ही लोगों की अपीलों का।

इस जिले में दो मुख्य केन्द्र हैं—एक बलूरघाट जो जिले का अब मुख्यालय है और दूसरा है रायगंज जिसकी जिले का मुख्यालय बनने की आशा है। यहां पर संचार साधनों की बहुत कमी है। इस कमी को दूर करने के लिये बलूरघाट का सम्पर्क खजुरियाघाट से सिलीगुड़ी तक बनाई गई बड़ी लाइन से जोड़ा जाये और दूसरी यह बात की जाये कि रायगंज से राधिकापुर तक जाने वाली छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये। वास्तव में बलरघाट से बड़ी लाइन तक एक लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण भी किये गये। यह लाइन अन्य उत्तर–पूर्व सीमान्त रेलवे लाइनों की तरह अलाभप्रद नहीं होगी जैसा कि मंत्री जी ने उन लाइनों के सम्बन्ध में उल्लेख किया है कि वे लाभप्रद नहीं

होंगी। अतः मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले की पूरी तरह छानबीन करें और इस समस्या को हल करें ताकि लोगों को इससे होने वाली असुविधा से युक्ति युक्ति मिले।

इसकी समझ नहीं आती कि दिये गये आश्वासनों को पूरा क्यों नहीं किया जाता। यह सच है कि रेलवे मंत्री बदलते रहते हैं परन्तु रेलवे प्रशासन में तो कोई तबदीली नहीं आती। जब खजुरियाघाट पर बड़ी लाइन को खोला गया था उस समय श्री जगजीवन राम ने, रेलवे बोर्ड के वतमान सभापति (जो उस समय वहां के महाप्रबन्धक थे) तथा दक्षिणी रेलवे के महाप्रबन्धक श्री बी० सी० गंगूली (जो तब मुख्य इंजीनियर थे) की उपस्थिति में यह कहा था कि रायगंज की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जायेगा परन्तु ऐसा अभी तक नहीं किया गया। जब रेलवे बोर्ड को इस बारे में लिखा गया तो उन्होंने बताया कि वहां तो छोटी लाइन पहले ही है। वे यह भूल जाते हैं कि रायगंज का कलकत्ते से बड़ी लाइन द्वारा कोई सीधा सम्पर्क नहीं है। बड़ी लाइन का होना उस जिले के हित में है। छोटी लाइन द्वारा पटना अथवा लखनऊ से इसका सम्पर्क इतना हितकर नहीं है। खजुरियाघाट लाइन जो बनाई गई है वह उस क्षेत्र में छोटी लाइन के साथ साथ जाती है। कहीं तो लोगों को बड़ी तथा छोटी दोनों लाइनों की सुविधा प्राप्त है और कहीं लोगों को रेलवे लाइन से वंचित रखा जा रहा है यह कहां का न्याय है।

श्री अब्दुल गनी गोनी (जम्मू तथा काश्मीर): मुझे खेद से कहना पड़ता है कि जम्मू तथा काश्मीर को अभी भी देश से अलग थलग रखा हुआ है। उसको रेलवे लाइन द्वारा देश के अन्य भागों से क्यों नहीं मिलाया जाता। इस समय पठानकोट द्वारा एक ही सम्पर्क है जो काश्मीर को देश के अन्य भागों से मिलाता है और वह है जम्मू-पठानकोट सड़क। इस सड़क पर भी पाकिस्तानियों ने उपद्रव मचाया हुआ है। आये दिन वे युद्ध विराम रेखा को पार कर के हमारे जीवन में खलबली उत्पन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं।

जम्मू तथा काश्मीर तक रेलवे लाइन बनाने की मांग केवल इसलिये ही नहीं की जा रही कि इससे हमें सुविधा हो जायेगी परन्तु इसलिये की जा रही है कि इसका होना प्रतिरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। हमने अपने देश के उस भाग को पाकिस्तान तथा चीन दोनों शत्रुओं से बचाना है परन्तु दुख इस बात का है कि रेलवे मंत्रालय तथा केन्द्रीय सरकार की उस क्षेत्र के बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है। कार्य बड़ी धीमी चाल से किया जा रहा है। 2 वर्ष पूर्व मुझे बताया गया कि पठानकोट से जम्मू तक रेलवे लाइन अप्रैल, 1964 तक पूरी हो जायेगी परन्तु वह अब भी तैयार नहीं हुई। माननीय मंत्री को जांच करनी चाहिये कि यह कार्य इतनी धीमी रफ्तार से क्यों किया जा रहा है और हमें बतायें कि यह कब तैयार हो जायेगी। प्रतिरक्षा के अलावा राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से भी इस लाइन का होना बहुत आवश्यक है कि जैसा कि श्री दी० चं० शर्मा ने भी कहा है। काश्मीर तक रेलवे लाइन न बनाने में उस राज्य को कई आर्थिक लाभों से भी वंचित रखा जा रहा है। यातायात सम्बन्धी सुविधायें न होने के कारण वहां के कोयले तथा अन्य खनिजों के निक्षेपों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा। इमारती लकड़ी जो रेलवे स्लीपरों के काम भी आती है, कितनी मात्रा मे हमें मिल सकती है और यातायात सम्बन्धी सुविधाओं के होने से और भी सस्ती पड़ेगी। यदि जम्मू से रियासी तक रेलवे लाइन बना ली जाये

[श्री अब्दुल गनी गोनी]

तो उस क्षेत्र से कोयला निकाला जा सकता है जो हमें बंगाल और बिहार की कोयला खानों से कोयला लाने की तुलना में कहीं सस्ता पड़ेगा। यही नहीं वहां का सबसे बड़ा व्यापार पर्यटक यातायात है और रेलवे लाइन न होने के कारण उस पर कितना कुप्रभाव पड़ता है। क्योंकि वहां पर सड़क यातायात सम्बन्धी सुविधायें भी अच्छी नहीं हैं, इसलिये इस उद्योग में बहुत हानि हो रही है। मेरे विचार में काश्मीर मेल, श्रीनगर एक्सप्रेस तथा सियालदाह एक्सप्रेस गाड़िया पठानकोट की बजाये कथुआ से चलाई जानी चाहिये और कथुआ में होटल और जलापानगृह खोले जायें जिससे पर्यटकों को सुविधा हो। एक और सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि श्रीनगर में अनंतनाग से उरी तक सर्कुलर रेलवे बनाई जानी चाहिये इससे पर्यटकों तथा वहां के रहने वाले लोगों को काफी सुविधा हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं रेलवे सम्बन्धी अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बसुमतारी (गोलपारा): बंगाल की तरह आसाम भी, जहां तक रेलवे संचार-साधनों का सम्बन्ध है, पिछड़ा हुआ है। आसाम में केवल एक ही रेलवे लाइन है जो बंगाल से गुजर कर जाती है। इस रेलवे लाइन को बड़ी-बड़ी नदियों और असुरक्षित क्षेत्र से होकर जाना पड़ता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपात-काल के पश्चात इस लाइन को सुदृढ़ बनाया गया है और इसकी भी खुशी है कि जलपाईगुड़ी से जोगीघोपा तक एक बड़ी लाइन की भी मंजूरी दी गई है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। अतः जैसे मेरे और माननीय मित्रों ने सुझाव दिये हैं कि इस बड़ी लाइन को बोंगाइगांव द्वारा गोहाटी तक बढ़ा दिया जाये, में भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सुझाव पर विचार किया जाये और इसके लिये चौथी योजना में व्यवस्था की जाये। जहां केन्द्रीय सरकार आसाम में संचार-साधनों की वृद्धि करने में जोश दिखा रही है, वहां कई नेताओं ने आसाम को प्राथमिकता देने पर आपत्ति की है क्योंकि आसाम की जनसंख्या केवल एक करोड़ है। निःसन्देह प्रजातंत्रात्मक देश में जनसंख्या का बहुत महत्व है, परन्तु आसाम की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। प्रतिरक्षा की दृष्टि से काश्मीर की तरह आसाम को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जहां तक रेलवे लाइनों का विस्तार का सम्बन्ध है। चीनी आक्रमण के समय हमें जो अनुभव हुए उनकी दृष्टि से हमें इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में सुलझाना चाहिये।

जलपाईगुड़ी से आसाम तक जो रेलवे लाइन है उसपर स्टेशनों का स्तर अन्य राज्यों के स्टेशनों की तुलना में बहुत गिरा हुआ है। प्रतीक्षालयों में टूटी हुई कुर्सियां देखी जाती है। सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जैसा कि हमारे मंत्री श्री राम सुभग सिंह को ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष बिहार से काफी मजदूर आसाम जाते हैं और वहां कार्य करते हैं। उनके लिये विशेष गाड़ियां चलाई जानी चाहिये। एक और बात जो में इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह यह है कि जबकि आसाम के बाहर से आने वालों को रात को चलने वाली गाड़ियों की सुविधा प्राप्त है, परन्तु यह सुविधा आसाम वालों को नहीं दी गई है। अतः सरकार को चाहिये कि आसाम के लोगों को भी यह सुविधा दे।

रेलवे विभाग में आसामियों को, दूसरे वर्गों की तुलना में रोजार के अवसर बहुत कम दिये जाते हैं। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि रेलवे विभाग ने आसाम से एक अधिकारी की भी नियुक्ति नहीं की है।

माननीय मंत्री ने रेलवे प्रशासन की बहुत सराहना की है। इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु जैसा कि श्री भट्टाचार्य ने बताया कि मंत्रियों द्वारा समय समय पर दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं किया जाता है। यह समझ में नहीं आया कि ऐसी हालत में मंत्री जी उनकी प्रशंसा किस लिये करते हैं। रेलवे प्रशासन को चाहिये कि वह कार्यकुशलता का एक ऐसा उदाहरण पेश करे जिसका अन्य उपक्रम अनुकरण करें। अन्य विभागों की तुलना में रेलवे विभाग में भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं जैसाकि में इसका कई बार पहले भी उल्लेख कर चुका हूं। आसाम में गाड़ियों की रफ्तार 12 से 20 मील प्रति घंटा है जो कि बहुत कम है। वहां पर रेलगाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाया जाना चाहिये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित पद होने चाहिये। श्री जगजीवन राम जी जब रेलवे मंत्री थे उस समय उनको अधिक नौकरियां दी जाती थीं। मंत्री जी ने जहां इस विषय पर छानबीन करने को कहा है, वहां उन्होंने श्री जयपाल सिंह द्वारा दिये गये भाषण का भी उल्लेख किया कि वह उनके लिये आरक्षण नहीं चाहते। मेरे विचार में श्री जयपाल सिंह ने उनकी पदोन्नति के आरक्षण के बारे में कहा था कि यह नहीं होना चाहिये क्योंकि उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर आपत्ति की है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उनकी नियुक्तियों के लिये आरक्षण ही न किया जाये।

मुझे आशा है कि मंत्री जी आसाम में रेल-संचार में वृद्धि करने का हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

Shri Daljit Singh (Una): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Bus stands are put up by the State Government at a long distance from the Railway Stations, for want of co-ordination between the State Government and the Railways, which causes great inconvenience to the travelling public and loss to the branch lines. A special bogie should be attached with the train from Hoshiarpur to Delhi.

With the increase in railway fares, the traffic on the branch lines would decline and the people would prefer to travel by buses. The fares should not therefore, be increased in any case, not for distances upto one hundred kilometres.

The backward areas have been ignored in the budget proposals. Amenities like extension of platforms, provision of drinking water, goods sheds etc. are urgently needed to be provided. Special attention should be paid to provide those facilities on Ambala-Kalka, Rupar-Nagal, Jullunder-Hoshiarpur, Jogindar Nagar-Pathankot lines. No survey for new lines have been provided. At least one-fourth of the new lines should be opened in the backward areas.

Rupar-Nagal and Mukerian-Jalwara dam lines should be connected keeping in view the defence requirements.

[Shri Daljit Singh]

On the completion of a dam, the machinery installed there should be transferred to another dam and skilled as well as unskilled workers absorbed there.

Branch lines lacked passenger facilities, which should be provided. There should be a direct train from Delhi to Nangal which was an important place and served as a link with Himachal Pradesh.

There were complaints by V.I.Ps about first and second class compartments without proper amenities in the train going to Nangal, which a good number of tourists use. That should be looked into.

The old agreement between the Centre and Punjab Government about Rupar-Nangal line should be cancelled and the line taken over by the Centre. Proper amenities should be provided for the passengers as also for the employees working on the line, only Nangal dam is showing a profit of Rs. 10 lakhs.

I would urge upon the Government that Chandigarh, the capital of Punjab should be linked with Ludhiana and Jagadhari by a railway line and arrangements made to extend more amenities to passengers.

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा): उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे देश में सबसे बड़ा वाणिज्यिक और सामाजिक कल्याण संगठन है अतः इससे देश की प्रगति में बहुत बड़ी सहायता मिलने की आशा की जाती है। रेलवे की सफलता अधिकतर उसमें काम करने वालों पर निर्भर करती है इसलिए उनमें स्वविवेक और उत्साह लाने के लिए कुछ नये प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए। उनकी कार्यकुशलता को मान्यता देनी चाहिए और अच्छे और सराहनीय कामों के लिए उन्हें पुरस्कार दिये जाने चाहिए। योग्य व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतियोगितायें भी होनी चाहिऐं।

रेलवे म भोजन व्यवस्था विभाग हानि उठा रहा है क्योंकि इसके द्वारा तैयार किया गया भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है। इस काम में विशेषत: देखभाल के काम में महिलाओं को लगाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकतायें उनके पिछड़ेपन की सीमा के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र का विकास सबसे पहिले किया जाना चाहिए, और दक्षता विभाग द्वारा उनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

अंग्रेजों ने बुन्देल खण्ड को बहुत उपेक्षित हालत में रखा क्योंकि उसमें बहुत स्वतंत्रता संग्राम में पैदा होने वाले वीर पैदा हुए हैं, यहां एक भी लाइन नहीं है। कम से कम उस लाइन का निर्माण तो किया जाना चाहिए जिसका वर्ष 1929 में सर्वेक्षण हो चुका है, किन्तु बाद में लाखों रुपये खर्च करने के पश्चात उसका काम रोक दिया गया था।

माल-डिब्बों के आवंटन सम्बन्धी नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, एक वर्ग के लोगों के प्रति पक्षपात दिखाया जाता है और उन्हें वेगन दिये जाते हैं किन्तु दूसरे वर्ग के लोगों को इन्कार किया जाता है। इस प्रकार के भेद-भाव को दूर किया जाना चाहिए।

रेलवे में भीड़-भाड़ की बड़ी जटिल समस्या बनी हुई है। भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए "जनता गाड़ियां" चलायी जानी चाहिएं। कोई नया तरीका बनाया जाना चाहिए जिससे यात्रियों का भारी सामान बैठने वाले डिब्बों के बजाय दूसरे डिब्बों में रखा जा सके।

रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए और चोरी आदि से बचने के नये तरीके अपनाये जाने चाहिएं । बेकार सम्पत्ति को तुरन्त बेच देना चाहिए ।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Balrampur Gonda is a backward area and lacked in railway lines, roads and employment opportunities.

The direct train between Lucknow and Balrampur is welcome. But it runs very late and its services are irregular. The first and second class compartments are very inferior and lacked proper amenities. It is, therefore, requested that both the train service and the speed should be improved.

The construction of the first class compartments was very defective and called for improvement. It is difficult for the travellers to sit and sleep in the first class as well as in the third class sleeping births.

There was a stone-crushing contract at Jarba, the terminus of Balrampur area, where labourers are engaged in large numbers. Arrangements should be made to provide the facilities of quarters and wagons should be allotted to carry stone. A survey was undertaken for the Saidullah Nagar-Attraula line upto Jarba. Some work should be started to lay the line.

It is really surprising that train examiners are not given night duty allowance. They should be given this allowance particularly when the other staff are entitled to get this allowance.

Coming to catering in the Railways, I am sorry to say that catering arrangements have deteriorated and service is very poor. It causes much inconvenience and difficulties to the passengers. I would like to request the Railway Minister to look into this matter and some arrangements for catering should be made in the Lucknow-Delhi train *via* Kanpur.

Shri Bakliwal (Durg) : Bhilai has a big railway marshelling yard. The number of railway employees stationed there is about 10,000, but the facilities provided are inadequate. There are only 1,500 residential quarters for them. Previously there was only one primary school run by Railway administration. It has now been upgraded to Higher Secondary standard.

The wages paid to the labour by Railways are very low. If you cannot pay them more, you should provide them with the facilities like living accommodation, child education etc. Necessary attention should be paid to sanitation. There is no lady doctor in the hospital.

Casual labour has been devided into different categories and their rates of wages are also different. I feel that this discriminatory treatment should not be there. They do almost the same type of work. I want that the number of rest givers and leave reserves should be increased at Bhilai, Bhatapara and Anup Pur. It will add to the efficiency of Railways.

Another cause of frustration in railway employees is the system of stop-gap promotion or officiating charge. Under this the favouriates of high officials get some benefit and later claim seniority. It is another form of nepotism. This system should be regularised and clear rules may be laid down in this connection. A station has been set up at Charaunda near Bhilai marshelling yard. I suggest that all trains should stop there, so that people who work at Bhilai or Durg can avail of those trains. Chhattisgarh area is famous for producing paddy. It supplies paddy to many parts of the country I would request the hon. Railway Minister to pay attention to this area and provide more railway facilities there. A survey for a line from Durg to Jabalpore was undertaken long ago, That line should be taken up.

श्री दे० जी० नायक (पंचमहल) : रेलवे हमारा सब ►बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। यह बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इस की सेवाओं में कुछ त्रुटियां हैं जो दूर की जा सकती हैं और की जा रही हैं। मुझे खुशी है कि पश्चिमी रेलवे में नई लाइनों के लिये सर्वेक्षण कार्य प्रगति से चल रहा है। इसके लिये मैं रेलवे मंत्री श्री पाटिल का धन्यवाद करता हूं। और आशा करता हूं कि वह रेलवे के कार्य में जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने में सफल होंगे।

हमारे देश में बहुत से ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं कि जहां रेलवे सुविधा न होने के कारण प्रगति नही हो पा रही है। ऐसा ही एक क्षेत्र मध्य प्रदेश में बस्तर का क्षेत्र है। इसके विकास के लिये रायपुर से जगदलपुर तक एक लाइन निकाली जानी चाहिये। इसी प्रकार निमाड़ क्षेत्र के विकास के लिये इन्दौर से दोहद तक लाइन बनायी जाये। अंकलेश्वर में तेल के भंडार मिले हैं। अतः इस क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था ठीक प्रकार से चलाने के लिये और रेलवे सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिय।

मैंने देखा है कि अनुसूचित जातियों के मजदूरों को ठेकेदार लोग बहुत तंग करते हैं। रेलवे प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि ठेकेदार मजदूरों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करें। पश्चिमी रेलवे पर बम्बई और दिल्ली के बीच दो रेल गाड़ियां चलती हैं। एक है जनता एक्सप्रस और दूसरी है देहरादून एक्सप्रस। इन दोनों में बहुत अधिक भीड़ होती है। मेरा सुझाव है कि भोपाल से अहमदाबाद तक एक एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलायी जाये। रेलों में ईंधन पर खर्च कम किया जाना चाहिये। दोहद पर प्लेटफार्म बड़ा किया जाये।

रेलवे की विभागीय खान पान व्यवस्था बहुत अच्छी है। परन्तु सभी रेल गाड़ियों में एक ऐसे मूल्य पर वस्तुएं मिलनी चाहिये। सभी दर्जों के यात्रियों को एक ही प्रकार की सेवाये उपलब्ध होनी चाहियें।

Shri Veerappa (Bidar) : Sir, I come from a backward area of Mysore state. My main complaint is that the trains in that area run at very slow speed. I had refered to this last year also, but nothing has been done in this regard. No proper facilities are available to the travelling public in my area.

I request that a railway line from Zaheerabad to Sholapur be laid. Shri Jagjivan Ram the former Railway Minister had promised that it would be done but I am sorry to say that things have not moved in this direction.

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

[SHRIMATI RENU CHAKRVARTI *in the chair*]

I would also like that a broad gauge line be laid between Secunderabad and Bangalore. Recently there has been heavy loss to railway property on Southern Railway in Madras state. It is really deplorable. I would request the Railway Minister to see that the legitimate interests of people belonging to scheduled are casts safeguarded.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : दक्षिण भारत में भाषा के प्रश्न पर हुए दंगों में रेलवे की सम्पत्ति को बहुत हानि उठानी पड़ी है। इस पर मुझे खेद है। प्रजातन्त्र में ऐसा कार्य नहीं होना चाहिये। पम्बन के पुल को बड़ी कार्यकुशलता और शीघ्र ता से तैयार कर दिया गया है। इस विषय में रेलवे मंत्रालय का कार्य सराहनीय है। भद्रचालम-दान्तवाड़ा रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण हो रहा है। भद्राचलम एक बड़ा तीर्थ स्थान है यह कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिये। जैसा कि आंध्र प्रदेश के अन्य सदस्यों ने मांग की है। गोदावरी नदी पर पुल साथ सड़क का पुल भी बनाया जाये। यह

वहां के लोगों की बहुत आवश्यक मांग है। इस पर केवल 2.5 करोड़ रुपये अधिक खर्च होंगे । मेरी मांग है कि जी० टी० गाड़ी खम्मम के स्थान पर भी रुकनी चाहिए । अन्य गाड़ियां भी वहां अधिक समय के लिये रुकनी चाहियें । रेल गाड़ियों में चलने वाले बैरों को खाना मुफ्त दिया जाना चाहिए । स्त्री यात्रियों को और सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहियें । मैंने देखा है कि स्टेशनों पर प्रतीक्षा-गृह प्राय: गन्दे रहते हैं । इन की सफाई आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए । हमारे देश की गाड़ियां बहुत धीमी गति से चलती हैं । उन की गति तेज की जानी चाहिये । गुन्टूर जिले में पट्टाभिपुरम और मंगलगिरि पर गाड़ियां रुकनी चाहिये ।

Dr. Ram Subhag Singh : I have been listening to members, who spoke, very attentively. It is a matter of satisfaction that members have appreciated the role of railway as an integrating force. Members from all parts of the country have demanded for more railway facilities. India is a very big country. Its area is more than 12 lakhs sq. miles. Then some areas have special significance from the defence point of view.Members have given suggestions that railway net-work should be expanded keeping in view the industrial, agricultural, and mineral development of the country. The People of the country take railway as a national trust. They have faith in Railways. It is a source of confidence and consolation. That is why they want its expansion. Almost all the members have put forward the demands of their respective areas. Members from Madhya Pradesh have asked for more facilities in their state.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
(MR. SPEAKAR *in the Chair*)

At the time of formulation of Plan all factors will be considered. Shri Goni was saying about Kashmir. I can say that a line upto Kathua will be opened in October. We are considering about Jammu and Kashmir. We will take into account all the suggestions which have been made here.

When draft plan comes before Parliament it will be seen as to which works have been included in it. It will be considered in all its aspects. Parliament has got full authority. Its decisions will be carried out.

It has been said that light railways should be nationalised and line dismenteled during war should be laid again. These suggestions will be given due consideration. Every effort will be made to provide as many facilities to people as possible. Many hon. members have raised the question of co-operation of staff. The work done by railway staff is of paramount importance. A little negligence on their part can be the cause of great loss. The railways employees have been doing magnificant work during hard times. We will make every effort to remove their difficulties.

With regard to casual labour, I want to say that we have asked for the information about the wages paid to them. Our intention is that thay should not be in bad condition. We will write to Ministry of Labour about Minimum Wages Act. Shri Mathur has said that first scientific study should be made and thereafter new zones should be created. I can say that we have been doing this all along. Shri Khadilkar's suggestion regarding Satara will be considered. Shri Heda and Shri Trivedi have referred to alleged irregularities. We will look into them. For speeding up of trains we are trying to do the needful. We have already informed the House about the report on

[Dr. Ram Subhag Singh]

Dhanaishkoti accident enquiry. Shri Jyotishi has asked for the setting up of a complaints commission. We will try that there is no complaint. Shrimati Subhadra Joshi and Shrimati Kamala Chaudhary have said about the catering arrangements at Ghaziabad and Meerut. We will try to provide these facilities there.

It is baseless that there are no local persons on the N.E.F. Railway and especially belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There are two persons on N.E.F. Railway in the officers' grade and we will try to increase their number according to the Traffic need.

So far as promotions and recruitment is concerned, all the appointments in Class III services are made through the Railway Service Commission. The Commission has been informed about the policy of the Ministry. In future we shall see that more and more persons from villages are given jobs on railways.

Much has been said by the Hon. Members about the passenger amenities. We have decided henceforth to spend a sum of Rupees four crores every year on passenger amenities and we shall see that no amount is left unutilised. We shall pay special attention on the amenities for class III passengers.

So for as Siliguri line is concerned, the work is being done.

So far as regional languages are concerned, I agree that English is a developed language but if the Government want to serve in the real sense, they would have to look towards regional languages in the interest of masses and this is Ministry would do likewise.

We shall enquire about the school and police station in Kotah. We shall also see about West Dinajpur area.

Attention has been invited towards backward areas. Last year we prepared a booklet incorporating replies to all the suggestions given by Hon. Members in this House and that booklet was placed in the Parliament Library and this year we shall do accordingly.

So far as the speed and number of trains are concerned we shall try to increase them according to the availability of rakes.

Regarding time-table we shall look into this separately and is it not possible here to reply in detail about that.

So far as the decision of the Supreme Court and the suggestions of Hon. Members are concerned, we shall do whatever is possible.

I again thank the whole House that they created an atmosphere and sense of confidence which gave us encouragement.

Shri R. S. Pandey (Guna) : In the Fourth Five Year Plan a sum of Rs. 182 crores was reduced as only 40 crores rupees were accepted for the development of railways. By this petty sum we shall not be able to do the development work fully. I want to know the steps taken in this regard by the Railway Ministry.

Shri Balkrishna Wasnik (Gonda) . May I know whether in view of the decisions of the Supreme Court, the Government contemplate to change the policy adopted before that.

श्री नि० रं० लास्कर : मंत्री महोदय ने जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने की बात कही है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी अफ्रीका की रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों को यहां पुनः नियोजित किया जाए गा ।

Shri Vishram Prasad : According to the provisions of Constitution, there should be 18 percent reservation of seats. I want to know as to how long it will take to complete this quota regarding Classes I, II, III, & IV.

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) **:** I want to know the reason for the train not stopping at Gobindpur railway station on Allahabad Hathni line.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) **:** Shri Patil had said that construction of 500 kilometer new line is proposed. I want to know whether this includes Ajmer also.

Shri A. P. Sharma : The Hon Minister has said that canal labourer are not being paid less than rupees two. Do we take it that canal labourers would not be paid less than rupees two.

Shri Priya Gupta : Regarding the Remeshawram bridge, you have decided not to hold judicial enquiry. Have you enquired that the railway workers give a notice that it is dangerous the the train to go at that time ?

Dr. Ram Subhag Singh : I asked from the Northern railway and three other railways. They told that it was not less than rupees two. As I said earlier, we shall do whatever is possible in their interest in the light of the Wages Act and conditions prevailing at other places.

So far as Gobindpur railway station is concerned, I shall enquire about that.

So far as African labourers are concerned, we shall able to say something only after ascertaining everything about the Indian who come back here.

Regarding Dhanushkoti, certain officers, alongwith the Hon. Minister went there to enquire. They have completed their enquiry. There will be no use of judicial enquiry. In the report broadcast from there, there was no mention about the tidalwave.

We had not given any assurance about the construction of new line. Now the decision is to re-instate persons retrenched six years ago.

Regarding the Plan, the Hon. Minister would be able to tell.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

All the cut Motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of Ministry of Railways were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड . . .	1,18,64,000
2	विविध व्यय . . .	3,63,63,000
3	चालू तथा अन्य लाइनों के लिए भुगतान	34,13,000
4	कार्यवहन व्यय--प्रशासन . .	52,68,93,000
5	कार्यवहन व्यय--मरम्मत और संधारण .	167,73,90,000
6	कार्यवहन व्यय--संचालक कर्मचारी .	106,78,34,000
7	कार्यवहन व्यय--संचालन (ईंधन) . .	107,76,66,000
8	कार्यवहन व्यय--कर्मचारी और धन के अतिरिक्त संचालन .	32,00,17,000
9	कार्यवहन व्यय--विविध व्यय .	29,97,17,000
10	कार्यवहन व्यय--श्रम कल्याण . .	20,17,16,000
11	कार्यवहन व्यय--अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग	85,00,00,000
11-क	कार्यवहन व्यय--पेंशन निधि में विनियोग .	12,10,00,000
12	सामान्य राजस्व को भुगतान	115,90,17,000
13	चालू लाइन के काम (राजस्व)	11,00,00,000
14	नई लाइनों का निर्माण	65,82,32,000
15	चालू लाइन निर्माण-कार्य--पूंजी, अवक्षयण रक्षित निधि तथा विकास निधि .	5,19,01,64,000
16	पेंशन सम्बन्धी प्रभार--पेंशन निधि .	3,12,40,000
18	विकास निधि में विनियोग	29,23,67,000

चीन समर्थक साम्यवादियों की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर गृह-मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : HOME MINISTER'S STATEMENT ON ANTI-NATIONAL ACTIVITIES OF PRO-PEKING COMMUNISTS

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री प्र० के० देव के प्रस्ताव पर विचार करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे लिखा है कि वह निदेश 115(1) और (2) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। क्या वह वही बात है या कुछ और ?

श्री स० मो० बनर्जी : जी, यही बात है। इसके समर्थन में मैं बतलाता हूं कि . . .

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। उन्हें चाहिये था कि वे मेरे पास लिख कर भेजते कि इस में क्या गल्ती है। वक्तव्य क्या दिया गया है और ठीक बात क्या है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आप समझते हैं कि इस में कोई गलती नहीं है ? आप मुझे . . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी को निदेश 115 की ओर ध्यान देना चाहिये। इसमें लिखा है :

> "कि कोई सदस्य जो किसी मंत्री या अन्य सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य में किसी भूल या अशुद्धि की ओर ध्यान दिलाना चाहे, सभा में उस विषय का उल्लेख करने से पूर्व, अध्यक्ष को भूल या अशुद्धि का ब्यौरा लिखेगा और उस विषय को सभा में उठाने के लिए उस की अनुमति मांगेगा।"

उन्होंने इस सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं दी है। वह पहले मुझे विवरण लिख कर भेजें। अब वह कृपा कर के बैठ जायें।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : You have not given me any intimation. The point of order is in which connection and under which rule ?

Shri Madhu Limaye : It relates to the discussion on this motion and is sought to be raised under rules 186 and 337 I want to draw your attention to clause 2 of rule 186. It says :

"I shal not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations o defamatory statements".

Similarly rule 337 says :

"If in the opinion of the Speaker, any notice contains words, phrases or expressions which are argumentative, unparliamentary, ironical, irrelevant, verbose, or otherwise inappropriate, amend such notice before it is circulated."

Mr. Speaker, it may be surprising that my name has been included in the persons who have raised this motion and yet I am raising a point of order. In my notice for the motion I had stated :

"Arrest of Communist workers and the statement of the minister thereon".

In the notice before us certain accusations have been made like pro-Peking Communists, Anti-national activities and preparations for violance etc. I want that the notice may be amended and it should be moved in the form mentioned by me in my notice.

Mr. Speaker : Shri P. K. Deo was quoting the heading and title of the statement of the minister.

Shri Madhu Limaye : There should have been a quotation mark on the words quoted from the statement of the Minister.

Mr. Speaker: There is no need for that.

श्री प्र० के० देव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा पेकिंग समर्थक साम्यवादियों की राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों और तोड़ फोड़ तथा हिंसात्मक कार्यवाही के लिए उनकी तैयारियों के बारे में गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य पर, जो 18 फरवरी, 1965 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

इस देश के इतिहास में मीर जाफर और जयचन्द जैसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने न केवल देश के साथ द्रोह किया है बल्कि विदेशी शत्रुओं को इस देश में बुला कर राजद्रोही भी बने हैं ।

हमें आशा थी कि इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण वाला एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जायेगा और इस बात पर प्रकाश डाला जायेगा कि पेकिंग समर्थक साम्यवादियों के पास इतना धन कहां से आता है । हमारा विचार था कि इस में 'बैंक आफ चाइना' सम्बन्धी और उन परिस्थितियों सम्बन्धी, जिन में इण्डोनेशिया के वाणिज्य दूतावास को बन्द करना पड़ा, प्रकाश डाला जायेगा परन्तु इस के साथ ही मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने उन पथभ्रष्ट लोगों के इरादों को नंगा किया है जो अपने व्यक्तिगत हित के लिए तथा दल के हित के लिए देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान तक दे देना भी बुरा नहीं समझते ।

हम पिछले छः वर्षों से इस बात पर आग्रह करते रहे हैं कि इस दल पर प्रतिबन्ध लगाया जाये परन्तु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । मैंने 12 सितंबर, 1959 को पहले श्वेत पत्र पर चर्चा के समय सरकार को सावधान किया था कि वह आने वाली घटनाओं पर विचार करें तो श्री डांगे ने कहा था कि चीन इस देश पर कभी आक्रमण नहीं करेगा परन्तु समय ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन सच कहता है । यद्यपि कुछ साम्यवादी नेता शान्तिपूर्ण संसदीय समाजवाद की बात कहें परन्तु रनदीव, मुज़फ्फर अहमद, हरेकृष्ण कोन्नर तथा प्रमोद दास गुप्त जैसे बड़े नेता अपने असली रंग में प्रकट हो गये हैं उन्होंने तथाकथित शान्तिपूर्वक क्रान्ति को निरर्थक बताया है और चीनियों द्वारा 24 जून, 1958 के पेकिंग रिविय़ू संख्या 17 में बताये गये मार्ग का पक्ष किया है । मार्क्स तथा लेनिन के लेखों . . .

श्री दाजी : यह शैतान द्वारा धर्मशास्त्रों के उल्लेख के समान है । **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री कपूर सिंह : उन्होंने माननीय सदस्य को शैतान कहा है । मेरे विचार में यह असंसदीय है ।

अध्यक्ष महोदय : पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार कार्यवाही चल रही है मुझे उसे देख कर बहुत दुख होता है । तर्क का उत्तर तर्क से दिया जाना चाहिये ।

श्री प्र० के० देव : इन व्यक्तियों के लेख साम्यवादियों के लिए ऐसे हैं जैसे कि ईसाइयों के लिए बाइबिल । सितम्बर, 1959 में इन साम्यवादियों ने चीन के उद्देश्यों का समर्थन किया और

मैकमहोन लाइन को धोखा तथा भारत को आक्रमणकारी बताया । श्री रनदीव ने कहा कि साम्यवादियों के चीन के आक्रमण के विरुद्ध देश की रक्षा नहीं करनी चाहिये और अन्तर्राष्ट्रीयवाद नहीं छोड़ना चाहिये ।

चीनी आक्रमण तथा हमारे राज्यक्षेत्र के बारह हज़ार वर्ग मील पर बलपूर्वक कब्ज़े के समय 'न्यू एज' मासिक पत्र ने चीन के प्रधान मंत्री के पत्र के उद्धरण देकर इन कार्यवाहियों को उचित ठहराने का प्रयत्न किया था । हमने लगातार इस बात की मांग की कि साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि मंत्रिमंडल के अन्दर साम्यवादियों के पक्षपाती भरे पड़े थे और उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री चीन के प्रतिरक्षा मंत्री के साथ 'हिन्दी चीनी भाई भाई' के जाम चढ़ा रहे थे ।

अब सारी बात साफ तौर से मालूम हो गई है और उस समय जबकि साम्यवादी हमारी सीमा पर खड़े हैं उस समय सीमा पर तोड़फोड़ की कार्यवाहियां प्रारम्भ हो गई हैं। पहाड़ी लोगों की आर्थिक संकट और अज्ञानता का लाभ उठाकर साम्यवादी चीन का प्रचार कर रहे हैं । साम्यवादी दल के सम्मेलनों में माओ के चित्र लगाये गये हैं । उसका राष्ट्र विरोधी स्वरूप इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जब पश्चिमी बंगाल सभा में श्री बसवापुन्नैया ने यह घोषणा की कि चीन ने परमाणु बम का विस्फोट किया है तो वहां हर्ष व्यक्त किया गया और तालियां बजाई गईं। 1948 में स्तालिन के कहने पर तेलंगांना में विद्रोह आरम्भ किया गया परन्तु सरदार वल्लभभाई पटेल की दृढ़ता के कारण वह असफल रहा । अब भी उसी प्रकार काम कर रहे हैं । इसका कारण उत्तरी सीमा पर चीन जैसे देश का होना है । जो सरकार को क्रान्ति द्वारा उलटने के लिये पृष्ठभूमि और शक्तिशाली अड्डे के रूप में काम करेगा ।

देश के अन्तर मूल्य बृद्धि खाद्यान्नों की कमी, भ्रष्टाचार तथा सरकार द्वारा भ्रष्ट व्यक्तियों को संरक्षण और कांग्रेस के अन्दर एक शक्तिशाली साम्यवादी गुट होना हिंसात्मक संघर्ष के लिये बहुत उपयुक्त है । यह स्थिति सरकार की नई नीतियों के कारण पैदा हुई है । यदि सरकार ने ठीक समय पर साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगा दिया होता तो यह स्थिति पैदा न होती । आश्चर्य की बात है कि एक ऐसे दल को दल के रूप में काम करने दिया गया और निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति दी गई जो कि इस प्रकार के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती । यदि केरल में चुनाव के समय साम्यवादियों को गिरफ्तार न किया जाता तो वे वहां चुनाव में सबसे बड़ा दल नहीं बन सकते थे ।

यह तो सरकार की मुर्खता है । हम तो कभी भी यह नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति को भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किया जाय । मैं तो चाहता हूं कि श्री गोपालन तथा शेख अब्दुल्ला जैसे व्यक्तियों को भी अदालत में लाया जाना चाहिए। यदि इन साम्यवादी लोगों के साथ निपटने के लिये विधि में भी कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो कर लेना चाहिए । इस दिशा में सरकार को ठोस प्रस्थापनायें प्रस्तुत करनी चाहिएं ताकि हम सब उसका समर्थन कर सकें। जहां तक दक्षिणपंथी साम्यवादियों का सम्बन्ध हैं, ठीक है उनके मतभेद हो गये हैं । परन्तु वह चीन के विरुद्ध हमारा समर्थन केवल अपने वास्तविक इरादों को छिपाने के लिए कर रहे हैं । यदि आज रूस और चीन दोनों एक हो जायें तो वाम तथा दक्षिण पंथी पक्ष पुनः दोनों एक ही दल बनकर सामने आ जायेंगे । इन दलों में विशेष कोई अन्तर नहीं, अतः हमें सचेत ही रहना चाहिए । जो अन्तर 'पड़-ताल' और जांच में है वही दक्षिण पंथी और वामपंथी साम्यवादियों में है ।

[श्री ए० रू० देव]

हमारी सरकार को इनसे होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई व्यक्ति पदासीन दल में शामिल हो गये हैं । सम्यवाद से सहानुभूति रखने वाले लोगों पर कड़ी नजर से रखी जानी चाहिए । इसी में लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी । कई साम्यवादी तो धन भी लेते हैं ।

श्रीमती रणु चक्रवर्ती : इसके लिये सबूत पेश किया जाए ।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमती चक्रवर्ती तथा श्री मुकर्जी में कितना भी आर्कषण क्यों न हों मैं साम्यवादी नहीं हो सकता, परन्तु इतना मैं मानता हूं कि जो लोग यहां नहीं हैं और अपनी सफाई नहीं दे सकते, उन पर आरोप नहीं लगाने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा है कि कुछ लोग पैसे लेते हैं । उन्हींने किसी का नाम नहीं लिया ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–केन्द्रीय) : श्री देव ने इस संकल्प को प्रस्तुत करके राजनीति और इतिहास में अपना अज्ञान व्यक्त किया है । उनका हम पर यह आरोप है कि हम लोकतंत्र को तबाह करने वाले हैं । हमें इस प्रकार के आरोप के लिये अपनी घृणा ही प्रकट करनी होगी ।

गृह–कार्य मंत्री ने जो श्वेत पत्र प्रस्तुत किया है, उसे मैं काला पत्र कह सकता हूं । उससे केवल निराशा ही व्यक्त होती है । लगभग एक हजार वामपक्षियों को बिना मुकदमा चलाये जेल में डाल दिया गया है और इस पर हर्ष व्यक्त करके उसे न्यायोचित ठहराने का प्रयत्न किया गया है । मेरे मत में नजरबन्दी के पक्ष में जो भी तर्क प्रस्तुत किया गया है वे निराधार हैं । मंत्री महोदय ने उन सभी संसदीय आदर्शों को आघात पहुंचाया है । जो कि हमें परम्परा से प्राप्त हुआ है । यह भी अत्यन्त खेद की बात है कि सभा के मान्यता प्राप्त दल के लगभग सभी सदस्यों को अपनी सेवा से रोक दिया गया है । कितने दुःख की बात है कि उन पर देशद्रोही होने का अभियोग लगाया जा रहा है, परन्तु वे लोग अपनी सफाई देने के लिए इस सदन में नहीं आ सकते । राजनीतिक शत्रुता को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार की दस्तावेज तयार की जा रही है ।

जो वक्तव्य गृह कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि वामपंथी साम्यवादियों से बहुत अधिक खतरे का विचार झूठा है जिसका उद्देश्य केरल के निर्वाचकों को डराकर कांग्रेस के पक्ष में मत देने के लोकतंत्री-विलोधी लक्ष्य पर परदा डालना है । यह चाल शासक दल के अपने विरुद्ध आ पड़ी है और उसके लिए मंत्री महोदय बहाने बना रहे हैं । मुक़दमे के बिना नज़रबन्दों से अच्छा लोकतंत्रात्मक भावना का उल्लंघन किया गया है । आपात के नाम पर प्रशासन द्वारा राजनैतिक दबाब डाला गया । इस प्रशासन ने अपने आप को अयोग्य और भ्रष्ट सिद्ध किया है । बड़ी बड़ी विचित्र बातें देखने को मिल रही हैं । जब सर्व श्री राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण अथवा अन्य राजनैतिक व्यक्ति खुले तौर पर भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान को देने के सुझाव दे रहेहैं तो कुछ भी नहीं किया जाता । परन्तु जहां तक वाम पंथी साम्यवादियों का सम्बन्ध है उन्हें बिना मुकदमे के जेल में डालने के लिये बिना कोई और कार्यवाही नहीं की गई है ।

वामपंथी साम्यवादियों के विरुद्ध बैंक आफ चाईना तथा अन्य सूत्रों से धन लेने के आरोप लगाये जाते हैं । परन्तु सरकार यह बताने में असफल रही है कि कौन यह धन प्राप्त करता रहा है ।

इन आरोपों के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं मिला जो केवल इस दल को बदनाम करने के लिये ही लगाये गये हैं । इसके विपरीत कांग्रेस के समर्थकों द्वारा बैंक आफ चाईना से अधिक धन निकाला गया । उस विषय पर पश्चिमी बंगाल कौंसिल में सदस्य द्वारा सूचना सभा पटल पर रखी गई थी । इ स पत्र में वामपंथी साम्यवादियों की भारत की आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिया गया है । इसमें तो केवल कुछ बहुत ही अस्पष्ट आरोप लगाये गये हैं । जैसा आरोप लगाया गया है यदि वह चीनी आक्रमण के समय में ही आतंरिक विद्रोह की योजना बना रहे थे तो उन पर सीधे ही मुकदमा चलाया जाये । यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो वह इतने व्यक्तियों पर झूठे आरोप लगा कर बदनाम न करे तथा बिना मुकदमा चालाये उन्हें बन्दी न रखे ।

जो विवरण सभा के समक्ष रखा गया है वह एक भद्दा पत्र है जिससे लोकतंत्र की बातों का उपहास होता है । सरकार ने भारतीय जनता के एक पूरे वर्ग को बन्दी बना रखा है और उन पर राष्ट्रद्रोही होने का खोखला आरोप लगाया गया है । सरकार को शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिये तथा बन्दियों को रिहा करके वामपंथी साम्यवादियों को केरल में सरकार बनाने देना चाहिए यदि वह ऐसा कर सकें । और इस तरह देश का राजनीतिक वातावरण स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

श्री शिवचरन शुक्ल (महासमंद) : जो दस्तावेज सभा पटल पर रखी गयी है उसमें दिये गए गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य द्वारा बहुत सी बात प्रकाश में आई हैं । उसका गम्भीरता से अध्ययन किया जाना बड़ा जरूरी है। आज भारत और चीन में युद्ध चल रहा है और सरकार ने देश विद्रोहियों के विरुद्ध जितनी तेजी से कार्यवाही की है वह ठीक ही है। जिन लोगों को जेल में डाला गया है वह चीन के एजेन्ट हैं। इसके लिये दस्तावेज़ में काफी सबूत मौजूद हैं। सरकार ने काफी सबर से काम लिया है । बीच में इस प्रकार के गद्दारों को जेल से मुक्त भी कर दिया गया था परन्तु बाद में फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । चाहिये तो यही था कि जब तक सीमाओं पर चीन के आक्रमण की स्थिति समाप्त न हो जाती तब तक उन्हें जेल में ही रखा जाना चाहिये था परन्तु सरकार ने अपनी लोकतंत्रीय मनोवृत्ति के कारण उनका काफी लिहाज़ करती रही है । यह लोग तो तब भी अपनी गलत कार्यवाहियां करते रहे हैं जबकि उनकी सारी कार्यवाहियां सरकार के नोटिस में आ गई थीं । यह ठीक है कि अब जो इनकी गिरफ्तारियां हुई तो इन्होंने केरल में इस का लाभ उठाया। और इन लोगों के कुछ प्रतिनिधि चुनाव में चुन लिये गये । यह लोग दक्षिणपंथी साम्यवादियों के विरुद्ध भी काफी प्रचार करते रहे हैं। यद्यपि सरकार को इन के विरुद्ध कार्यवाही बहुत पहले कर लेनी चाहिये थी परन्तु फिर भी जिस तेजी से अब सरकार ने कार्यवाही की है उस के लिये वह बधाई की पात्र है । इससे यह पता चलता है कि देश में हो रही हलचलों के प्रति भी गृह-कार्य मंत्रालय पूर्ण रूप से सचेत है । मेरा निवेदन यह है कि सरकार को संसद् के विशेष विधान द्वारा एक न्यायाधिकरण की स्थापना करनी चाहिये । जो कि इन लोगों के मुकदमों की छानबीन करे । हमें इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाने में लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिये । जो आरोप इन गद्दारों के विरुद्ध लगाये गये हैं वह बड़ी सरलता से सिद्ध किये जा सकते हैं । हम यह भी आशा कर सकते हैं कि सरकार दक्षिण पंथी साम्यवादियों से भी सचेत रहेगी । और किसी भी प्रकार उन के झांसे में नहीं आयेगी ।

इह वक्तव्य में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है जिससे कम्युनिस्टों के हिंसा में विश्वास का पता चलता है। तामिलनाड कम्युनिस्ट पार्टी के पत्र के अनुसार साम्यवादियों द्वारा उसी प्रकार की खूनी क्रान्ति का लाना है जो कास्ट्रो ने क्यूबा में लाई थी । संसद् द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाना चाहिये था जिस से देश विद्रोहियों पर मुकदमा चलाए जाने की उसी प्रकार से व्यवस्था की जाय जैसी कि युद्ध-

[श्री शिवचरण शुक्ल]

अपराधी नाज़ियों के बारे में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई थी । केरल के निर्वाचित नजरबन्दों की रिहाई की मांग हास्यजनक है । ऐसा विशेषत: उस वक्तव्य के अनुसार है जिस में श्री इ० एम० एस० नम्बूद्रीपाद ने कहा है कि यदि वाम पक्षी कम्युनिस्ट एक बार सत्तारूढ़ हो गए तो वे अपने सत्तारूढ़ होने को केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच सघर्ष को बढ़ाने और सरकार के स्तर पर वर्ग-संग्राम को उन्नत करने के लिये प्रयोग में लायेंगे । इस विचार से केरल में उनके द्वारा सरकार बनाने के प्रस्ताव को रद्द किया जाना चाहिये ।

कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने दौलत एकत्र कर ली है तथा संदिग्ध स्थानों से उन्हों ने परिसम्पत खरीदे हैं । इस पार्टी के समस्त विख्यात सदस्यों ने "बैंक आफ चाइना" में अपने लेखे रखे हैं तथा उन्ह उस बैंक द्वारा बड़े पमाने पर अधिक धन निकालने की अनुमति दी गई है । सरकार इस बारे में अवश्य ही जांच करे ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): For the last seventeen years the Government has been taking half-hearted decisions in all those matters which either effected the whole country or the whole of world. These half-hearted decisions are reflected in Kashmir, Nagaland, Goa. and In the case of language problem also, the Government on the one hand wants to fulfil the promises contained in the constitution, on the other hand it wants to please Shri Kamaraj and his followers. The Government has arrested 600 communists but their leaders like Shri Namboodripad and Shri Jyoti Basu are still at large. This is also a result of the half-hearted decisions I want to ask the Government that when it considers that their activities are anti-national, why doesn't it ban the Communist Party. Whenever half-hearted decisions are taken, both the country and the Government have to suffer as a result thereof.

I do not want to go into the history of the Communist Party. In 1949 when Gandhiji, after creating the desired atmosphere gave the slogan "do or die" this in the party which said that when Gandhiji had not prepared the country, then why he had pushed the public into the fire of revolution. They had not spared even Subhash Chandra Bose. They had called him a quisling. During the partition of the country, half of the Communists were instigating the Muslim League to press their demand for the partition of the country. On the Kashmir question also the party was saying that Kashmir is an integral part of India and there cannot be any demand for a plebiscite. But their attitude has changed ever since China has entered into an agreement with Pakistan. The Government has started paying special attention after the Tenali session of the Communist Party where they displayed the photographs of Mao-Tse-Tung and Chau-En-Lai.

When Shri Nanda placed the White-Paper in the House, I had asked him what was the basis on which he divided the leftist and rightist groups of the Communist party. To-day there are pro-Peking and pro-Moscow groups but tomorrow they may again merge into one group; then how will Shri Nanda separate the leftist and the rightist group? Doesn't Shri Nanda know that in 1933-34 one wing of the Communist Party wanted to take part in the movement started by the Popular Front while the other wing was opposed to it? During the partition of the country one wing of the Communist Party was working with Muslim League while the other wing was working separately.

When man-slaughter was going on in Telangana, Shri Rajeshwar Rao who now belongs to the rightist group of the Communist party, was at that time the general secretary of the Communist party. This Rajeshwar Rao was responsible for the episode in Telangana. The Government should take lessons from the elections in Kerala.

If there is slight untruth in my statement then let the rightist group declare that they will not support the said leftist group in their anti-national activities. Then we can be sure that there are two groups.

There is a history behind the attack launched on our borders. When a scheme for spreading Communism in the world was being prepared, in Moscow, a slogan was being raised "Road to Paris through Shanghai and Calcutta". The Communists wanted to conquor Calcutta after Shanghai. This is the reason why Communist party concentrated its activities in the Eastern India. The communists had stated in a circular, which has been referred to in the white paper, that they will not repeat the mistake Committed by them in October, 1962. The Government had established a Communication line with Peking through Nagaland and Burma. They had received some weapons through this line and were prepared for an armed revolt. Why doesn't Shri Nanda tell all these things to the Country.

What is the reason that the price of our currency has doubled in Hong Kong; what is the reason that the demand for our currency has gone up from 3 crores to 12 crores within a year? It is clear that China is purchasing our currency and through certain Embassies in our country, is giving this currency to the Communists. Has not Shri Nanda been informed by his vigilance department that this money is coming into the country by diplomatic bags? I do not want to name the two embassies, but the Government should break diplomatic relations with those countries.

The Government should publish the full report about seven and a half crores of rupees in the Bank of China. Shri Hiren Mukherjee told that an account of Sooraj Mal Nagarmal has been found in the China Bank. The Government should give the same punishment to a person whose money is lying used in anti-national activities as to a traitor.

If you want to preserve the independence of India achieved after a long struggle of about 900 years and after a sacrifice by inumerable persons, then not only should the Communist party be banned but the Congress party should look for Communists within its own party.

I want to say a few words about the Challenge thrown by Shri Hiren Mukherjee that their principles will develop and remain alive like the rising sun. I want to inform him that so far it was possible for those engaged in anti-national activities to keep alive because of the weakness of the present Government; but now the people of the country have awakened and they will finish off the Communist Party.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Government under which all the wrong policies in connection with China were formulated is accusing another party that it has got relations with China and its activities are against the interest of the country. The real culprit is the Home Minister who is sitting before us and not Smt. Renu Chakravartty or Shri Gopalan.

[Shri Madhu Limaye]

In 1954 the Government entered into a Panchsheel agreement with the China which had swallowed Tibet and come to the borders of India. Did Shri Nanda criticize this policy at that time and resigned. And just after the 1954 agreement was concluded, the Chinese started encroaching in Ladakh. The Government kept it a secret from the public. Did Shri Nanda resign on this issue. When China lanunched an all-out attack in 1962, the Indian Government declared that it will not enter into any agreement or talks with China till it has clear the territory occupied by it.

But after we were badly defeated in the battle field, we at once started talks on the Colombo proposals. I want to know what is the difference between the policy followed by the leftist Communists and that followed by the Congress party. All the charges levelled against the leftist communists are contained in this white-paper. There are only few paragraphs about their activities. The rest of the charges are very vague. I have my differences with the leftist communists. If some of them are looking towards Peking or Moscow for inspiration, I am prepared to fight with them. We must pay our attention to the labourers, farmers or the middle class of our country and only then can we establish socialism in our country.

The Govt. has declared the state of emergency, which according to the Constitution can only be declared when there is danger of war or internal revolt. Now neither a war is going on nor there is any fear of internal revolt. I want to know why the Government is keeping this emergency. The Government should either release the leftist Communists detained under D.I.R. or should allow those Communists to vote who have been elected members of Vidhan Sabha, so that a Govt. may be formed there. The Congress is acting in an irresponsible way by imposing the President's rule. Now the declaration of emergency should end. To-day in the interest of nation those articles of the constitution are being used which should only be used in case of war or internal revolt. The Governments has alleged in this booklet of forty-five pages that the Communists' way of thinking is anti-national. There may be some people who think that Dictatorship is better than Democracy, but we cannot arrest them till they try to remove this Government by violent means. I would appeal to the Government that it should stop concentrating all the powers in its own hands; it should either file cases against all the Communist detenus in law courts or allow those twenty nine communists detained in the Kerala jails to vote in the Vidhan Sabha. I can very much aggrieved when one party demands that the other party should be banned. Recently rightists Communists demanded that R.S.S. should be banned. In this way neither the Jansangh nor the Communists can come into power, and the anti-public Government of Shree Nanda would continue.

श्री प० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मेरा इस सरकार के विरुद्ध यह आरोप है कि इसने वाम-पन्थी कम्युनिस्टों को पकड़ने में बहुत विलम्ब कर दिया है, क्योंकि वह देश की सुरक्षा को संकट में डाल रहे हैं। कुछ दिन हुए जब इस सभा में श्री सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाने का प्रश्न उठा तो श्री मुकर्जी ने इसका जोरदार समर्थन किया परन्तु मैं अपने साम्यवादी मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब नेता जी अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम लड़ रहे थे तो कम्युनिस्टों ने उन्हें जापान के टोजों का एजेन्ट कहा था। हमारे संविधान ने हमें वाकस्वातन्त्र्य मिला हुआ है। शर्त केवल यह है

कि इसका राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों के लिए प्रयोग न किया जाए । कम्युनिस्टों ने कोई भी ऐसा राष्ट्र नेता नहीं छोड़ा जिसका उन्होंने आलोचना न की हो । जैसे राष्ट्रपिता बापू जी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस । यह लोग जिनका देश में बहुत आदर था और जो स्वतन्त्रता युद्ध में सबसे आगे थे उनको कम्युनिस्टों ने अंग्रेज़ों का एजेन्ट कहा ।

केरल में निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रोफेसर मुकर्जी के भाषण पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ? कम्युनिस्टों का केरल में निर्वाचन घोषणा पत्र क्या था । क्या यह साम्यवादियों की नजरबन्दी के सम्बन्ध में था ? जी नहीं, बिलकुल नहीं । उन्होंने लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाया है । उन्होंने खाद्य संकट के सम्बन्ध में लोगों को भड़का कर कुछ सीटें जीत लीं । और जब उन्हें जनता का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो वह किस प्रकार मंत्रिमंडल बनायेंगे ।

जो विवरण श्री नन्दा ने सभा-पटल पर रखा है उसमें से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । तिनाली में एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें उस माओत्से तुंग का चित्र रखा गया था जिसने हमारे देश पर आक्रमण किया था और उसे कुचलना चाहा था । यह लोग अपने को देशभक्त कहते हैं जो वास्तव में देशद्रोही हैं ।

जब देश पर आक्रमण हो रहा था तब कम्युनिष्ट पार्टी ने इस प्रकार का एक शब्द नहीं कहा कि चीन ने आक्रमण किया है । वह अब भी यही कहते हैं चीन ने आक्रमण नहीं किया ।

मैं श्री मुकर्जी से पूछना चाहता हूं कि उनका वामपंथी कम्युनिस्टों से मतभेद का कारण क्या है ? किस कारण यह दल दो भागों में विभक्त हो गया ? उनके अपने ही साथियों ने श्री डांगे की उस पत्र के लिये निन्दा की है जो उन्होंने 20 वर्ष पहले लिखा था और अंग्रेज़ों का एजेन्ट बनना स्वीकार किया था । यही कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है । इस दल का मुस्लिम लीग से मेलजोल बढ़ रहा है, क्योंकि पिंडी और पीकिंग में भी मेलजोल बढ़ रहा है । कम्युनिस्ट इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं मानते । परन्तु वह प्रेरणा किसी और देश से प्राप्त करते हैं । हमें इन लोगों के सम्बन्ध में बहुत सावधान रहना चहिये। उन लोगों की कार्यवाहियां बहुत सन्देहजनक है । सिवाये केरल के उनको देश के किसी भी भाग में समर्थन नहीं प्राप्त हो सकता । अतः मैं गृह-मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन लोगों से सख्ती से पेश आयें ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सभा से निवेदन है कि इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय हम सब के लिये देश की सुरक्षा तथा राज्य क्षेत्र की प्रभुसत्ता बहुत महत्व की बात है । मुझे श्री गोपालन के साथ इस सभा में कई साल तक कार्य करने का सौभाग्य मिला है । मैं समझ नहीं पाता कि उन पर देश द्रोह का आरोप कैसे लगाया जा सकता है ।

श्री नन्दा द्वारा प्रस्तुत किये गये पत्र से मालूम होता है कि 30 दिसम्बर 1964 को लगभग 900 साम्यवादी दल के सदस्यों को भारत प्रति रक्षा नियमों के नियम 30 के

[श्री नि० च० चटर्जी]

अन्तर्गत बन्दी बना लिया गया है । इस के बारे में संसद को पहले सूचित किया जाना चाहिये था। आप को इस बारे में पूर्वसूचना मिलनी चाहिये थी । इन बन्दी बनाये गये लोगों में संसद सदस्य भी थे । इस 45 पृष्ठ के विवरण में साम्यवादी दल के अपने गुटों में विचारधारा सम्बन्धी मतभेदों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । हमारा उस से कोई सम्बन्ध नहीं । केरल के लोगों ने गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध अपना निर्णय दे दिया है ।

साम्यवादी दल के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं उन में कोई तथ्य जान नहीं पड़ता है । उन पर यह आरोप है कि वे तोड़ फोड़ की कार्यवाही की तैयारी कर रहे थे परन्तु इस के लिये कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्रीमान आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने भारत रक्षा नियम 30 को असंवैधानिक करार दिया है तो सरकार उस का प्रयोग क्यों कर रही है ? इसी सम्बन्ध म सरकार ने संविधान का अट्ठारहवां संशोधन प्रस्तुत किया था परन्तु हमने उस का कड़ा विरोध किया और प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने वह संशोधन वापिस ले लिया । आज सरकार संविधान के खिलाफ़ कार्यवाही कर रही है । में ने श्री नन्दा को इस बारे में लिखा भी था कि इस विषय पर विचार करने के लिये एक बोर्ड की स्थापना की जाये। उस बोर्ड में भारत के मुख्य न्यायाधीष श्री गजेन्द्रगदकर तथा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री एस० आर० दास और श्री मेहर चन्द महाजन हों । इस सुझाव पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया है ।

यदि सरकार को विश्वास है कि श्री गोपालन और अन्य बन्दी बनाये गये लोगों ने देशद्रोह का कार्य किया है तो उन पर न्यायालय में अभियोग चलाया जाना चाहिये और उन को दण्ड मिलना चाहिये ।

मैं गृहकार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह न्याय संगत बात करें और वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान दें । और इन लोगों को बिना किसी कारण के बन्दी बना कर न रखा जाये ।

श्री कप्पन (मवातुपुजा) : श्री ही० ना० मुकर्जी ने गृह कार्य मंत्री के इस आरोप का कि वाममार्गी साम्यवादी चीन समर्थक हैं का कड़ा विरोध किया है । परन्तु कुछ समय पहले श्री मुकर्जी ने स्वयं यह आरोप लगाया था । यह बात वह भूल गये मैं हैं। इस बात का दावा किया गया है कि केरल में लोगों ने वाममार्गी साम्यवादियों के समर्थन में निर्णय दिया है । परन्तु वह भूल जाते हैं कि यह सफलता मुस्लिम लीग जैसी साम्प्रदायिक संस्था के साथ गठजोड़ करने से मिली है । यदि यह गठजोड़ नहीं होता तो मालाबार में उन को एक स्थान भी प्राप्त नहीं होता । वास्तव में सच्ची बात कड़वी लगती है । केरल के साम्यवादी नेता श्री एम० एन० गोविन्दन नायर तथा श्री मुकर्जी ने स्वयं वामपंथियों पर चीन के समर्थक होने का आरोप लगाया था । तो इस में कोई बड़ी बात नहीं कि देश के प्रति विद्रोह की भावना फैलाने वालों को बन्दी बना लिया जाये और उन की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जायें । अतः मेरे विचार में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ठीक है ।

श्री चटर्जी तो उन के पक्ष की बात करेंगे ही । उन के चुनाव में साम्यवादियों ने बहुत सहायता की थी । यदि वामपंथियों साम्यवादियों को केरल में कुछ स्थान प्राप्त हुए हैं तो इस का कारण उन की लोकप्रियता नहीं बल्कि दूसरे दलों में फूट है । प्रजातंत्रीय दलों के वोट वहां बट गये हैं। अतः साम्यवादियों को लाभ हो गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्री नन्दा एक महान व्यक्ति हैं। उन्होंने यह विवरण सभा पटल पर रखा है । इस में वामपंथी साम्यवादियों पर आरोप लगाया गया है कि वे चीन समर्थक हैं । 1959 में सरकार ने तिब्बत के बारे में अपना मत बदल लिया था । यह उचित नहीं था उन दिनों हम हिन्दी-चीनी भाई भाई के भुलावे में फंसे हुए थे, और हमारी डरपोक सरकार को वास्तविक स्थिति मालूम ही नहीं थी।

कांग्रेस पार्टी और साम्यवादी दल में उस समय बहुत घनिष्टता का सम्बन्ध था। आज उसी दल के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । आज तक "बैंक आफ़ चाइना' के कार्यों पर जांच की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है । इस का क्या कारण है? मेरे सहयोगी श्री द्विवेदी ने इस बारे में प्रश्न भी किये थे । वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी ने इसे गोपनीय बताया है । मैं समझता हूं कि इस में कांग्रेस पार्टी तथा साम्यवादी दल दोनों दोषी हैं। मेरी पार्टी 1954 से इस बात को चेताबनी दे रही थी कि हमें चीन पर विश्वास नहीं करना चाहिये । आज आप वाम मार्गियों पर चीन समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं। इस बात को श्री डांगे ने भी माना है। मैं तो इस बारे में सरकार की लापरवाही को ज़िम्मेदार कहूंगा। यह हमारी डरपोक सरकार की नीतियों का परिणाम ही था कि हमें 1962 में हार खानी पड़ी । जब भी हम किसी जानकारी के लिये कहते हैं तो यह कहा जाता है कि लोक हित में यह जानकारी नहीं दी जा सकती । इस के द्वारा सभी त्रुटियों को छुपाया जाता है । यही कारण है कि देश को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

सरकार ने वामपंथी साम्यवादियों पर आरोप लगाया है कि वे हिंसा तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही की तैयारी कर रहे थे । मेरा यह कहना है कि ऐसा करना उन की विचार धारा का अंग है । मुझे पता चला है कि सरकार के पास बहुत सी ऐसी सामग्री है कि जिस के आधार पर इन लोगों पर अभियोग चलाया जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन पर मुकदमा चलाया जाये । अन्यथा सरकार को डरपोक कहा जायगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : यह बात प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों और संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है या नहीं कि इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य श्री गोपालन को बन्दी बनाया गया है। मेरा यह छोटा सा प्रश्न आप से है । वह प्रथम लोक सभा के समय से सदस्य चले आ रहे हैं और अपने दल के नेता भी हैं। यह किस प्रकार का प्रजातन्त्र है? यहां पर वाम मार्गियों और सरकार की बात नहीं है । यहां पर तो प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों के समाप्त किये जाने का प्रश्न है । श्री चटर्जी जैसे विख्यात विविध वेत्ता ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि यह संविधान के विरुद्ध है । लोगों का विचार था कि चुनाव के पश्चात् श्री नाम्बूदरीपाद को सरकार बनाने दी जायगी परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अड़चनें उत्पन्न कर दी हैं। सरकार ने सदस्यों को बन्दी बना दिया है। क्या यह न्याय है ? क्या यह प्रजातंत्र है?

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

इस विवरण में सभी निराधार बातें कही गई हैं यह नितान्त झूठ है कि सामसार्गी चीन समर्थक हैं । सरकार को न्यायालय में जाना चाहिये और इन लोगों पर अभियोग चलाये जाने चाहियें । इस से तो यह जान पड़ता है कि इस देश में न्याय नहीं होता है । मैं फिर सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि इस के पास इस आशय का प्रमाण है कि इन लोगों ने देशद्रोह की कार्यवाही की है तो उन पर मुकदमा चलाये और दन्ड दिलाये । नहीं तो सरकार पर निर्दोष लोगों को उत्पीड़न करने का आरोप लगेगा । मैं प्रो० मुकर्जी की बात को दोहराता हूं कि कांग्रेस पार्टी वालों ने बैंक आफ़ चाईना से धन प्राप्त किया था । क्या सरकार इस बात का खंडन कर सकती है ?

केरल में लोगों को पथभ्रष्ट करने की कोशिश की गई । वहां झूठा प्रचार किया गया, परन्तु फिर भी लोगों ने बड़ी संख्या में साम्यवादियों को चुना । श्री नाम्बूदरीपाद ने श्री नन्दा के वक्तव्य का खण्डन किया है । मेरा अनुरोध है कि सभी बन्दियों को रिहा किया जाये और श्री नाम्बूदरीपाद को सरकार बनाने दी जाय । लोगों द्वारा चुने सदस्यों को अवसर मिलना चाहिये । सरकार को ऐसे हथकंडे नहीं अपनाने चाहियें कि जो शोभा न दें । यदि श्री नन्दा चाहें तो श्री गोपालन के मुकाबले में केरल से चुनाव में खड़े हो कर देख लें तो पता चल जायगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है ।

Shri R. S. Pandey (Guna): Sir, the country has been informed through this House by Shri Nanda about the anti-national activities of such traitors. The pages of Communist history are red. Their deeds may be summed up in the characters of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. On the one hand Mr. Khrushchev had promised all help in the event of an attack on Kashmir and India whereas shortly afterwards his comrade Mao-Tse-Tung attacked the Himalayas-Looking back, we are reminded of the warnings given by Mr. Churchill and Gandhiji about their strategy, underground activities and hoodwinking the masses. Their history has proved that they are anti-national elements ready to mortgage the existence of the country itself for the achievement of their own ends. Their principle is that they have no principle. They follow the dictates of Peking and their minds are receptive to only red thoughts. That they are extreme fascists and reactionaries who have left the path of international proletarianism and are working against the interests of resurgent people and the labour class —these are the views not of anyone else, not of the Congress Party, but of the Soviet controlled Communist Party led by Prof. Hiren Mukerjee. They have claimed that they have faith in peaceful means and democratic way of life but in 1951, in a pamphlet secretly distributed by them they had openly advocated the strategy of guirella warfare and sabotage to bring about Communist revolution of the type of China. They have full faith in armed revolution, they will stab in the back and go ahead to have collusion with China and kill democracy. They are traitors and therefore should be dealt with an iron hand. In my opinion they are receiving a fairly good treatment, though they do not deserve it, because of democracy here, whereas in a country like Russia, their very existence would not be known. As to China, 3532 persons stand in a park and hold a session of the so-called Parliament for 2 days This is their democracy.

Shri Nanda should face the situation courageously and have no fears as the public and Congress is with him. You are the custodians of democracy and in order to save it, you should also join us in condemning these traitors.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas): Mr. Speaker, Sir, I, on behalf of my party congratulate the Government for the action taken against Left Communists but regret that it was belated action. The pamphlet about the activities of Left Communists is very informative, though it contains information which has repeatedly been given in newspapers and over the radio.

At the time of Chinese aggression, certain Communists were arrested, I wish they were not arrested and then only we could know who is a patriot and who a traitor. The public would have dealt with them in a very befitting manner had they not been arrested then. In a way they are being protected and encouraged by Government.

We should wind up China Embassy here since all anti-national plots are hatched here in the Chinese and Pakistan Embassies. The Communist Party should be declared illegal and disbanded. Those who have been arrested under DIR should be tried in courts. Like this you are making them heroes, bringing them into lime light. They should therefore be tried as traitors to our mother land.

This pamphlet does not contain all the details. Let the full facts be known. All the names connected with the Bank of China should be disclosed. Those who were arrested before Kerala Elections and have not been released so far, should be penalised in the strictest manner possible.

Shri V. K. Krishnamenon, who was the former Defence Minister was guilty of deceiving this House and the nation. He was responsible for the death of thousands of our Jawans, but he was let off only by being sacked. He should also be tried likewise. Because in Democracy the guilty must be brought to books. If the Right Communists are in real sympathy with the labour, why do they not work with them. They only want sabotage, disturbance and chaos. They know that as long as the labour is hungry, they have influence over them.

There are other parties also, like the Swatantra Party who are working on anti-national lines. Swatantra Party wants Kashmir to be a separate State. They had tried for the release of Sheikh Abdullah. They want retention of English. Did they not support what Jaiprakash Narayan said recently? There might be good persons also among them, but who ever speaks of Kashmir's separation must be banned.

I have to tell Shri Nanda that certain patriots have also been arrested as in Maharashtra. They should be tried and their offence known. The policy of keeping people in prison without trial for an indefinite period is wrong. Misuse of power should be stopped.

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): The party about which the House is discussing at this moment have charges of anti-national activities. The point is whether these vague charges are enough for so many people to be arrested without trial. The question is who is a traitor—he who differs in opinion or he who sells rice secretly to China, I appeal to Government to frame charges against detenus and try them in a court.

[Shri Sarjoo Pandey]

Even in Communist Party people have more sacrifices to their credit than many of those who call them traitors. The denial of proper opportunity to defend the charges levelled in a court means negation of democracy and therefore Shri Nanda should make sure that this opportunity is afforded to them at the earliest. I submit that to pass a comment on others, it is necessary for the Government to be above-board. That party, all of whose members are corrupt, get money from others can never create confidence among the masses. Mere abuses cannot crush the Communist Party. Others who claim to be wedded to Socialism are using it as a cloak to deceive the masses whereas the CPI is the only real and true harbinger of Socialism. We allege that wrong ideas have been allowed to gain currency. I submit that the Government by arresting the Communist Party people are guilty of stifling the voice of those who speak about the corruption, who voice the grievances of the poor. These acts will certain cut democracy short. Certain persons like Shri (Prakash Vir) Shastri, propagate castism in the name of patriotism, persons like he have maligned the name of Hindi in the country. They are the people who spread communalism. The Government should, instead, arrest these persons who are reactionaries.

अध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र---------- (अन्तर्बाधाएं) क्या वह यहां नहीं ।

माननीय मंत्री जी अपना भाषण आरम्भ करें ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : अध्यक्ष महोदय । मैं व्यक्तिगत बात से आरम्भ करता ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह व्यक्तिगत है तो हम इसे कल सुनेंगे । वह कल (अपना भाषण) जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा, शुक्रवार, 12 मार्च, 1965/ फाल्गुन 21, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिय स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 12, 1965/Phalguna 21, 1886 (Saka).

———

GMGIPNND—LS III—392 (Ai) LS—6-7-65—600